G20 भारत 2023 INDIA

सत्यमेव जयते
नीति आयोग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

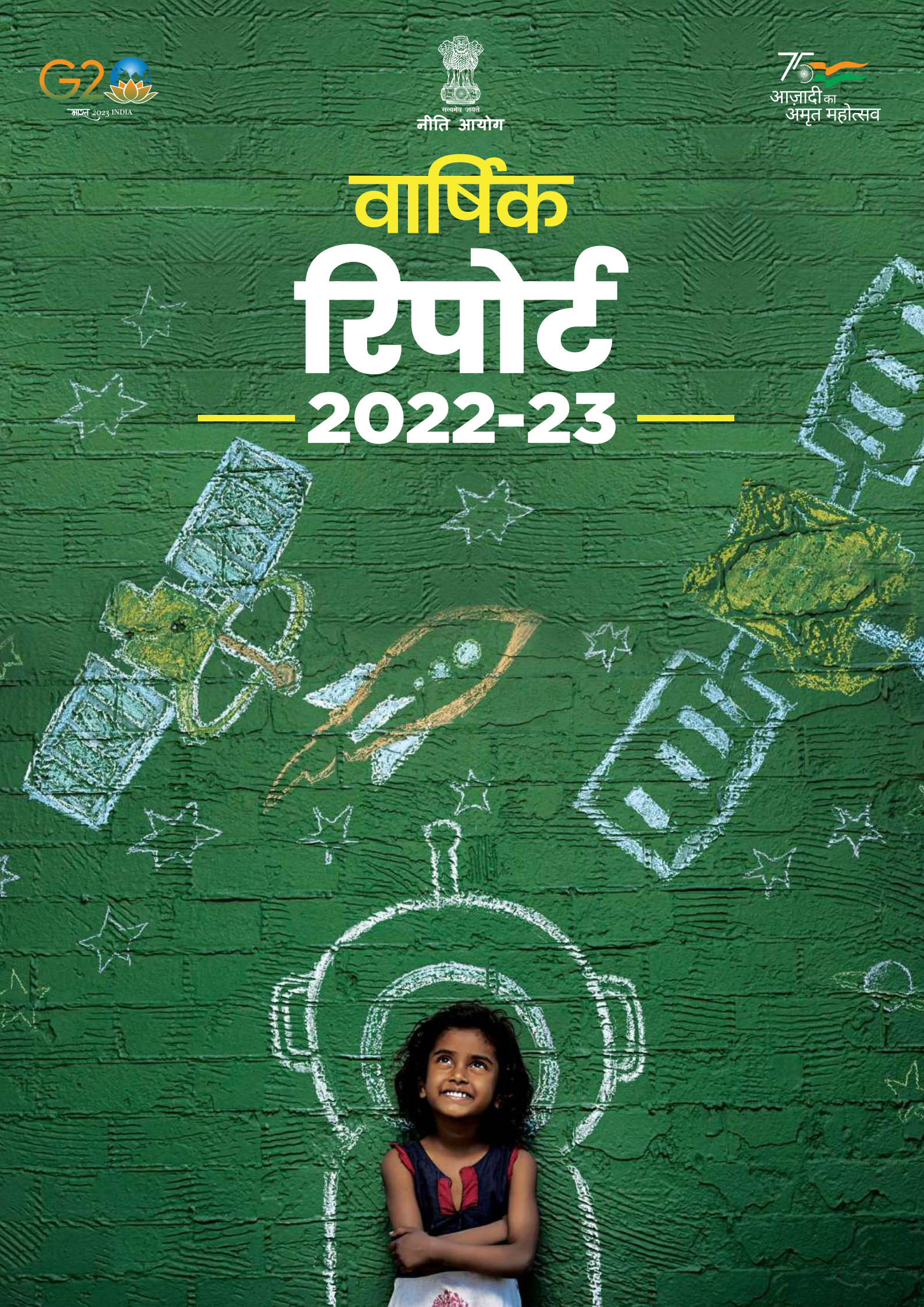

वार्षिक रिपोर्ट

2022–23

विषय सूची

संक्षेपाक्षरों की सूची *vii*

खंड-I
नीति आयोग: ढांचा गठन 3

- प्रस्तावना 3
- उद्देश्य और विशेषताएं 6
- नियुक्तियां 7
- वर्टिकल/प्रकोष्ठ 7
- नीति आयोग की शासी परिषद 8

खंड-II
नीतियां और कार्यक्रम 11

- प्रस्तावना 11
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम 11
- स्वास्थ्य और पोषण 13
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण 16
- उद्योग 16
- मिशन लाइफ–पर्यावरण के लिए जीवन शैली 18

खंड-III
निगरानी एवं मूल्यांकन 23

- प्रस्तावना 23
- विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) 23
- निष्पादन डैशबोर्ड 27
- प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सूचकांक 33

खंड-IV

सहकारी संघवाद 41

- प्रस्तावना 41
- राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) 41
- मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 43
- मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों के साथ बैठक 45
- द्वीपों का समग्र विकास 46
- भारतीय हिमालयन क्षेत्र का संधारणीय विकास 47
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नीति मंच 47
- परियोजना साथ-ई 48
- एसडीजी का स्थानीयकरण 49
- राज्यों के साथ जुड़ाव 51

खंड-V

थिंक-टैंक की गतिविधियाँ 57

- प्रस्तावना 57
- अर्थशास्त्रियों का जमावड़ा 57
- नीति इन-हाउस व्याख्यान श्रृंखला 58
- सीमांत प्रौद्योगिकियां 62
- राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बैटरी भंडारण मिशन 63
- कार्बन कैप्चर, मेथनॉल और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था 64
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग 66
- भागीदारी 70
- महिला उद्यमिता मंच 70
- राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) 71

खंड-VI

अटल इनोवेशन मिशन 77

- प्रस्तावना 77
- अटल टिंकरिंग लैब्स 78
- अटल इन्क्यूबेशन सेंटर 80
- अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर 83
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज 88

- एआईएम ईकोसिस्टम विकास कार्यक्रम (एईडीपी) 90
- वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (प्रादेशिक नवोन्मेष कार्यक्रम) 92
- विवाटेक में भारत 93

खंड-VII
कार्यक्षेत्र की उपलब्धियां 97

- प्रस्तावना 97
- कृषि 98
- चक्रीय अर्थव्यवस्था 100
- डाटा प्रबंधन, विश्लेषण और सीमांत प्रौद्योगिकी 102
- अर्थ एवं वित्त प्रकोष्ठ 104
- शिक्षा 106
- ऊर्जा 112
- शासन और अनुसंधान 114
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 117
- उद्योग-I 119
- उद्योग-II 120
- अवसंरचना-कनेक्टिविटी 120
- शहरीकरण प्रबंधन 122
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) 123
- प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण 123
- परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) 124
- सार्वजनिक निजी भागीदारी 125
- ग्रामीण विकास 127
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 127
- कौशल विकास और रोजगार 129
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता 131
- राज्य वित्त एवं समन्वय 133
- सतत विकास लक्ष्य 136
- व्यापार एवं वाणिज्य 137
- पर्यटन और संस्कृति 139
- स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ 140
- जल एवं भूमि संसाधन 140
- महिला एवं बाल विकास 141

खंड-VIII

प्रशासन और सहायक इकाइयां 147

- प्रस्तावना 145
- टीम नीति के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करना 145
- आजीविका प्रबंधन 148
- संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ 148
- शासी परिषद सचिवालय 149
- हिंदी अनुभाग 149
- पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र 151
- ओएम एंड सी अनुभाग 152
- आरटीआई प्रकोष्ठ 154
- सतर्कता अनुभाग 154

अनुलग्नक 159

संक्षेपाक्षरों की सूची

एबीपी	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
एसीसी	उन्नत रसायन सेल
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीपी	आकांक्षी जिला कार्यक्रम
एआई/एमएल	कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग
एआईआईएमएस	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एआईएम	अटल नवाचार मिशन
एपीआई	सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक
एपीआई$_{एस}$	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
बीएमजेड	संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (जर्मनी)
सीबीसी	क्षमता निर्माण आयोग
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी करार
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीएम	मुख्य मंत्री
सीपीएसई$_{एस}$	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
सीएस	मध्य क्षेत्र
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसओ$_{एस}$	सिविल सोसायटी ऑर्गनाइजेशन

सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
सीएसएस	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
सीडब्ल्यूएमआई	समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
सीओसी	चैंपियंस ऑफ चेंज
डीईएसी	विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति
डीजीक्यूआई	डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक
डीएमईओ	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय
ईसीटीए	आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
ईजीओएस	सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह
ईपीआई	निर्यात तैयारी सूचकांक
एफआईसीसीआई	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
एफएमसीजी	जल्दी चलने वाले उपभोक्ता सामान
जीआईआई	वैश्विक नवाचार सूचकांक
जीआईआरजी	सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीआईजैड	जर्मन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु और सेवा कर
जीटीएपी	वैश्विक व्यापार विश्लेषण परियोजना
जीओआई	भारत सरकार
एचएलपीएफ	सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच
एचएमआईएस	स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईएएफ$_{एस}$	भारतीय प्रशासनिक अध्येता
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ
आईसीईडी	भारतीय जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईडीए	द्वीप विकास एजेंसी

आईईडी	भारत ऊर्जा डैशबोर्ड
आईईएसएस	भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य
आईएफपीआरआई	अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
आईएचबीटी	इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी
आईएचसीयूसी	इंडियन हिमालयन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम
जेसीईआरटी	झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य समूह
केपीआई	प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक
केएसएम$_{एस}$/डीआई$_{एस}$/एपीआई$_{एस}$	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एमएंडई	अनुवीक्षण और मूल्यांकन
एमडीओएनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमआईबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
एमआईटीआरए	महाराष्ट्र इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमपीआई	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमओएचएंडएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएचयूए	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एनएएस	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनआईएलईआरडी	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान
एनआईटीआई	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था

एनएमपी	राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
एनओटीपी	राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम
ओओएमएफ	परिणाम निष्पादन निगरानी रूपरेखा
ओओएससी	स्कूल में न पढ़ने वाले बच्चे
पीएलआई	उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन
पीएमजेएवाई	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पीएसएचआईसीएमआई	भारत के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए नीति एवं कार्यनीति
एसएटीएच-ई	मानव पूंजी को बदलने के लिए सतत कार्रवाई -शिक्षा
एससी-एनईसी	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसईसीआई	राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक
एसईक्यूआई	स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
एसईटीयू	उत्तराखंड को सशक्त बनाने और बदलने के लिए राज्य संस्थान
एसआईटी	परिवर्तन के लिए राज्य संस्थान
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रियाएँ
एसटीसी	राज्य परिवर्तन आयोग
एसओआई	आशय का कथन
यू-डीआईएसई	शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संस्थान

GATE No.
5
EXIT
OUT

नीति आयोग NITI AAYOG
नीति भवन NITI BHAWAN

खंड

01

नीति आयोग: ढांचा गठन

प्रस्तावना

केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से 01 जनवरी, 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह भारत सरकार का नीति से संबंधित प्रमुख 'थिंक टैंक' है, जो निर्देशनात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के अलावा, नीति आयोग केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कार्यनीतिक एवं तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय हित में साथ मिलकर कार्य करने के लिए राज्यों को एक मंच पर लाने के लिए नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

नीति आयोग का गठन (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी
अध्यक्ष

श्री सुमन बेरी
उपाध्यक्ष

पूर्णकालिक सदस्य

डॉ. वी के सारस्वत
सदस्य

प्रो. रमेश चंद
सदस्य

डॉ. वी के पॉल
सदस्य

डॉ. अरविंद विरमानी
सदस्य

श्री परमेश्वरन अय्यर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नीति आयोग का गठन (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

पदेन सदस्य

श्री राजनाथ सिंह
माननीय रक्षा मंत्री

श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री और
सहकारिता मंत्री

श्रीमती निर्मला सीतारमण
माननीया वित्त मंत्री और
कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

श्री नरेंद्र सिंह तोमर
माननीय कृषि एवं किसान
कल्याण मंत्री

विशेष आमंत्रितगण

श्री नितिन जयराम गडकरी
माननीय सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्री

श्री पीयूष गोयल
माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक
वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री

श्री अश्विनी वैष्णव
माननीय रेल मंत्री,
संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

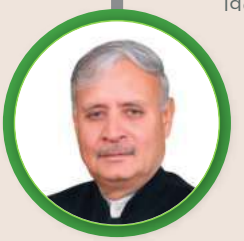

राव इंद्रजीत सिंह
माननीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री

डॉ. वीरेंद्र कुमार
माननीय सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्री

उद्देश्य और विशेषताएं

नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इस नोडल एजेंसी को आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर वाले दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत के राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों के एक साझा विजन का विकास करना।
- यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्रों का विकास करना और इनको उत्तरोतर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना।
- यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित किया गया है।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो सकता है।
- कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और प्रभाव की निगरानी करना। निगरानी और फीडबैक के माध्यम से सीखे गए सबक का प्रयोग आवश्यक मध्यावधि संशोधन सहित नवोन्मेषी सुधार करने के लिए किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्क्षेत्रक और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना।
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का अनुरक्षण करना, सुशासन पर अनुसंधान तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का भण्डार बनना और साथ ही उसे हितधारकों तक पहुंचाने में भी मदद करना।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ-साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रियता से मूल्यांकन और निगरानी करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
- कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना।
- ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लागू करने और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

नीति आयोग खुद को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है जो इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति विज़न प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में समर्थ बनाएगा। इसे एक संबद्ध कार्यालय यानी विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन संगठन (डीएमईओ), एक महत्वपूर्ण पहल यानी अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और एक स्वायत्त निकाय यानी श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

नीति आयोग के समस्त कार्यकलापों को चार मुख्य शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है:

1. नीति और कार्यक्रम रूपरेखा
2. सहकारी एवं तुलनात्मक संघवाद
3. निगरानी एवं मूल्यांकन
4. थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र

नियुक्तियां

वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार ने डॉ. राजीव कुमार के पदत्याग के उपरांत, श्री सुमन बेरी को उनके स्थान पर नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। श्री सुमन बेरी ने दिनांक 01.05.2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके अलावा, श्री परमेश्वरन अय्यर ने श्री अमिताभ कांत के कार्यकाल के पूरा होने पर दिनांक 10.07.2022 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है । डॉ. अरविंद विरमानी ने दिनांक 16.11.2022 को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

वर्टिकल/प्रकोष्ठ

नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकल, प्रकोष्ठ, संबद्ध कार्यालय और स्वायत्त निकाय इसके अधिदेश को पूरा करने के लिए आवश्यक समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं। वर्टिकल और प्रकोष्ठ की सूची नीचे दी गई है :

- प्रशासन और सहायता एकक
- कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रकोष्ठ
- संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ
- डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण और फ्रंटियर प्रौद्योगिकी
- अर्थ एवं वित्त प्रकोष्ठ
- शिक्षा
- शासन और अनुसंधान
- शासी परिषद सचिवालय और समन्वय
- उद्योग-I
- उद्योग-II

- इन्फ्रास्ट्रक्चर–कनेक्टिविटी
- इन्फ्रास्ट्रक्चर–ऊर्जा
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
- प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण और द्वीप विकास
- परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी
- ग्रामीण विकास
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ
- सामाजिक क्षेत्र-I (कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार, और शहरी विकास)
- सामाजिक क्षेत्र-II (स्वास्थ्य एवं पोषण, और महिला एवं बाल विकास)
- राज्य वित्त एवं समन्वय
- सतत विकास लक्ष्य
- जल एवं भूमि संसाधन

नीति आयोग की शासी परिषद

नीति आयोग की शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से 16 फरवरी, 2015 को प्रभाव में आई। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से शासी परिषद का पुनर्गठन किया गया।

शासी परिषद प्रमुख निकाय है जिसे विकास की गाथा को आकार देने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों का एक साझा विज़न विकसित करने का काम सौंपा गया है। शासी परिषद, जो सहकारी संघवाद के उद्देश्यों का प्रतीक है, राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रक, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रस्तुत करती है।

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों और शासी परिषद के अन्य सदस्यों के साथ अब तक शासी परिषद की सात बैठकें हो चुकी हैं।

शासी परिषद की सातवीं बैठक

7 अगस्त, 2022 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की सातवीं बैठक हुई। बैठक में 23 मुख्यमंत्रियों, 3 उप राज्यपालों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों ने भाग लिया। बैठक में पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रिती के रूप में चुनिंदा केंद्रीय मंत्रियों; नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों; मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव; नीति आयोग के सीईओ; और भारत सरकार के चुनिंदा सचिवों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। महामारी की शुरुआत के बाद से शासी परिषद की यह पहली प्रत्यक्ष बैठक थी, जबकि 2021 की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी।

7 अगस्त, 2022 को आयोजित शासी परिषद की 7वीं बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/ उप राज्यपालों के साथ माननीय प्रधानमंत्री

माननीय प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद की भावना से सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की, जिसने कोविड महामारी से उभरने में भारत की मदद की और वैश्विक नेता के रूप में भारत की ओर देखने के लिए विकासशील देशों के लिए एक उदाहरण के रूप में भारत को प्रस्तुत करने में राज्यों की मदद की।

इस वर्ष, शासी परिषद ने 15 से 17 जून 2022 के बीच धर्मशाला में आयोजित मुख्य सचिवों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निर्धारित एजेंडे पर विचार-विमर्श किया, जिसमें फसल विविधीकरण और दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना; स्कूल और उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का कार्यान्वयन शामिल था। इसके अलावा, भारत की आगामी जी-20 अध्यक्षता पर माननीय विदेश मंत्री द्वारा प्रस्तुति दी गई।

माननीय प्रधानमंत्री ने उपर्युक्त सभी मुद्दों के महत्व पर, विशेष रूप से आधुनिक कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बन सके। उन्होंने कहा कि तेजी से हो रहा शहरीकरण भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की सुगमता, पारदर्शी सेवा वितरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए भारत की ताकत बन सकता है जिसके लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 2023 में भारत को जी-20 की जो अध्यक्षता मिली है वह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भारत की विविधता को प्रदर्शित करने और जी-20 के इर्द-गिर्द एक जन आंदोलन विकसित करने का अनूठा अवसर है।

अपने समापन भाषण में, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक राज्य को पूरे विश्व में स्थित भारतीय मिशनों की मदद से अपने 3टी–व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी–को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। राज्यों को आयात कम करने, निर्यात बढ़ाने और इसके लिए अवसरों की पहचान करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, बल्कि यह एक साझा लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि जीएसटी के संग्रहण में वृद्धि के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है जो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी हितधारकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में शामिल होना चाहिए और इसके लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध रोडमैप विकसित करना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है वे अगले 25 वर्षों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को परिभाषित करेंगे और यह भी कहा कि हम आज जो बीज बो रहे हैं, वह 2047 में भारत को मिलने वाले फलों को तय करेंगे।

खंड

02

नीतियां और कार्यक्रम

प्रस्तावना

नीति आयोग को राज्यों, नागरिक समाज और अन्य थिंक टैंकों की सक्रिय भागीदारी से कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचा और पहलों को डिजाइन करने और उनकी प्रगति और कारगरता की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है।

2022-23 में, जैसा कि भारत ने अमृत काल अर्थात् इंडिया@100 के लिए 25 वर्षीय लीडअप में प्रवेश किया है, नीति आयोग ने सर्व-समावेशी कल्याण वाले सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ स्थूल आर्थिक स्तर की संवृद्धि को बढ़ाने का बीड़ा उठाया है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) ने जनवरी 2023 में पांच साल पूरे कर लिए हैं–जिनमें से लगभग दो साल कोविड-19 महामारी की तीव्र वेदना में थे। इस प्रकार, एडीपी जिलों के जीवनकाल में एक अभूतपूर्व अवधि का हिस्सा रहा है, और जो उभर कर सामने आया है वह आशाजनक है।

इस कार्यक्रम ने अच्छे और प्रभावी शासन के एक सफल टेम्पलेट के रूप में काम किया है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत भारत के 112 पिछड़े जिलों ने ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है जो लोगों के लिए मायने रखते हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य ताकत डेटा पर आधारित शासन पर इसका ध्यान है जो जिला स्तर पर साक्ष्य आधारित नीतिगत अंतःक्षेप का मार्ग प्रशस्त करता है। नीति आयोग मासिक आधार पर प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआइ) पर 112 आकांक्षी जिलों की निगरानी करता है। केपीआई को इस

तरह से डिजाइन किया गया है कि इनपुट और प्रक्रिया संकेतकों का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना जैसे प्रमुख सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में वांछनीय आउटपुट और परिणाम प्राप्त किए जा सकें। निगरानी की मजबूत कार्यनीति ने जिला प्रशासन को अंतर विभागीय समीक्षाओं में शामिल होने और इस प्रकार अभिसरण लाने में सक्षम बनाया है। डेल्टा रैंक के मासिक विमोचन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा जिलों को केपीआई में सुधार के लिए लगातार प्रेरित करती रहती है।

जिलों ने पिछले पांच वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य एवं पोषण के अंतर्गत, जिलों ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं बच्चों के पोषण से संबंधित संकेतकों में अच्छी प्रगति का प्रदर्शन किया है। प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकरण, बाल टीकाकरण और पूरक पोषण का प्रावधान आदि जैसे संकेतकों ने बड़ी प्रगति का प्रदर्शन किया है। स्वच्छता और विद्युतीकरण जैसे स्कूल अवसंरचना और बुनियादी अवसंरचना के संकेतक भी संतृप्ति के करीब हैं।

इस कार्यक्रम ने पिछले वर्षों में परिणाम देना जारी रखा है क्योंकि यह सभी हितधारकों–केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों, निजी भागीदारों, नागरिक समाज और आम जनता के प्रयासों को समन्वित करने में सफल रहा है। संबद्ध मंत्रालयों ने जिलों में अपने-अपने संकेतकों में सुधार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की हैं और जिलों के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

नीति आयोग ने रीयल टाइम के डेटा संग्रह और निगरानी के लिए "परिवर्तन के चैंपियन" डैशबोर्ड का विकास और उपयोग किया है। नीति आयोग ने 'परिवर्तन की गाथाएं' और 'सर्वोत्तम प्रथाएं' नामक प्रकाशनों के माध्यम से सफलता की कहानियों को संकलित किया है। ये अंतःक्षेप जिनको व्यवहारिक सिद्धांतों के उपयोग, नवाचार, प्रतिकृति और प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता के आधार पर चुना गया है, प्रदर्शित करते हैं कि कैसे व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और नवाचारी पहलें जमीनी स्तर पर परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। नीति आयोग जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में बदलाव के लिए अन्य जिलों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को नियमित रूप से साझा भी करता है। ऐसे जिलों से उभरने वाली इन सर्वोत्तम प्रथाओं को समान चुनौतियों से जूझ रहे देश के अन्य हिस्सों में लागू करके महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जा सकती है।

आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से निर्देशित नीति आयोग ने प्रमुख पहलों के माध्यम से एडीपी टेम्प्लेट को दोहराने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम (एबीपी) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 500 पिछड़े ब्लॉकों में समग्र और सतत विकास को गति देना है। एबीपी के तहत, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से भारत के 28 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों से 500 पिछड़े ब्लॉकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य के अन्य ब्लॉकों के समकक्ष होने या उनकी तुलना में बेहतर होने के लिए विभिन्न योजनाओं के त्वरित और समन्वित कार्यान्वयन के लिए ब्लॉकों का समर्थन करेगा। उच्च प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर काम किया जा रहा है और ऐसे ब्लॉकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जो प्रमुख संकेतकों पर सुस्पष्ट प्रगति हासिल करेंगे। मिशन उत्कर्ष के तहत, मंत्रालयों/विभागों, जिनका जनता के साथ जुड़ाव है, ने अपने-अपने केपीआई के आधार पर सबसे पिछड़े जिलों का चयन किया है और इन पिछड़े जिलों को अगले एक वर्ष में राज्य के औसत और अगले दो वर्ष के अंदर राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

झारखंड के साहिबगंज जिले के एक प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करती महिलाएं

स्वास्थ्य और पोषण

एकीकृत स्वास्थ्य नीति

समावेशी, किफायती तथा साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य नीति की संकल्पना तैयार की जा रही है। शिक्षा, अनुसंधान, क्लीनिकल प्रैक्टिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के मुख्य क्षेत्रों को देखने के लिए एक समिति और चार कार्य समूहों का गठन किया, जिन्होंने कार्यात्मक एकीकरण के लिए एकीकृत दृष्टिकोणों के लिए सिफारिशें प्रदान की हैं। दोनों प्रशासनिक मंत्रालयों अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्रियों को सिफारिशें प्रस्तुत कर दी गई हैं। अंतिम दस्तावेज पर काम चल रहा है।

राष्ट्रीय टेली-मेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम

नीमहंस बेंगलुरु के सहयोग से नीति आयोग ने राष्ट्रीय टेली-मेंटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रूपरेखा तैयार की, जिसके बाद केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार लोगों को 24x7 मुफ्त परामर्श और देखभाल प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय टेली-मेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया गया। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा।

दुर्लभ रोगों के लिए ऑर्फन ड्रग और उपचार

आज 7000 से अधिक दुर्लभ बीमारियां ज्ञात हैं, जिससे दुनिया भर में 300 मिलियन लोग और अकेले भारत में लगभग 90 मिलियन लोग प्रभावित हैं। दुर्लभ रोगों का क्षेत्र जटिल और विषम है। ज्ञात आणविक आधार वाले विकारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन स्वीकृत उपचारों की संख्या बहुत पीछे है। इसे ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 'दुर्लभ रोगों के लिए औषधि एवं खुराक प्रपत्र: विनिर्माताओं के साथ जुड़ाव' पर एक समिति का गठन किया गया और फार्मास्यूटिकल्स विभाग और चिकित्सकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया ताकि प्राथमिकता वाले विकारों/संकेतों की पहचान और उनसे संबंधित उपचारों पर विचार किया जा सके जिनको ऑर्फन ड्रग के घरेलू निर्माण के लिए सक्षम किया जा सकता है। जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार, समिति ने सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक (एपीआई) के निर्माताओं के शॉर्टलिस्ट किए गए सेट के साथ जुड़ाव के लिए पांच बैठकें बुलाई हैं।

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में सुधार

मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, जिसे संसद द्वारा 1994 में पहली बार पारित किया गया था, के प्रावधानों के अनुसार भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण सरकार द्वारा विनियमित गतिविधि है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) की जांच करने की पहल की है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डीजीएचएस और एनओटीटीओ के सहयोग से बेहतर और उन्नत एनओटीपी की स्थापना को सक्षम करने की प्रक्रिया में है।

दान किए गए अंगों के अंतर-राज्यीय परिवहन को एनओटीपी दिशानिर्देश 2021 में एक चुनौती के रूप में माना गया है। नीति आयोग ने सात संबद्ध मंत्रालयों के लिए अंग परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों को एसओपी का मसौदा परिचालित किया है, जिसके बाद 01 नवंबर, 2022 को सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक परिचयात्मक अंतर-मंत्रालयी बैठक की गई, जिसमें मंत्रालयों और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों ने भाग लिया, जिसमें राज्यों से मिले इनपुट को भी साझा किया गया। यह बैठक देश के भीतर अंगों के परिवहन और उपयोग को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम थी। अंग परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के अलावा, एक उन्नत राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम की दिशा में अग्रेतर काम चल रहा है।

देश के भीतर अंगों के परिवहन को मजबूत करने के लिए माननीय सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी बैठक

सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए पहुंच में वृद्धि करना

सहायक प्रौद्योगिकी (एटी) में कोई भी वस्तु, उपकरण, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या उत्पाद प्रणाली शामिल हो सकती है जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने या सुधारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, एटी का उपयोग मानव शरीर में दृष्टि या श्रवण में कमी या लोकोमोटर विकलांगता जैसे बुढ़ापे के परिवर्तनों से संबंधित कार्यात्मक क्षति को दूर करने और बौद्धिक या सीखने की अक्षमता के कारण होने वाली विकलांगता से संबंधित कार्यात्मक क्षति को भी दूर करने के लिए किया जाता है। नीति आयोग एटी की पहुंच और सुलभता में सुधार के लिए अपने प्रयास के तहत आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि उन लोगों की अपूर्ण आवश्यकता और इस क्षेत्र की क्षमता को समझा जा सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

आपातकालीन और आघात देखभाल प्रणाली को बदलना : आयुष्मान भारत के तहत एक नए मिशन की अवधारणा

भारत में आपातकाल और आघात के मामलों का बोझ देखने को मिलता है, जिसमें युवाओं का अनुपात काफी अधिक होता है, जो अक्सर परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य होते हैं और यह अधिक मात्रा में तुरंत देय खर्च थोपता है जिससे स्वास्थ्य के इन मुद्दों को हल करने की अत्यावश्यकता बढ़ जाती है। इन मुद्दों को हल करने से कई एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान मिलेगा, जिसमें 2030 तक सड़क यातायात की दुर्घटनाओं से वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना शामिल है और यह प्रसूति, बाल चिकित्सा, संक्रमण, एनसीडी और आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों को भी शामिल करता है। मजबूत, समग्र एम्बुलेंस–आपातकालीन–आघात देखभाल प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए इन मुद्दों को व्यापक तरीके से हल करने की तत्काल आवश्यकता है।

नीति आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ इस योजना पर काम कर रहा है और डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए विभिन्न राज्यों/अन्य देशों में मॉडल का अध्ययन करने के अलावा, आपातकालीन देखभाल की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए 100 सुविधाओं का अध्ययन (एम्स, नई दिल्ली के साथ) किया है। उच्चतम पदाधिकारियों को शामिल करते हुए इस योजना पर कई उच्च स्तरीय प्रस्तुतियां दी गई हैं, जिसमें इसे संकर्षण मिला है और बेहतर अनुकूलन के लिए इसे और परिष्कृत किया जा रहा है।

परिवार चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से एमडी डॉक्टरों का प्रसरण

उम्मीद की जाती है कि भारत के प्रमुख एम्स/आईएनआई में जीवंत एमडी परिवार चिकित्सा कार्यक्रम या पाठ्यक्रम देश भर के मेडिकल कॉलेजों में इस तरह के पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। मध्यम अवधि का लक्ष्य यह है कि भारत के लोगों को परिवार स्वास्थ्य/सामान्य प्रैक्टिस स्पेशियलिटी पेशेवर स्वास्थ्य देखभाल तक इष्टतम पहुंच प्राप्त हो। देश के मेडिकल कॉलेजों में परिवार चिकित्सा कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता के मद्देनजर, नीति आयोग देश में नए एम्स/आईएनआई के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है ताकि वे अपने-अपने चिकित्सा संस्थानों में परिवार चिकित्सा कार्यक्रम शुरू कर सकें।

भारत के नामौजूद मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए नीति और कार्यनीति

नीति आयोग की 'भारत के नामौजूद मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा' नामक रिपोर्ट के जारी होने के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नीति आयोग से 'नामौजूद मध्यम वर्ग' तक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने की कार्यनीति का सुझाव देने का अनुरोध किया, जो आबादी की एक व्यापक श्रेणी है, वंचित गरीब वर्गों और अपेक्षाकृत संपन्न संगठित क्षेत्र के बीच स्थित है जिसमें स्वास्थ्य बीमा की कमी है। तदनुसार, नीति आयोग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक बहु हितधारक समिति का गठन किया गया और इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सदस्यों और बीमा क्षेत्र सहित अन्य हितधारकों को शामिल किया गया।

इस समिति को (i) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के दायरे में या इससे स्वतंत्र स्वास्थ्य कवरेज को नामौजूद मध्यम वर्ग तक बढ़ाने या विस्तारित करने की नीति और कार्यनीति तैयार करने; (ii) व्यक्ति या समूह के रूप में नामौजूद मध्यम वर्ग की पहचान के लिए मानदंड तैयार करने और इनके प्रशंसनीय नामांकन या सदस्यता के लिए किसी क्रियाविधि की कार्यनीति तैयार करने; (iii) प्रभावी वितरण के तरीके सुझाने, स्वास्थ्य बीमा के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने; और (iv) नामौजूद मध्यम वर्ग तक कवरेज बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन के मार्ग सुझाने का काम सौंपा गया है। समिति ने कई हितधारक विचार-विमर्श आयोजित किए हैं और अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)

केंद्रीय बजट 2021-22 में संवर्धित और सतत अवसंरचना वित्त पोषण के लिए देश के तीन स्तंभों में से एक के रूप में मुख्य परिसंपत्ति मुद्रीकरण को चिन्हित किया गया था। बजट में नीति आयोग को ब्राउनफील्ड की मुख्य अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का निर्माण करने का काम सौंपा गया है। एनएमपी को अगस्त 2021 में जारी किया गया जिसमें चार साल (वित्त वर्ष 2022 से 2025) की अवधि में केंद्रीय मंत्रालयों/सीपीएसई की 6.0 लाख करोड़ रुपये के सांकेतिक मूल्य वाली संभावित मुख्य परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण नीति और पाइपलाइन को सूचीबद्ध करने के लिए रूपरेखा विहित की गई है। यह सड़क, रेलवे, विमानन, विद्युत, तेल और गैस तथा भंडारण सहित विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में संभावित मुद्रीकरण के लिए तैयार परियोजनाओं की पहचान करने के लिए मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में कार्य करता है।

इसकी शुरुआत के बाद से, नीति आयोग ने निवेश और लेनदेन संरचना, प्रगति की समीक्षा और अंतर-मंत्रालयी और संरचनात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श पर मंत्रालयों के साथ मिलकर काम किया है। वित्त वर्ष 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्य (88,000 करोड़ रुपये) को प्राप्त कर लिया गया था, जबकि संबंधित मंत्रालयों द्वारा ~1.4 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की पाइपलाइन प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023 के लिए 1,62,422 करोड़ रुपये के कुल लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से ~26,000 करोड़ रुपये के अर्जित और/या निवेश में मुद्रीकरण मूल्य के साथ लेनदेन पूरा हो गया है। इसके अलावा, वर्तमान में कुल ~1.23 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की पाइपलाइन प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में है।

उद्योग

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

भारत में विनिर्माण तथा भारत से निर्यात को बल प्रदान करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने अनेक संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों के परामर्श से 5 साल की अवधि के लिए प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने का आधार तैयार किया था। 11 नवंबर, 2020 को आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई।

पीएलआई योजना का उद्देश्य प्रत्येक चयनित क्षेत्र में सीमित संख्या में पात्र एंकर इकाइयों के लिए वृद्धिमूलक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है, जो प्रौद्योगिकी, संयंत्र एवं मशीनरी तथा अनुसंधान एवं विकास में निवेश करेंगी। योजना के तहत स्थापित एंकर इकाइयों के लिए व्यापक आपूर्तिकर्ता आधार के निर्माण के माध्यम से इस योजना के लाभप्रद प्लवन प्रभाव भी होंगे जिससे बड़े पैमाने पर प्राथमिक और द्वितीयक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन योजनाओं से अगले पांच वर्षों में 14 क्षेत्रों में उत्पादन में 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है और 60 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

नीति आयोग ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ व्यक्तिगत पीएलआई योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में सहायक की भूमिका निभाई है। वर्तमान में सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नीति आयोग के सीईओ सभी 14 क्षेत्रों की पीएलआई योजनाओं की निगरानी के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) का हिस्सा हैं।

क्षेत्रों, कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों की सूची तथा क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :

प्राथमिकता	क्षेत्र	क्रियान्वयन करने वाला मंत्रालय/ विभाग	अनुमोदित वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1	क्रिटिकल केएसएम/डीआई/एपीआई	औषध विभाग	6,940
2	चिकित्सा डिवाइस	औषध विभाग	3,420
3	बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक्स का विनिर्माण	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	38,645
4	एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	भारी उद्योग मंत्रालय	18,100
5	इलेक्ट्रानिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	7,350
6	आटोमोबाइल एवं आटो कंपोनेंट	भारी उद्योग मंत्रालय	25,938
7	फार्मास्युटिकल ड्रग	औषध विभाग	15,000
8	दूरसंचार के नेटवर्किंग उत्पाद	दूरसंचार विभाग	12,195
9	टेक्सटाइल उत्पाद : एमएमएफ सेगमेंट तथा टेक्निकल टेक्सटाइल	वस्त्र मंत्रालय	10,683
10	खाद्य उत्पाद	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	10,900
11	उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	4,500
12	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	6,238
13	स्पेशियलिटी स्टील	इस्पात मंत्रालय	6,322
14	ड्रोन और ड्रोन के कंपोनेंट	नागर विमानन मंत्रालय	120

वैधीकरण समिति

मार्च 2022 में नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में 'भारत में कारोबार करने की सहूलियत के लिए गैर अनुपालन का वैधीकरण' पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया। नीति आयोग ने आगे की कार्रवाई और सभी मंत्रालयों में मानकीकरण के लिए 36 मंत्रालयों की समीक्षाओं के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा और सीख को डीपीआईआईटी को भेज दिया है। नीति आयोग वैधीकरण की कवायद में डीपीआईआईटी को समर्थन देना जारी रखे हुए है।

अनुबंध के प्रवर्तन पर कार्यबल

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया। इस संबंध में, प्रक्रिया, मानव संसाधन और अवसंरचना में कमियों की पहचान करने के लिए उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और कुछ वाणिज्यिक न्यायालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं। इसके अलावा, अवसंरचना और मानव संसाधन से जुड़ी अड़चनों की पहचान करने के लिए सभी वाणिज्यिक न्यायालयों और उच्च न्यायालयों का एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया।

मिशन लाइफ–पर्यावरण के लिए जीवन शैली

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में सीओपी 26 के दौरान लाइफ–पर्यावरण के लिए जीवन शैली का विजन दिया। लाइफ के तहत 'बिना सोचे-समझे और विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत और सोच-समझकर उपयोग' के लिए सभी को एक साथ लाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने की परिकल्पना की गई है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सामूहिक व्यक्तिगत व्यवहार कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकते हैं।

भारत का यह मानना है कि कुल मिलाकर व्यक्ति और समुदाय के पर्यावरण हितैषी व्यवहार का पर्यावरण और जलवायु संकट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर जीवन जीने का स्वस्थ और टिकाऊ तरीका जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की कुंजी है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में शामिल किया है। इसके बाद, यह निर्णय लिया गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन लाइफ के भारतीय पहलुओं को देखेगा और नीति आयोग इस मिशन के वैश्विक पहलुओं को आगे बढ़ाएगा।

20 अक्टूबर, 2022 को केवडिया गुजरात में मिशन लाइफ के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद में विश्व स्तर पर मिशन लाइफ लॉन्च किया। अर्जेंटीना, एस्टोनिया, फ्रांस, जॉर्जिया, गुयाना, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम सहित दस देशों के राष्ट्राध्यक्षों/प्रधानमंत्रियों ने वीडियो संदेश के माध्यम से मिशन लाइफ का समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ की बुकलेट लॉन्च की जा रही है

संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ का लोगो लॉन्च किया जा रहा है

भारत की आजादी के 75वें वर्ष में लॉन्च किए जा रहे मिशन लाइफ को ध्यान में रखते हुए, सात श्रेणियों में 75 अलग-अलग लाइफ एक्शन की गैर व्यापक सूची की पहचान की गई है :

- ऊर्जा की बचत
- पानी की बचत
- सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी
- सतत खाद्य प्रणाली को अपनाना
- अपशिष्ट में कमी (स्वच्छता)
- स्वस्थ जीवन शैली अपनाना
- ई-कचरे में कमी

ये क्रियाएं विशिष्ट और मापने योग्य, व्यवहार में लाने में आसान और चल रही आर्थिक गतिविधियों के लिए गैर विघटनकारी हैं।

नीति आयोग ने दुनिया भर से कागजात/विचारों को आमंत्रित करने के लिए लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज एंड पेपर्स की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को जलवायु हितैषी आचरण अपनाने के लिए प्रेरित करना है। शीर्ष 75 विचारों को एक संग्रह के रूप में संकलित किया जाएगा और शीर्ष 5 विचारों को जून 2023 में लाइफ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा।

APL
BPL
AAY
5 Kg.
25 kg
35 Kg.
500 ग्राम

खंड

03

निगरानी एवं मूल्यांकन

प्रस्तावना

साक्ष्य आधारित नीति निर्माण दक्षता बढ़ाने और निर्णय लेने में सुधार का मूल मंत्र है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), जो नीति आयोग की एक संबद्ध इकाई है, सरकारी नीति और कार्यक्रमों के सभी स्तरों पर निगरानी और मूल्यांकन के अनुप्रयोग और उपयोग को संस्थागत बनाने की कल्पना करता है और यह दक्षता, कारगरता, समता, स्थिरता और परिणामों की प्राप्ति में सुधार लाने में मदद करता है। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, डेटा प्रणाली और वास्तुशिल्प को मजबूत करना, और निगरानी एवं मूल्यांकन के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना डीएमईओ के प्रमुख स्तंभ हैं।

इसके अलावा, नीति आयोग ने डेटा विश्लेषण के आधार पर प्रभावी प्रबंधन एवं बेहतर परिणामों पर ध्यान देते हुए अनेक सूचकांकों एवं डैशबोर्डों का भी विकास किया है।

विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)

डीएमईओ भारत सरकार का सर्वोच्च अनुवीक्षण और मूल्यांकन (एमएंडई) निकाय है। नीति आयोग के सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के अधिदेश के तहत इसके कार्यक्षेत्र में राज्यों को तकनीकी सलाह प्रदान करना भी शामिल है। पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए डीएमईओ को अनन्य रूप से एक अलग बजटीय आवंटन प्रदान किया गया है।

डीएमईओ की भूमिका इस प्रकार है : (i) आवश्यक मध्यावधि संशोधनों सहित सुधारों को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतिक एवं दीर्घावधिक नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा तथा पहलों की प्रगति एवं प्रभाव की निगरानी करना; और (ii) सफलता की संभावना तथा प्रदायगी के कार्यक्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन की सक्रियता से निगरानी एवं मूल्यांकन करना।

2022-23 में डीएमईओ द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाएं

- उत्पाद–परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ)
- डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई)
- सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक का अनुवीक्षण
- मूल्यांकन को संस्थागत बनाना और बढ़ावा देना
- राज्यों के साथ काम करना

उत्पाद–परिणाम निगरानी रूपरेखा

उत्पाद–परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) केन्द्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे 2017-18 से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों का ध्यान भौतिक और वित्तीय प्रगति पर केंद्रित करने के बजाय किए गए कार्यों के परिणामों पर केंद्रित करने के लिए परिणाम निगरानी को संस्थागत बनाना है। ओओएमएफ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- लगातार 4 वर्षों से यह रूपरेखा प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के साथ संसद में रखी जा रही है
- सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 54 ने ओओएमएफ को मंत्रालयों/विभागों के लिए एक अभिन्न प्रक्रिया बनायी है
- इसमें 67 मंत्रालय/विभाग शामिल हैं
- 11+ लाख करोड़ रुपये के संचयी वार्षिक बजटीय परिव्यय के साथ 500+ केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस)
- प्रगति और अनुपालन रिपोर्टों के माध्यम से डैशबोर्ड पर उत्पाद और परिणाम के 5000+ संकेतकों को ट्रैक किया गया

मुख्य रूप से (i) केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने; (ii) विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इसके परिणामों की निगरानी करने, (iii) पिछले वर्ष की ओओएमएफ समीक्षा बैठक से संबंधित कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा करने, और (iv) अन्य मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 2020 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओओएमएफ से संबंधित वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। 2020-21 और 2021-22 के दौरान कुल मिलाकर क्रमशः 37 और 53 ऐसी समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। 18 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 30 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं।

इसके अलावा, ओओएमएफ की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएस/सीएसएस की सभी योजनाओं की रूपरेखा और संकेतकों की एक सतत क्षमता निर्माण कवायद तथा व्यवस्थित समीक्षा पूरे वर्ष की जाती है। सरकार

के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों की क्षमता में सुधार लाने के लिए भी डीएमईओ निरंतर प्रयास करता रहा है। ओओएमएफ रूपरेखा में योजनाओं के प्रदर्शन में सुधार लाने और सरकारी हस्तक्षेपों की दक्षता के साथ-साथ कारगरता बढ़ाने की काफी क्षमता है। इस संदर्भ में, डीएमईओ ने 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ कई ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए हैं।

डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई)

अंतिम डीजीक्यूआई 2.0 के बाद फरवरी 2022 में 74 मंत्रालयों/विभागों के लिए रिपोर्ट कार्ड साझा किए गए और मार्च 2022 में मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपयोग के लिए डीजीक्यूआई डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। इस डैशबोर्ड का उपयोग करके वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के लिए मंत्रालयों/विभागों की डेटा प्रणाली पर स्टेटस अपडेट एकत्र करने के लिए अप्रैल से जून 2022 के दौरान डीजीक्यूआई 2.0 कवायद का दूसरा दौर आयोजित किया गया। डीजीक्यूआई 2.0 के दूसरे दौर के निष्कर्षों सहित मसौदा रिपोर्ट अक्तूबर 2022 में मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा की गई।

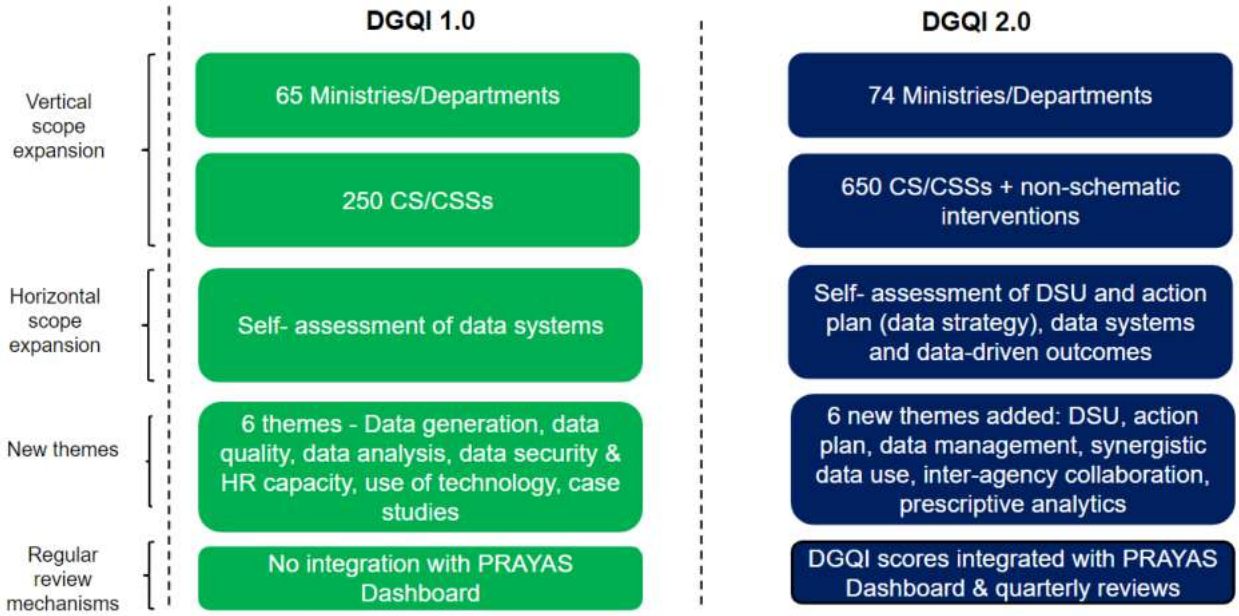

डीजीक्यूआई 1.0 की तुलना में डीजीक्यूआई 2.0 कवायद का परिष्कृत विस्तार

डीजीक्यूआई कवायद से प्राप्त सीखों का व्यापक रूप से प्रसार करने के उद्देश्य से डीएमईओ की वेबसाइट पर डीजीक्यूआई कार्यप्रणाली टूलकिट को प्रकाशित किया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया ताकि वे समान डेटा परिपक्वता आकलन करने में सक्षम हो सकें।

मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के बीच समकक्ष अधिगम को बढ़ावा देने के लिए डीएमईओ की वेबसाइट पर निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रशासनिक डेटा का उपयोग करने में अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह भी प्रकाशित किया गया।

अप्रैल 2022 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डीजीक्यूआई से प्राप्त प्रमुख जानकारियों पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। इसी प्रकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 180 परिवीक्षार्थियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।

मूल्यांकन को संस्थागत बनाना और बढ़ावा देना

डीएमईओ जून 2021 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनर्गठित विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) के व्यापक मार्गदर्शन में मूल्यांकन करता है। इस समिति के सदस्यों में नीति आयोग के सीईओ; वित्त सचिव, व्यय सचिव और ग्रामीण विकास सचिव; तथा 3 स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। डीईएसी द्वारा अनुमोदित आवर्ती मूल्यांकन योजना के अनुसार अध्ययन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, डीएमईओ मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर भी मूल्यांकन करता है और आवश्यकता के अनुसार अन्य मूल्यांकन/आकलन/समीक्षा भी करता है।

ऐसी योजनाओं का मूल्यांकन जिनके लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुरोध किया गया

डीएमईओ व्यय विभाग के अनुरोध के अनुसार कुछ मंत्रालयों से संबंधित एमएसएमई, वस्तु बोर्ड, पूर्वोत्तर का औद्योगीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चयनित केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययनों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। केंद्रीय क्षेत्र की इन योजनाओं के मूल्यांकन के लिए, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न परामर्शदाताओं/संस्थाओं को परामर्श कार्य सौंपा गया।

प्रमुख योजनाओं का मूल्यांकन

डीईएसी के अधिदेश के अनुसार, डीएमईओ सड़क, परिवहन, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का मूल्यांकन भी शुरू किया जा रहा है।

संगठन मूल्यांकन रूपरेखा

डीएमईओ प्रमुख संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का मूल्यांकन कर रहा है। इस संदर्भ में, डीएमईओ ने बड़े पैमाने पर आबादी को सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों की कारगरता में सुधार के उद्देश्य से एक संगठन मूल्यांकन रूपरेखा विकसित की है। उक्त रूपरेखा में किसी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसकी कारगरता (मिशन पूर्ति), दक्षता, सतत प्रासंगिकता (संगठन अपने वातावरण में बदलती परिस्थितियों के अनुसार किस हद तक अनुकूलन करता है) और वित्तीय व्यवहार्यता की दृष्टि से किया जाता है। ऐसे संगठनों से संबंधित परियोजनाओं का भी मूल्यांकन करना होता है। परियोजना स्तर के मूल्यांकन का उद्देश्य चुनौतियों, अंतरालों, सर्वोत्तम प्रथाओं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना है। यह मूल्यांकन परियोजना की डिजाइन और तार्किक रूपरेखा, प्रासंगिकता, कारगरता, दक्षता और परियोजनाओं की स्थिरता, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और परियोजना की सफलता में अन्य विभागों और एजेंसियों की भूमिका का आकलन करता है।

क्षमता निर्माण

डीएमईओ के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य दक्षता, कारगरता, समता, स्थिरता और परिणामों की प्राप्ति में सुधार लाने में मदद करके सरकारी नीति और कार्यक्रमों के सभी स्तरों पर निगरानी और मूल्यांकन के अनुप्रयोग को संस्थागत बनाना है। डीएमईओ पिछले वर्ष के दौरान केंद्रीय और राज्य स्तरों पर व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के निर्माण के लिए कई पहल कर रहा है। इन पहलों को सरकारी हितधारकों, वैश्विक विशेषज्ञों, थिंक टैंकों और शैक्षणिक संगठनों के साथ सहक्रियात्मक साझेदारी के माध्यम से समर्थन दिया जाता है।

राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की क्षमता का निर्माण

सहकारी संघवाद के लक्ष्य के अनुसरण में, डीएमईओ ज्ञान साझाकरण के साथ-साथ निगरानी और मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ रहा है। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के इस नेटवर्क के साथ आरंभिक साझेदारी का उद्देश्य महत्वपूर्ण लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का त्वरित क्षेत्र स्तरीय आकलन करना है।

क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ आशय पत्र (एसओआई)

डीएमईओ और सीबीसी ने अगस्त 2022 में सरकार की मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में मौलिक सुधार करके और भारत के 25 मिलियन सिविल सेवकों की क्षमता में वृद्धि करके भारतीय राज्यों की निष्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। सिविल सेवकों के लिए सीखने के इष्टतम अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एसओआई पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें निगरानी और मूल्यांकन के क्षेत्र में डीएमईओ और सीबीसी संयुक्त रूप से पाठ्यक्रम विकसित करेंगे। इसके अलावा, यह साझेदारी पूरे भारत में अधिकारियों के लिए मूल्यांकन एवं निगरानी की दक्षता रूपरेखा और मूल्यांकन एवं निगरानी की भूमिकाओं और गतिविधियों को विकसित करने की दिशा में काम करेगी।

ज्ञान का प्रसार

विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ इंटरएक्टिव ब्राउन बैग सत्र आयोजित किए गए :

- दुनिया के कार्बन उत्सर्जन की निगरानी में गेविन, क्लाइमेट ट्रेस कोएलिशन द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मदद कर रहे हैं, अप्रैल 2022
- गोंजालो हनडिज़ लिकोना, यूनिसेफ के लिए काम करने वाला देश अग्रणी मूल्यांकन विशेषज्ञ, द्वारा डिजाइन मूल्यांकन, अप्रैल 2022
- यूनिसेफ द्वारा बच्चों के लिए परिणामों की राष्ट्रीय डेटा प्रणालियां, मई 2022
- संतोष सिंह, साझेदार और प्रबंध निदेशक, जलवायु और कृषि समाधान, इंटेलकैप द्वारा कार्बन क्रेडिट की निगरानी और व्यापार को समझना, जुलाई 2022
- माइकल वूलकॉक, प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिक, विश्व बैंक विकास अनुसंधान समूह द्वारा समस्या पर आधारित पुनरावृत्त अनुकूलन, सितंबर 2022
- सौमेंद्र चट्टोपाध्याय, पूर्व अपर महानिदेशक, एनएसएसओ द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें दौर के सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर वेबिनार, मई 2022

डीएमईओ ने वार्षिक ग्लोकल मूल्यांकन सप्ताह जो वैश्विक मूल्यांकन पहल द्वारा संचालित वैश्विक निगरानी और मूल्यांकन ज्ञान साझाकरण गतिविधि है, के चौथे संस्करण में छह कार्यक्रमों की मेजबानी भी की। राज्य स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन की क्षमताओं के परिवर्तन के मार्गदर्शन के लिए सामूहिक सीख का लाभ उठाने के लिए, डीएमईओ ने अगस्त 2022 में 5वीं विकास भागीदार बैठक : राज्यों में निगरानी और मूल्यांकन क्षमताओं के परिवर्तन पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य डीएमईओ के विकास भागीदारों को डीएमईओ द्वारा संचालित की गई विभिन्न गतिविधियों की प्रगति से अवगत कराना और भारत में निगरानी और मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सहयोग के अवसरों को साझा करना था।

निष्पादन डैशबोर्ड

परिवर्तन के चैंपियन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम

रीयल-टाइम डेटा संग्रह और निगरानी के लिए परिवर्तन के चैंपियन डैशबोर्ड को 01 अप्रैल 2018 को जनता के देखने के लिए खोला गया। डैशबोर्ड का यह नाम जिलों की प्रगति में जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों और उनकी टीमों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए रखा गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नियमित रैंकिंग के माध्यम से 112 जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करने के लिए है, जो गतिशील है और हर महीने किए गए वृद्धिशील (डेल्टा) सुधार को दर्शाता है। डैशबोर्ड पर अद्यतन डेटा प्रविष्ट करने के लिए जिलों को अपने डेटा संग्रह और रखरखाव तंत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जिला प्रशासनों को डेटा संचालित शासन और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में और अधिक सशक्त बनाने के लिए परिवर्तन के चैंपियन पोर्टल (सीओसी 2.0) को अपग्रेड किया गया है। सीओसी 2.0 में कई नई विशेषताएं हैं जैसे कि नागरिक रिपोर्ट, नागरिक फीडबैक, एडवांस एनालिटिक्स, परियोजना प्रबंधन, जियो-स्पेशियल मैप और अन्य एआई/एमएल समाधान।

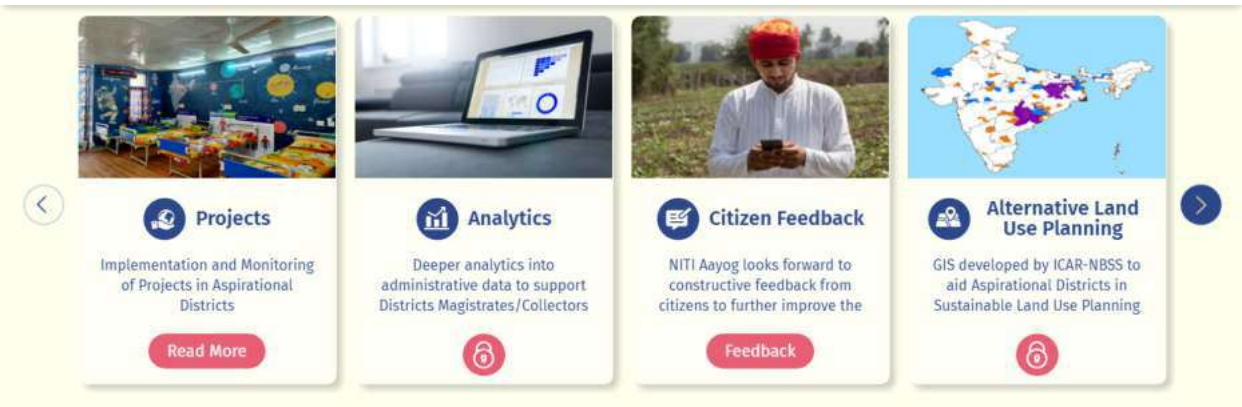

सीओसी डेटा के विश्लेषण के आधार पर नागरिक रिपोर्ट में 3 डैशबोर्ड शामिल हैं :

- स्थापना के बाद से आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन।
- जिलों की डेल्टा रैंकिंग जो प्रत्येक महीने जारी की जाती है।
- सभी जिलों के लिए सभी थीम में संकेतक स्तर की प्रगति।

इन रिपोर्टों के अलावा, सीओसी डेटा का उपयोग करके अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए जिला प्रशासन के पास डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल तक पहुंच है ताकि वे उन्नत विश्लेषण कर सकें।

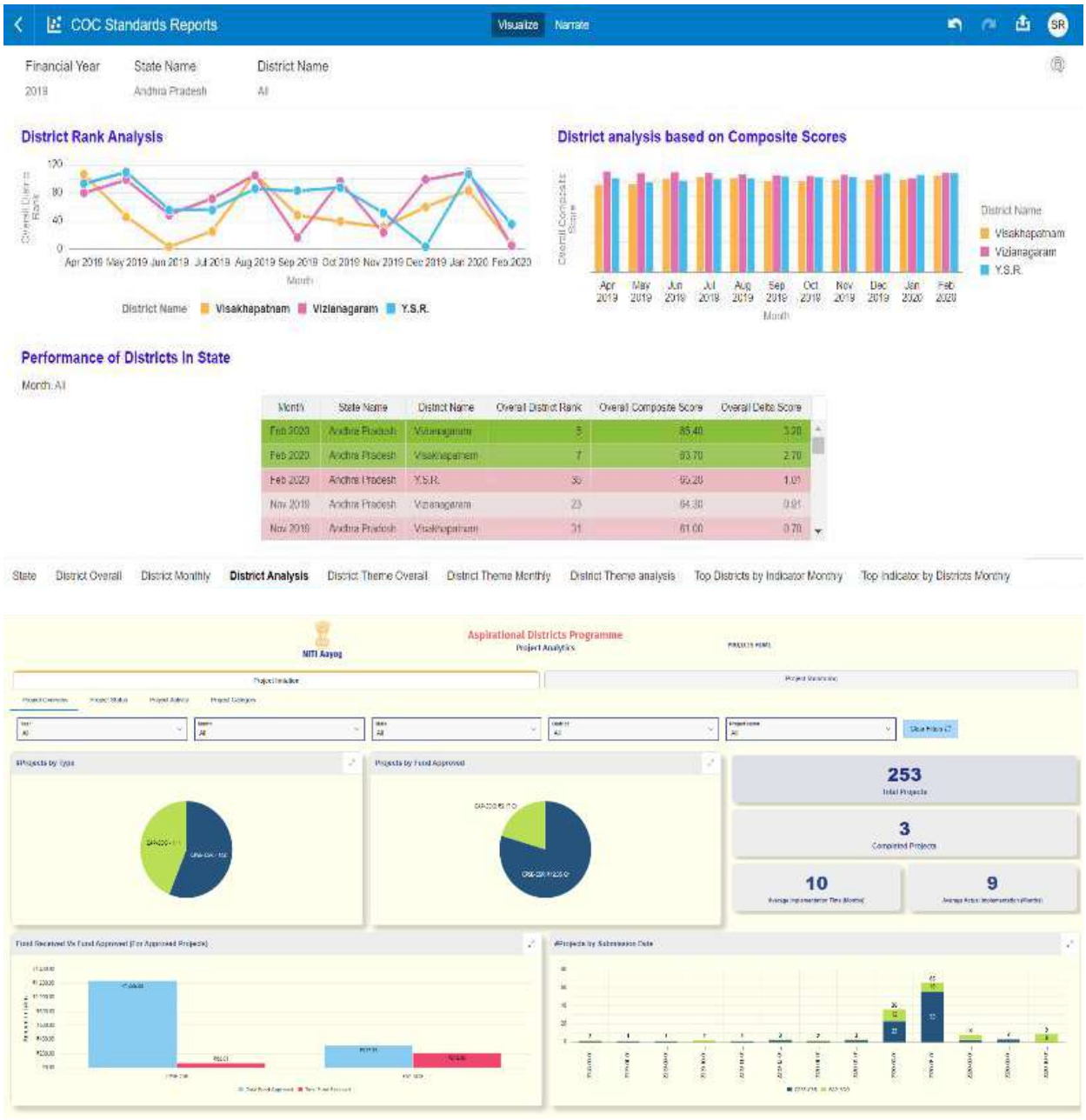

जिले राज्य के अन्य जिलों या सभी आकांक्षी जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं, अन्य डेटा स्रोतों जैसे कि एनएफएचएस, जनगणना और तीसरे पक्ष के सर्वेक्षण डेटा के साथ अपने विश्लेषण को त्रिकोणीय बना सकते हैं, और विश्लेषण के लिए ब्लॉक स्तर या ग्राम पंचायत स्तर के डेटा को भी अपलोड कर सकते हैं।

सीओसी 2.0 पूरी तरह से डिजिटलीकृत परियोजना प्रबंधन कार्य प्रवाह के साथ भी आता है। जिला प्राधिकारी नीति आयोग के बाहरी सहायता प्राप्त कार्यक्रम (ईएपी-एसडीजी) के तहत और सीपीएसई के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उन्नत परियोजना प्रबंधन प्रणाली प्रासंगिक परियोजनाएं तैयार करने में जिलों की सहायता करती है जो इन आकांक्षी जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती हैं। परियोजना प्रबंधन कार्य प्रवाह में न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ जिलों में परियोजनाओं के कार्यान्वियन के साथ-साथ निधियों के प्रवाह की निगरानी करने का भी प्रावधान है। जिलों में निगरानी रूपरेखा के अंग के रूप में परियोजना के पूरा होने और प्रभाव का समर्थन करने के लिए साक्ष्य के रूप में तस्वीरें अपलोड करने का प्रावधान है।

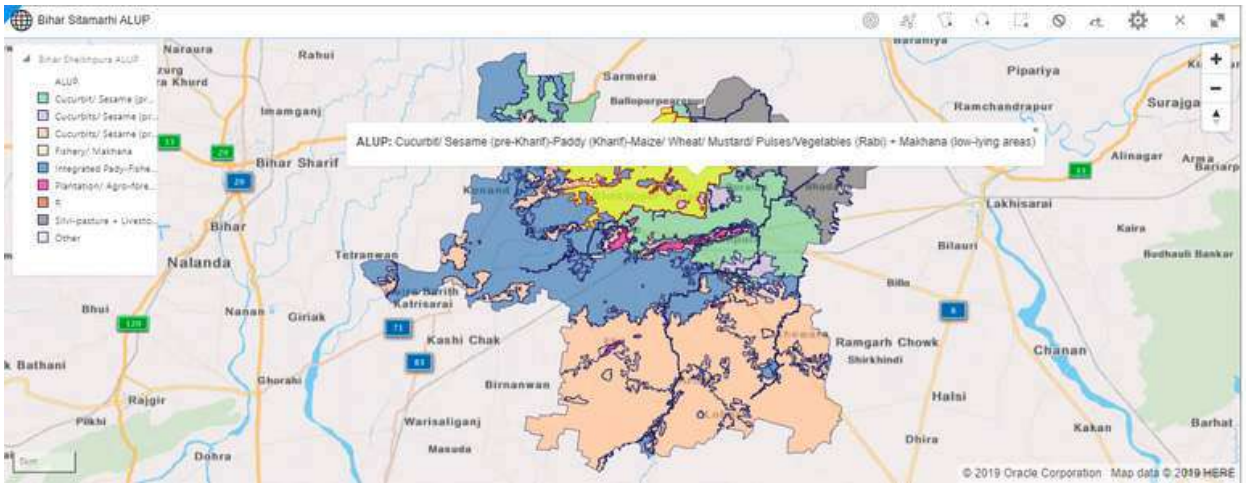

किसानों की आय में सुधार के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए, नीति आयोग ने टिकाऊ खेती और कृषि में प्रशासन का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के सहयोग से आकांक्षी जिलों की मैपिंग की। भू-स्थानिक विश्लेषिकी प्लेटफॉर्म (1) किसानों की आय में सुधार के लिए वैकल्पिक भूमि उपयोग योजना; जिले में फसल विविधीकरण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, और (2) मिट्टी के कटाव और प्रदूषण को कम करने के लिए मिट्टी और जल संरक्षण, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार और चेक डैम के संभावित स्थान प्रदान करने के लिए मैपिंग उपलब्ध कराता है।

इस नए प्लेटफॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक डेटा की गुणवत्ता और मासिक प्रदर्शन पर स्वचालित प्रणाली जनित मेलर्स है। सिस्टम में पहले से कॉन्फिगर किए गए लॉजिक्स के आधार पर जिलों को स्वचालित मेलर्स भेजे जाते हैं जिनमें उनके द्वारा प्रविष्ट किए गए डेटा में किसी भी तरह की विसंगतियों को उजागर किया जाता है। इससे कार्यक्रम की समग्र डेटा गुणवत्ता और तदनंतर जिलों के प्रदर्शन के विश्लेषण को बढ़ाने में मदद मिली है। जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों, केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों/राज्य प्रभारी अधिकारियों और राज्य के मुख्य सचिवों को भी प्रणाली जनित मासिक निष्पादन रिपोर्टें भेजी जाती हैं जिनमें विभिन्न संकेतकों पर उनके प्रदर्शन का विवरण होता है।

एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड

एसडीजी भारत सूचकांक डैशबोर्ड उपयोगकर्ताओं को एसडीजी भारत सूचकांक की रिपोर्टों में डेटा को देखने और अन्वेषण करने की अनुमति देता है। डैशबोर्ड को हर साल अपडेट किया जाता है–हर बार सूचकांक का एक नया संस्करण लॉन्च किया जाता है–और नीति निर्माताओं, नागरिक समाज, व्यवसाय जगत और शिक्षाविदों के लिए इसमें क्रॉस-सेक्टोरल प्रासंगिकता है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और एसडीजी शहरी सूचकांक के लिए दो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी विकसित किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः https://

sdgindiaindex.niti.gov.in/NER/dashboard/#/ और https://sdgindiaindex.niti.gov.in/urban/#/ पर अक्सेस किया जा सकता है।

सतत विकास लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सूचकांक

नीति आयोग ने अगस्त 2021 में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया जो इस तरह का पहला डैशबोर्ड है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 'वैश्विक से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से स्थानीय' के रूप में एसडीजी के स्थानीयकरण की दिशा में नीति आयोग के प्रयासों में एक और मील पत्थर है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित है, जो देश के विकास पथ के लिए काफी महत्व रखता है। यह सूचकांक पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों को सतत विकास लक्ष्यों और उनसे संबंधित लक्ष्यों पर उनके सापेक्षिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करता है। एक संवादात्मक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया ताकि प्रयोक्ता एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट में डेटा समन्वेषण कर सकें। यह डैशबोर्ड क्षेत्र स्तरीय और जिला स्तरीय अंतर्दृष्टि के लिए अनुमति देता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक के डेटा से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि निकालने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।

सूचकांक और आगामी कार्यप्रणाली का निर्माण एसडीजी पर जिलों के प्रदर्शन को मापने और उनकी रैंकिंग करने के मुख्य उद्देश्यों का प्रतीक है। यह अधिक ध्यान देने की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अंतरालों की पहचान करने में राज्यों का समर्थन करने; सांख्यिकीय और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने; और उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का इरादा रखता है।

सूचकांक की गणना करते समय, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड के संकेतकों और गणना पद्धति के चयन से संबंधित सभी पहलुओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों से परामर्श करने की व्यापक प्रक्रिया का पालन किया गया। राज्यों ने स्थानीय अंतर्दृष्टि और फील्ड के अनुभव के साथ फीडबैक प्रक्रिया को समृद्ध करके सूचकांक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अगला संस्करण यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र एसडीजी सूचकांक 2.0 प्रगति पर है।

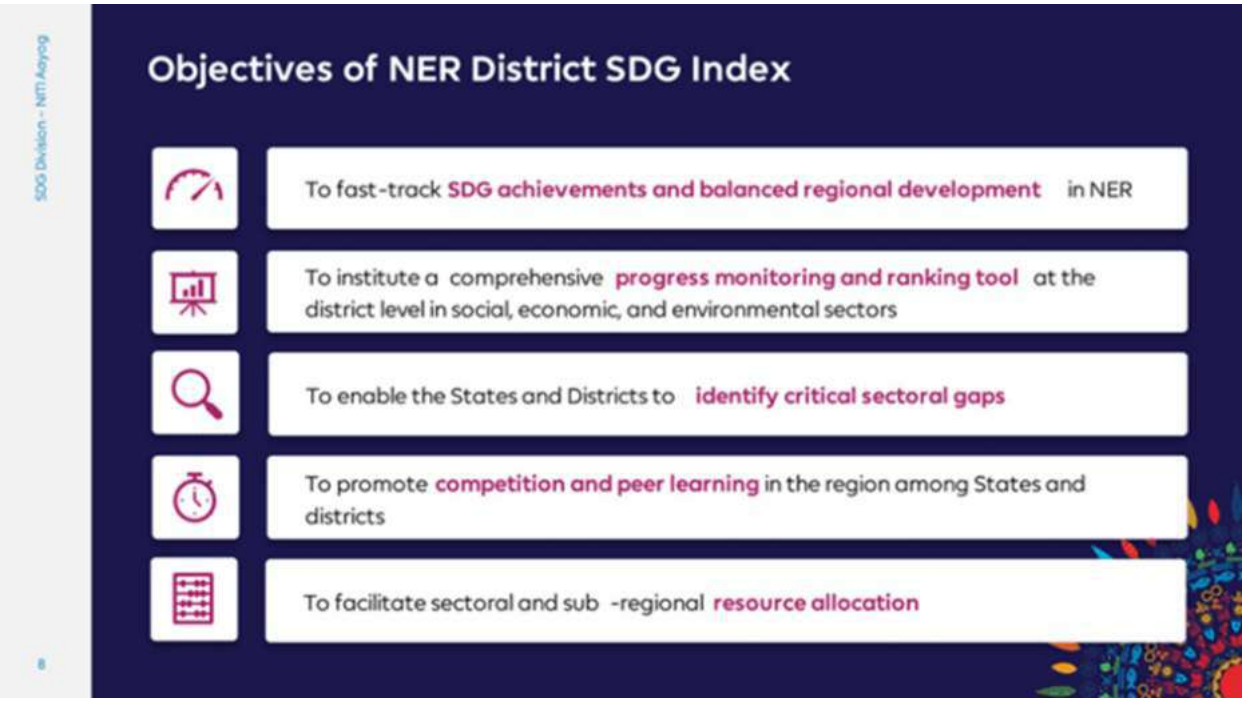

सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक

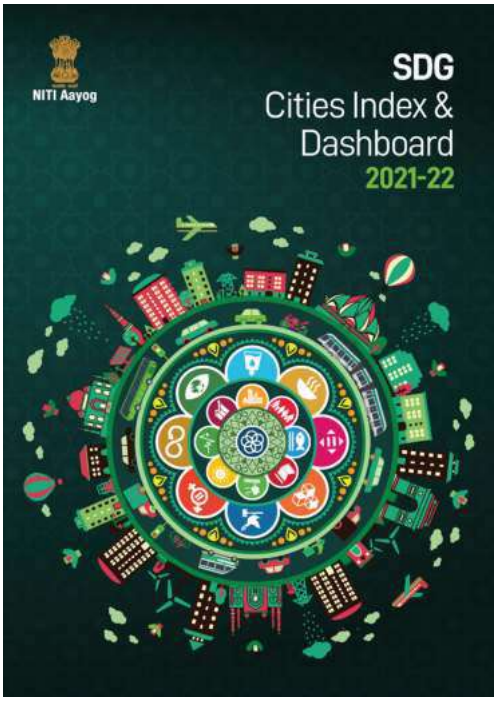

एसडीजी शहरी सूचकांक भारत-जर्मनी विकास सहयोग की छत्रछाया में भारतीय शहरों में एसडीजी के स्थानीयकरण का मार्ग प्रशस्त करने पर केंद्रित नीति आयोग–जीआईजेड और बीएमजेड सहयोग का परिणाम है। यह सूचकांक एसडीजी रूपरेखा के 46 टार्गेट में 77 एसडीजी संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। सूचकांक और डैशबोर्ड एसडीजी के स्थानीयकरण को मजबूत करने और शहर के स्तर पर एसडीजी की मजबूत निगरानी आरंभ करने के लिए हैं। यह यूएलबी स्तर के डेटा, निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम की ताकत और अंतराल पर प्रकाश डालता है। शहरी सूचकांक का अगला संस्करण प्रगति पर है।

वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक (जीआईआरजी)

वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक (जीआईआरजी) पहल सामाजिक, आर्थिक और विकास क्षेत्रों में विवेचनात्मक और महत्वपूर्ण संकेतकों में प्रदर्शन और सुधारों को प्रेरित करने पर केंद्रित है। जीआईआरजी के तहत निगरानी के लिए चुने गए 30 वैश्विक सूचकांक (जीआई), जो 21 अद्वितीय वैश्विक एजेंसियों (प्रकाशन एजेंसियों) द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, देश की धारणाओं और अपने-अपने क्षेत्रों में अन्य देशों के बीच सापेक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।

ये 30 सूचकांक 19 नोडल मंत्रालयों/विभागों (एम/डी) को आवंटित किए गए हैं, जिन्हें 46 संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाना है। इसके अलावा, जीआईआरजी को संचालित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को शामिल किया गया है।

इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने और संचालित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ाव के लिए ज्ञान साझेदार और समन्वयक के रूप में नीति आयोग के डीएमईओ को जीआईआरजी पहल सौंपी गई। 28 वैश्विक सूचकांकों के लिए नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव/मंत्रिमंडल सचिव समन्वय/सीईओ, नीति आयोग के स्तर पर जीआईआरजी पहल की लगातार समीक्षा की जाती है।

भारत जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 (आईसीईडी 3.0)

नीति आयोग ने कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से अप्रैल 2021 में भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0 (आईईडी 2.0) विकसित और लॉन्च किया। आईईडी की अगली पुनरावृत्ति को भारत जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 (आईसीईडी 3.0) के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह इंटरेक्टिव एनडीसी ट्रैकिंग, गैर जीवाश्म ईंधन शेयर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी कई सुविधाओं के साथ अपनी तरह का एक अनूठा मंच बनने जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि आईसीईडी देश में ऊर्जा डेटा के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। आईसीईडी 3.0 पर उपलब्ध कराए जा रहे डेटा में आपूर्ति और मांग, जलवायु, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी शामिल हैं। आईसीईडी 3.0 में एक विश्लेषणात्मक इंजन भी होगा जो पोर्टल पर उपलब्ध समृद्ध डेटा का विश्लेषण करने में उपयोगकर्ताओं की मदद करेगा।

भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 (आईईएसएस 2047)

भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईईएसएस) स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की योजना बनाने में सहायता के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित एक एक्सेल आधारित परिदृश्य नियोजन उपकरण है। 2016 में लॉन्च किए गए उपकरण के दूसरे संस्करण को अब आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर संशोधित किया जा रहा है ताकि इसमें शामिल किया जा सके : (i) आधार वर्ष को 2019-20 तक अद्यतन करना (ii) मॉडल में ग्रीन हाइड्रोजन, सीसीयूएस और कोयला गैसीकरण को शामिल करना (iii) आवासीय भवन क्षेत्र के लिए अद्यतन पद्धति (iv) आईईएसएस संस्करण 02 में उपयोग की गई विभिन्न गणनाओं का स्वचालन (v) मांग और जीडीपी लिंकेज (vi) पांच साल के अनुमानों के बजाय 2047 तक वार्षिक अनुमानों के लिए प्रावधान और (vi) ग्रिड संतुलन के एल्गोरिदम का कार्यान्वयन।

प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सूचकांक

स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई 2.0)

नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) का उद्देश्य चिन्हित किए गए संकेतकों के आधार पर स्कूल शिक्षा के परिणामों (पहुंच, समता, सीखने के परिणाम) और शासन पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का आकलन करना है। ये संकेतक काफी हद तक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस, 2017, 2021) और यू-डीआईएसई (2016-17, 2020-21) के आंकड़ों पर आधारित हैं, साथ ही कुछ संकेतकों के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डेटा प्रदान किया जाता है।

नीति आयोग द्वारा एसईक्यूआई का पहला संस्करण सितंबर 2019 में जारी किया गया जो एनएएस 2017 के सीखने के परिणामों के आंकड़ों पर आधारित था। इस वर्ष जारी किए गए एनएएस (2021) के अगले दौर के साथ, वर्टिकल एसईक्यूआई के अगले संस्करण यानी एसईक्यूआई 2.0 के लिए काम कर रहा है। इस संदर्भ में, क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं के बाद, वर्टिकल ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संकेतकों के लिए भरे गए डेटा के संबंध में डेटा सफाई का कार्य पूरा किया है। सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ

डेटा सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है और यह कार्य डेटा सत्यापन और डेटा प्रमाणन के अगले चरण में चला गया है। प्रतियोगिता संस्थान तीसरा पक्ष है जो डेटा सत्यापन का कार्य कर रहा है।

इसके साथ-साथ प्रतियोगिता संस्थान के समर्थन से वर्टिकल एसईक्यूआई 2.0 के लिए एसईक्यूआई पोर्टल और वेबसाइट पर तकनीकी विकास को देख रहा है।

राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक : चक्र 1

नीति आयोग ने एक राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक (एसईसीआई) चक्र 1 का विकास किया है, जो छह मापदंडों अर्थात (1) डिस्कॉम का प्रदर्शन (2) ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता और विश्वसनीयता, (3) स्वच्छ ऊर्जा पहल, (4) ऊर्जा दक्षता, (5) पर्यावरणीय स्थिरता, और (6) नई पहल पर राज्यों के प्रदर्शन को रैंक प्रदान करता है। इस सूचकांक में 27 संकेतक हैं। समग्र संयुक्त स्कोर के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है : बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के रूप में आकार और भौगोलिक अंतर के आधार पर फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट्स।

पहले संस्करण में, जो 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित है, गुजरात, केरल और पंजाब को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष तीन परफार्मर के रूप में रैंक प्रदान की गई है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा, इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़, दिल्ली और दमन और दीव/दादरा और नगर हवेली शीर्ष परफार्मर हैं।

राज्यों की विस्तृत प्रोफाइल और स्कोरकार्ड को रिपोर्ट में शामिल किया गया है जो विभिन्न मापदंडों पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का एक व्यापक स्नैपशॉट प्रदान करता है। नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक–चक्र 1 लॉन्च किया।

वैश्विक नवाचार सूचकांक

नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में नीति आयोग द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) पर डेटा/इनपुट को अपडेट करने की प्रगति की निगरानी करती है और जीआईआई में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए कार्रवाइयों का सुझाव देती है।

भारत नवाचार सूचकांक

नीति आयोग में एसएंडटी वर्टिकल ज्ञान साझेदार के रूप में प्रतियोगिता संस्थान के समन्वय से हर साल भारत नवाचार सूचकांक जारी करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की नवाचारी क्षमता के आधार पर उनकी रैंकिंग करने के लिए जिम्मेदार है।

नीति आयोग ने 21 जुलाई 2022 को भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया। भारत नवाचार सूचकांक 2021 की रूपरेखा को संशोधित किया गया तथा संकेतकों की संख्या भारत नवाचार सूचकांक 2020 में 36 से बढ़ाकर 89 कर दी गई ताकि पहले से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के 80 संकेतकों के साथ इनका मिलान किया जा सके। यह सूचकांक राज्यों के नवाचारी प्रदर्शन का बेहतर मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है और भविष्य में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को नीतिगत समाधान और सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सहकारी संघवाद को फिर से जीवंत करने के अपने प्रयास के भाग के रूप में नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक में रैंकिंग में सुधार के लिए भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मदद प्रदान कर रहा है। राज्य स्तर पर नवाचार प्रदर्शन में विकास और सुधार के परिणामस्वरूप वैश्विक नवाचार सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग में सुधार होगा।

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक : चक्र V

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से तथा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से नीति आयोग ने अनेक प्रकार के संकेतकों जैसे कि स्वास्थ्य परिणाम, शासन एवं प्रक्रियाओं पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए 2017 से स्वास्थ्य सूचकांक पहल की अगुवाई कर रहा है। इस सूचकांक का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्रवाई की दिशा में राज्यों को टहोकना है। नीति आयोग बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वार्षिक व्यवस्थित उपकरण के रूप में स्वास्थ्य सूचकांक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहनों से सूचकांक को जोड़ने के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के फैसले से इस उपकरण के महत्व को फिर से बल मिला है। यह बजट खर्च करने और इनपुट के बजाय आउटपुट और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक रहा है। दिसंबर 2021 में चक्र IV के लिए सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई; चक्र V की रिपोर्ट जारी होने के अंतिम चरण में है।

जिला अस्पताल सूचकांक : चक्र II

नीति आयोग ने जिला अस्पतालों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ घनिष्ठ सहयोग और डब्ल्यूएचओ इंडिया तथा अन्य हितधारकों के तकनीकी सहयोग से एक रूपरेखा विकसित की है। पहले चक्र में, वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के डेटा के आधार पर 'संरचना' और 'आउटपुट' के क्षेत्र में 10 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) पर देश भर के 707 जिला अस्पतालों का मूल्यांकन किया गया। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालों की पहचान की गई और उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को एकत्र किया गया और 'जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाएं' शीर्षक वाली रिपोर्ट में प्रलेखित किया गया।

नीति आयोग ने जिला अस्पताल सूचकांक के दूसरे चक्र की शुरुआत कर दी है, जिसमें संरचना, प्रक्रिया, आउटपुट और परिणाम जैसे क्षेत्रों को शामिल करत हुए 17 केपीआई पर जिला अस्पतालों (मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को छोड़कर) के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रदर्शन का आकलन मुख्य रूप से एचएमआईएस के डेटा के आधार पर किया जाएगा। सुविधा के एचएमआईएस डेटा की तुलना में उनके संबंधित भौतिक रिकॉर्डों के डेटा सत्यापन का कार्य एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी को सौंपा गया है। यह कुल जिला अस्पतालों के लगभग 10 प्रतिशत प्रतिनिधि नमूने के लिए किया जा रहा है, जिसके बाद देश भर के जिला अस्पतालों को शामिल करते हुए सूचकांक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

मिश्रित जल प्रबंधन सूचकांक 3.0 और 4.0

मिश्रित जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) प्रभावी जल प्रबंधन और अभिशासन में भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का आकलन करता है। यह कार्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ 2016-17 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है और इसके अब तक दो संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। वास्तव में नवीनतम संस्करण में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः सूचकांक 3.0 और 4.0 के दो सेट शामिल हैं। यह सूचकांक सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धा की क्षमताओं को संयोजित करता है जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र डेटा संग्रह, विश्लेषण और चर्चा में सीधे शामिल होते हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखते हैं।

निर्यात तत्परता सूचकांक 2022

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की निर्यात तत्परता और निष्पादन के आधार पर उनको रैंक प्रदान करने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रतियोगिता संस्थान के सहयोग से निर्यात तत्परता सूचकांक (ईपीआई) विकसित

किया गया है। ईपीआई चार स्तंभों अर्थात निर्यात नीति, व्यवसाय परिवेश, निर्यात अवसंरचना और निर्यात निष्पादन पर आधारित है। ईपीआई के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- भारतीय राज्यों की निर्यात संबंधी तत्परता एवं निष्पादन की जांच करना
- राज्य स्तर पर चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करना
- निर्यात निष्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख अंतर्दृष्टि प्रदान करना
- सुगमताकारी विनियामक रूपरेखा को प्रोत्साहित करना

अपने समकक्षों के विरुद्ध अपने निष्पादन की बेंचमार्किंग करने तथा उप राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात द्वारा संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीति तंत्रों का विकास करने के लिए संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ईपीआई का प्रयोग किया जा सकता है। यह सूचकांक निर्यात के भावी अवसरों की उनकी समझ को बेहतर करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि एवं इनपुट भी प्रदान करेगा।

ईपीआई 2020 की सफलता के बाद मार्च 2022 में निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। ईपीआई का तीसरा संस्करण तैयार किया जा रहा है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) गैर मौद्रिक गरीबी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परिवार स्तरीय हाई रिजोल्यूशन मापदंड है जिसमें 100 से अधिक विकासशील देशों को शामिल किया गया है। यह 3 आयामों यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर और 10 संकेतकों में परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों को दर्शाता है। राष्ट्रीय एमपीआई परियोजना का उद्देश्य वैश्विक एमपीआई का विखंडन करना और वैश्विक एमपीआई की रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के बड़े लक्ष्य के साथ सुधार हेतु कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए विश्व स्तर पर संरेखित लेकिन अनुकूलित भारतीय एमपीआई का निर्माण करना है। यह 12 संकेतकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों में परिवार द्वारा सामना किए जाने वाले अभाव को दर्शाता है और इसमें मातृत्व स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाने वाले 2 अतिरिक्त संकेतक शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय एमपीआई की बेसलाइन रिपोर्ट एनएफएचएस-4 (2015-16) पर आधारित है और बेसलाइन पर यानी आवास, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने के ईंधन, पोषण आदि पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योजनाओं के बड़े पैमाने पर रोलआउट से पहले स्थिति को मापने के लिए एक उपयोगी स्रोत के रूप में कार्य करती है। इससे एनएफएचएस-5 (2019-20) की तुलना में समय के साथ परिवर्तनों को मापने में मदद मिलेगी। अनुकूलित राष्ट्रीय एमपीआई का उद्देश्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को नाना प्रकार के कारकों को समझने का अवसर प्रदान करना है जो विकास में रुकावट पैदा कर रहे हैं तथा हस्तक्षेपों को अधिक कारगर एवं टिकाऊ बनाने में उनकी मदद करना है। राष्ट्रीय एमपीआई के कुल गणना अनुपात और तीव्रता के अनुमान न केवल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बल्कि सभी जिलों के लिए भी तैयार किए गए हैं, जो रिपोर्ट की एक अनूठी विशेषता है। यह न केवल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक और सापेक्षिक प्रदर्शन के विश्लेषण को सक्षम करेगा बल्कि राज्यों को अपने जिलों का तुलनात्मक विश्लेषण करने में भी सक्षम करेगा और इस प्रकार क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करेगा।

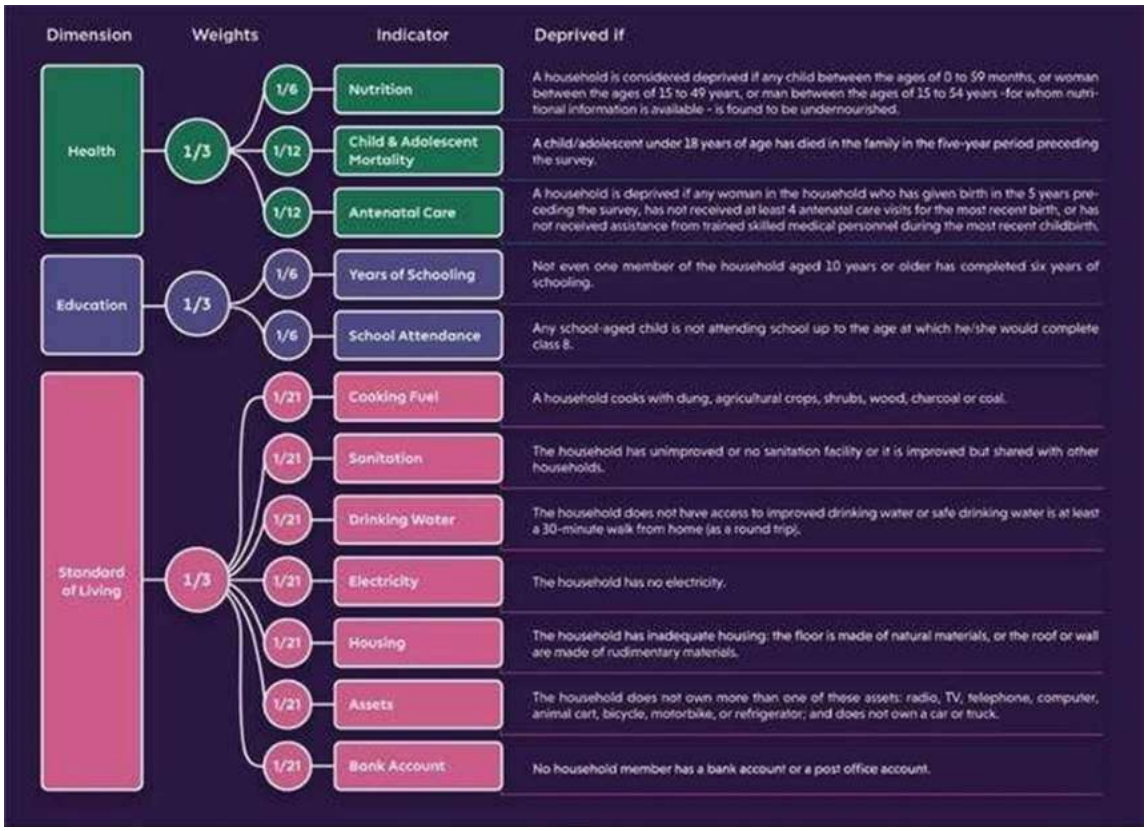

इसके अलावा, प्राथमिकता के संकेतकों की पहचान करने तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी की जिद्दी चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधार हेतु कार्य योजनाओं का विकास करने का कार्य अंतर्मंत्रालयी एमपीआई समन्वय समिति (एमपीआईसीसी) द्वारा किया जाता है, जिसके 12 मंत्रालय सदस्य हैं और नीति आयोग इसका संयोजक है। एनएफएचएस-5 के आधार पर रिपोर्ट का अगला संस्करण तैयार किया जा रहा है।

एमपीआई समन्वय समिति

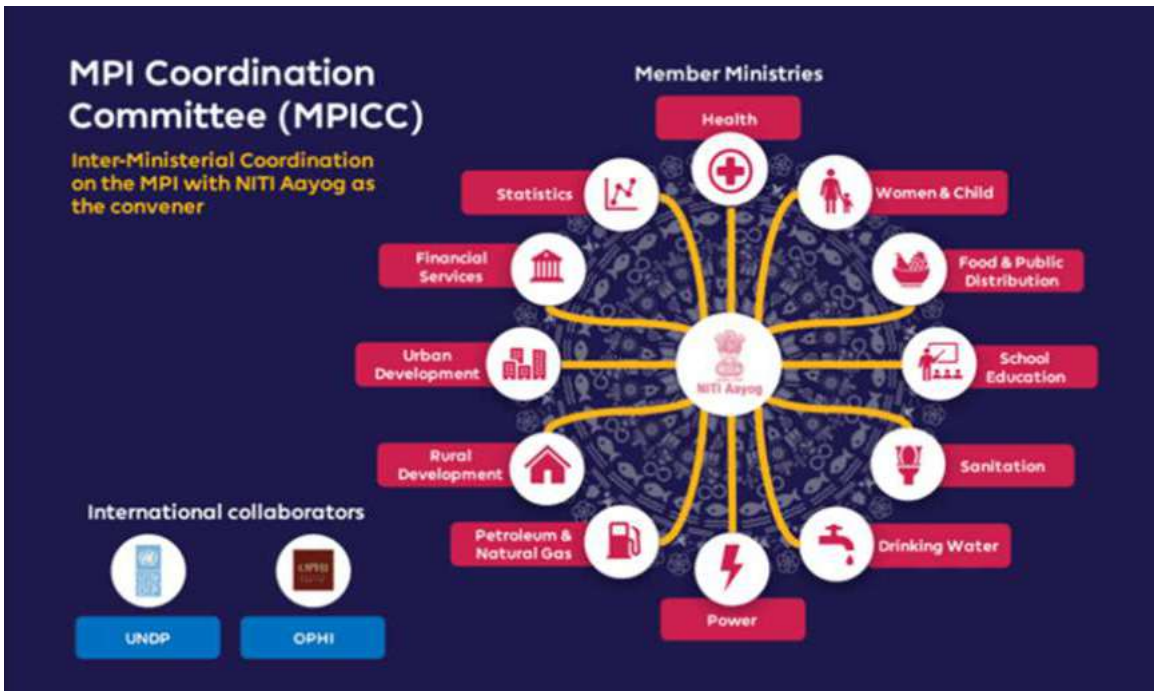

सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का व्यापक दस्तावेजीकरण और रैंकिंग कर रहा है।

एसडीजी इंडिया इंडैक्स डैशबोर्ड 2020-21

यह सूचकांक महत्वपूर्ण अंतरालों की पहचान करने में मदद करता है तथा राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति के लिए हस्तक्षेपों के बारे में सूचित करता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर, आर्थिक विकास, संस्थानों, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण आदि पर वैश्विक लक्ष्यों के विस्तृत सेट पर प्रगति का आकलन करने के लिए एक रेडी रेकनर के रूप में कार्य करता है।

लक्ष्यों और संकेतकों के व्यापक कवरेज के कारण एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 पिछले संस्करणों की तुलना में अधिक मजबूत था। 115 संकेतक लक्ष्य 17 के गुणात्मक मूल्यांकन के साथ 17 एसडीजी में से 16 को शामिल करते हैं और एसडीजी के 70 लक्ष्यों को कवर करते हैं। यह सूचकांक 2018-19 और 2019–20 के संस्करणों की तुलना में एक सुधार है, जिनमें क्रमश: 39 टार्गेट और 13 लक्ष्यों में 62 संकेतकों और 54 टार्गेट और 16 लक्ष्यों में 100 संकेतकों का उपयोग किया गया था।

लक्ष्यों और संकेतकों के और भी व्यापक कवरेज के साथ अगला संस्करण तैयार किया जा रहा है।

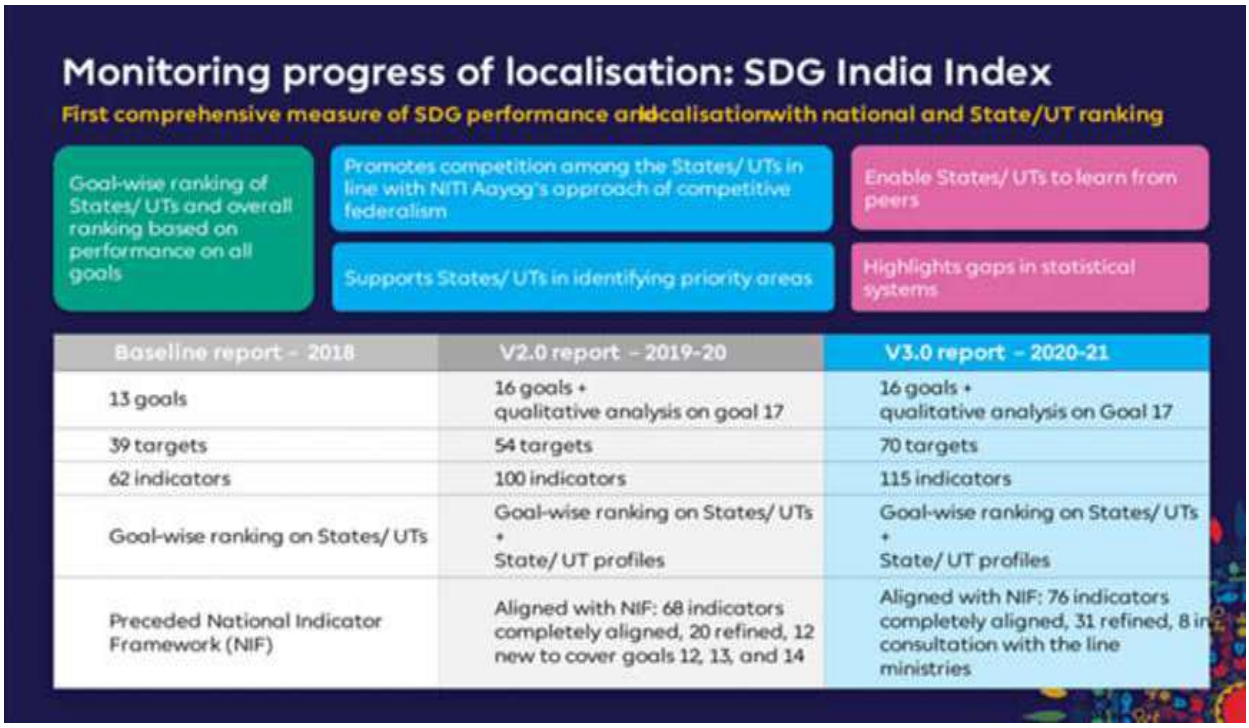

एसडीजी इंडिया इंडैक्स की यात्रा

ERECTED TO COMMEMORATE THE LANDING
IN INDIA OF THEIR IMPERIAL MAJESTIES
KING GEORGE VI AND QUEEN MARY
ON THE SECOND OF DECEMBER MCMXI

खंड

04

सहकारी संघवाद

प्रस्तावना

मजबूत राज्य मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राज्य सहायता मिशन 2047, जब भारत अपनी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मना रहा होगा, के लिए परिकल्पित परिवर्तनकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अपने सतत जुड़ाव को और अधिक संरचित और संस्थागत तरीके से फिर से मजबूत करने के लिए नीति आयोग की एक व्यापक पहल है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में तीन 'रोल मॉडल' राज्यों के निर्माण के लिए साथ-ई परियोजना यानी 'मानव पूंजी के बदलाव के लिए टिकाऊ कार्रवाई-शिक्षा' शुरू की गई। इसके अलावा, विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष कदम उठाए हैं जिनके लिए विशेष ध्यान एवं सहायता की आवश्यकता है, जैसे कि पूर्वोत्तर के राज्य, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह एवं हिमालयन राज्य।

राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)

नीति आयोग सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को सक्रिय करके 2047 में विकसित भारत की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी करना चाहता है। इसके लिए, अधिक संरचित और संस्थागत तरीके से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अपने सतत जुड़ाव को फिर से मजबूत करने के लिए नीति आयोग की व्यापक पहल के रूप में राज्य सहायता मिशन की कल्पना की गई है। इस मिशन के तहत, नीति आयोग समावेशी विकास की रणनीतियों का विकास करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रहा है ताकि वे अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और राज्य परिवर्तन संस्थान (एसआईटी) की स्थापना कर सकें। ये राज्य परिवर्तन संस्थान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक रणनीतियों के विकास का मार्गदर्शन करेंगे। राज्य/

संघ राज्य क्षेत्र नीति आयोग के सहयोग से एसआईटी स्थापित करने का विकल्प चुन सकते हैं या नियोजन विभागों और बोर्डों जैसे अपने मौजूदा संस्थानों की भूमिका की फिर से कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा, यह मिशन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र सहायता प्रदान करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य विजन का विकास करना, उनके आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण करना, मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना और नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना शामिल है। यह मिशन राज्यों के विजन को लागू करने में उनकी सहायता करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, विकास भागीदारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और नागरिक समाजों की विशेषज्ञता का लाभ भी उठाना चाहता है।

नीति आयोग पहले ही अपने-अपने राज्यों में एसआईटी स्थापित करने की वकालत करने के लिए सभी राज्यों से संपर्क कर चुका है। कुछ राज्यों ने एसआईटी की स्थापना की घोषणा की है, जिसमें कर्नाटक (कर्नाटक राज्य संस्थान परिवर्तन), महाराष्ट्र (मित्रा–महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान), उत्तर प्रदेश (एसटीसी–राज्य परिवर्तन आयोग) और उत्तराखंड (एसईटीयू–राज्य सशक्तिकरण और उत्तराखंड परिवर्तन संस्थान) शामिल हैं। नीति आयोग को राजस्थान, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और नागालैंड जैसे राज्यों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें राज्य विजन दस्तावेज और विकास रणनीति तैयार करने के लिए नीति आयोग से ज्ञान और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

एसएसएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नीति आयोग का जुड़ाव

उत्तर प्रदेश, 29 दिसम्बर 2022

मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन

माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार, मुख्य सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाना है। अब तक दो ऐसे तीन दिवसीय सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। यह सम्मेलन जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 15 से 17 जून, 2022 के दौरान धर्मशाला में आयोजित किया गया था जिसके आयोजन में नीति आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसमें सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधिनियों और डोमेन विशेषज्ञों के साथ 204 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, भारत सरकार के अन्य अधिकारियों, डोमेन विशेषज्ञों, मुख्य सचिवों/फील्ड पदाधिकारियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कई अन्य युवा अधिकारियों द्वारा किए गए पर्याप्त प्रयासों की परिणति था जिसमें छह महीने में विचार-विमर्श के 100 दौर शामिल थे। सम्मेलन में कवर किए गए प्रमुख विषयों और उनके उप विषयों में शामिल थे (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–स्कूल शिक्षा (ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–उच्च शिक्षा (iii) फसल विविधीकरण और तिलहन, दलहन और अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना (iv) शहरी अभिशासन। निम्नलिखित विषयों पर अतिरिक्त सत्र आयोजित किए गए थे–(i) भारत की विकास गाथा : राज्यों की भूमिका; (ii) आजादी का अमृत महोत्सव : 2047 का रोडमैप; (iii) आकांक्षी जिला कार्यक्रम; (iv) राजकोषीय प्रबंधन पर दृष्टिकोण : राज्यों की भूमिका। भोजनकाल के दौरान चार विषयों अर्थात (i) अनुपालन बोझ को कम करना और छोटे अपराधों का गैर अपराधीकरण; (ii) पीएम गति शक्ति के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे को बदलना; (iii) योजनाओं की संतृप्ति कवरेज प्राप्त करने और अंतिम व्यक्ति तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र राज्य समन्वय; और (iv) क्षमता निर्माण : आईजीओटी–मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन पर संकेंद्रित विचार-विमर्श आयोजित किया गया।

जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की आयोजन टीम के साथ माननीय प्रधानमंत्री

विचार-विमर्श से उभरे कार्रवाई योग्य बिंदुओं को कार्यवृत्त के रूप में तैयार किया गया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को संप्रेषित किया गया है। नीति आयोग में 20 जून 2022 को राष्ट्रीय मुख्य सचिव समन्वय प्रभाग के नाम से एक नए प्रभाग का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिव और नीति आयोग द्वारा कार्रवाई योग्य बिंदुओं की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन

यह सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनएएससी कॉम्प्लेक्स, आईसीएआर, पूसा, नई दिल्ली में 5 से 7 जनवरी, 2023 के दौरान आयोजित किया गया था जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 180 प्रतिभागियों के साथ-साथ चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों और बाहरी विशेषज्ञों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का व्यापक विषय 'विकसित भारत : अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना' था जिसके दो व्यापक स्तंभ अर्थात 'रोजगार सृजन के साथ विकास' और 'समावेशी मानव विकास' थे। चिन्हित किए गए छह विषयों अर्थात (i) एमएसएमई पर जोर; (ii) अवसंरचना और निवेश; (iii) कम से कम अनुपालन; (iv) महिला सशक्तिकरण; (v) स्वास्थ्य और पोषण; (vi) कौशल विकास के तहत आगे की राह का एक खाका विकसित करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर के दौरान केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिलकर व्यापक कार्य किया गया। नोडल मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विशेषज्ञों के बीच 150 से अधिक भौतिक और वर्चुअल परामर्श बैठकों का आयोजन किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार, मुख्य सम्मेलन से पहले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निम्नलिखित विषयों पर तीन वर्चुअल सम्मेलनों का आयोजन किया गया, अर्थात (i) विकास के आधार के रूप में जिले (ii) चक्रीय अर्थव्यवस्था; (iii) मॉडल संघ राज्य क्षेत्र।

सम्मेलन के दौरान, चिन्हित किए गए विषयों पर तीन विशेष सत्र आयोजित किए गए, अर्थात (i) विकसित भारत : अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना; (ii) माल और सेवा कर (जीएसटी) के पांच साल–सीख और अनुभव; (iii) वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया। दूसरे सम्मेलन के दौरान चार विषयों पर संकेंद्रित विचार-विमर्श का भी आयोजन किया गया, अर्थात (i) वोकल फॉर लोकल; (ii) अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष; (iii) जी-20 : राज्यों की भूमिका; और (iv) उभरती प्रौद्योगिकियां। इनमें से प्रत्येक सत्र के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया गया।

सम्मेलन को संस्थागत बनाने के लिए विकसित किए गए पोर्टल के माध्यम से नोडल मंत्रालयों और नीति आयोग द्वारा इनमें से प्रत्येक के तहत उभरने वाले कार्य बिंदुओं की निगरानी की जाएगी। इस पोर्टल को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और चुनिंदा केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अक्सेस किया जा सकता है और यह ज्ञान भंडार और निगरानी मंच के रूप में काम करेगा।

जनवरी 2023 में नई दिल्ली में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ माननीय प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्रियों/उप राज्यपालों के साथ बैठक

नीति आयोग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर आधार पर जुड़ाव के लिए समर्थन की संरचित पहलों और तंत्रों के माध्यम से अपने अधिदेश के हिस्से के रूप में सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इस पहल के हिस्से के रूप में, वर्टिकल द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर आधार पर बेहतर जुड़ाव के लिए एक कार्य योजना की परिकल्पना की गई, जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें और बातचीत करना शामिल है। इन बैठकों का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अंतर-क्षेत्रक और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच के रूप में काम करने था, जिसमें वे मुद्दे भी शामिल हैं जो राज्य सरकारों के विभागों और केंद्र सरकार के विभागों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यों और सीईओ द्वारा अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश नामक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आधिकारिक बातचीत का आयोजन किया गया। राज्य सहायता मिशन की स्थापना के लिए त्रिपुरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया।

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

द्वीपों का समग्र विकास

द्वीप समूहों के व्यापक विकास पर नजर रखने के लिए द्वीप समूह विकास एजेंसी (आईडीए) का गठन किया गया है। चिन्हित किए गए द्वीपों के समग्र विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है और नीति आयोग को इस प्रक्रिया का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के परामर्श से सतत विकास के लिए शुरूआती तौर पर दस द्वीपों यानी अंडमान और निकोबार में एवेस, लॉन्ग, लिटिल अंडमान, स्मिथ और रॉस और लक्षद्वीप में बंगारम, चेरियाम, मिनिकॉय, सुहेली और थिन्नाकारा को चिन्हित किया गया था।

अंडमान और निकोबार के चार द्वीपों और लक्षद्वीप के सभी चिन्हित द्वीपों के लिए विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में पर्यटन, द्वीपों में पैदा होने वाले समुद्री भोजन और नारियल उत्पादों के निर्यात, उच्च मूल्य वाली फसलों की जैविक खेती और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ शामिल हैं। इस क्षेत्र में पारिस्थितिकीय स्थिरता को बनाए रखते हुए नियोजित परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से द्वीपवासियों के लिए संतोषजनक नौकरियों के सृजन और अतिरिक्त आय के सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

पहले चरण की परियोजनाओं की सफलता को दोहराने के लिए, दूसरे चरण में समग्र विकास के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्यारह और स्थलों/द्वीपों और लक्षद्वीप के पांच द्वीपों की पहचान की गई। मास्टर प्लान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। कोल्ड स्टोरेज परियोजना, मछली प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, वेब कनेक्टिविटी में सुधार, अवसंरचना कनेक्टिविटी विकसित करना, स्वच्छ और हरित ऊर्जा नीतियां जैसी कुछ प्रमुख पहलें शुरू की जा रही हैं।

भारतीय हिमालयन क्षेत्र का संधारणीय विकास

भारतीय हिमालयन क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल) में फैला हुआ है, जिसका फैलाव 2500 किमी तक है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 50 मिलियन है, जहां विविध जनसांख्यिकीय और बहुमुखी आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियां पाई जाती हैं।

भारतीय हिमालयन केंद्रीय विश्वविद्यालय संघ

नीति आयोग ने इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हिमालयन राज्य क्षेत्रीय परिषद के तहत भारतीय हिमालयन केंद्रीय विश्वविद्यालय संघ (आईएचसीयूसी) का गठन किया जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का एक समूह है। आईएचसीयूसी और सीएसआईआर–आईएचबीटी (हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान) को निम्नलिखित पांच विषयगत क्षेत्रों पर काम करने के लिए कहा गया :

- पहाड़ों में महिला श्रम के आर्थिक प्रभाव की गणना एवं मूल्यांकन
- विपणन पर विशेष बल के साथ हिमालयन राज्यों में कृषि पारिस्थितिकी
- पहाड़ों में पर्यावरण हितैषी एवं लागत प्रभावी पर्यटन का विकास
- पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए आजीविका के अवसर
- जल संरक्षण एवं संचयन की रणनीतियां

सार्वजनिक डोमेन में जारी करने के लिए उपरोक्त पांच विषयगत क्षेत्रों पर रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नीति मंच

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में सतत आर्थिक विकास के लिए पेश आ रही चुनौतियों का समाधान करने और अपेक्षित हस्तक्षेप की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री की सह अध्यक्षता में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए नीति मंच की स्थापना की गई है।

नीति मंच द्वारा पांच क्षेत्रों यानी बांस, डेयरी, मछली पालन, चाय और पर्यटन की पहचान की गई है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नीति मंच की सिफारिशों के कार्यान्वियन को आगे बढ़ाने के लिए, नीति आयोग द्वारा सितंबर 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। जेडब्ल्यूजी की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं। जेडब्ल्यूजी की चौथी बैठक 25 अप्रैल, 2022 को हुई थी। जेडब्ल्यूजी ने संबंधित मंत्रालयों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नीति मंच द्वारा अनुशंसित पांच क्षेत्रों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मत्स्य विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में 12 जनवरी 2022 को सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अलग बैठक भी आयोजित की गई।

क्षेत्र का दौरा और परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन

नीति आयोग द्वारा 2021-22 के पूंजीगत व्यय के लिए सिक्किम राज्य को विशेष सहायता योजना के तहत परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया। 6 से 10 फरवरी 2022 के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थित आठ परियोजनाओं का दौरा किया गया और प्रगति का जायजा लिया गया।

एनई वर्टिकल ने 20 से 24 अप्रैल 2022 के दौरान फसलों को सूखे से हुई क्षति/हानि के आकलन के लिए नागालैंड में एक व्यापक फील्ड विजिट में भाग लिया। पांच जिलों अर्थात वोखा, दीमापुर, पेरेन, निउलैंड और

चुक्मुकेदिमा का सर्वेक्षण किया गया और 'नागालैंड में गंभीर सूखे के कारण हुए नुकसान पर अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की रिपोर्ट, 2021' शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट को विचार के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति (एससी–एनईसी) की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

पूर्वोत्तर राज्यों में अनुपालन बोझ को कम करना

एनई प्रभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समन्वय करने की पहल की और निजी निवेश को सुगम बनाने और आकर्षित करने, आजीविका निर्माण को सुगम बनाने और इस तरह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए निराधार अधिनियमों, कानूनों, फाइलिंग आदि जैसे अनुपालन बोझ में कमी को प्रोत्साहित किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित कई संचार के माध्यम से राज्यों में अनुपालन को कम करने और तर्कसंगत बनाने के लिए व्यक्तिगत ध्यान देने का अनुरोध किया गया। अनुपालन बोझ को कम करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिवों और पांच संबद्ध मंत्रालयों के सचिवों के साथ तीन बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

परियोजना साथ-ई

स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए तीन 'रोल मॉडल' राज्यों की पहचान और निर्माण के लिए 2017 में प्रोजेक्ट एसएटीएच-ई, 'मानव पूंजी के परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई–शिक्षा' शुरू किया गया। चयन की विस्तृत प्रक्रिया के बाद चुनौती विधि के माध्यम से झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश का चयन किया गया। साथ-ई का पहला चरण मई 2020 में पूरा हो गया; इस परियोजना ने 2.3 करोड़ छात्रों, 4.5 लाख शिक्षकों और 2.3 लाख सरकारी स्कूलों को प्रभावित किया।

परियोजना साथ के प्रमुख हस्तक्षेप

परियोजना साथ के प्रमुख हस्तक्षेप

इस परियोजना के तहत, सभी छात्रों के लिए ग्रेड स्तरीय दक्षता हासिल करने से जुड़ी अड़चनों की पहचान करने के लिए सभी तीन राज्यों में प्रणाली व्यापी विश्लेषण किया गया। परिणामत:, संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया गया। इस परियोजना के तहत छात्रों के स्तर पर लक्षित शिक्षण, प्रौद्योगिकी पर आधारित निगरानी प्रणाली, डेटा समर्थित समीक्षा प्रक्रियाएं, अनुकूलित शिक्षक प्रशिक्षण एवं मेंटरिंग सहायता आदि ऐसे कुछ हस्तक्षेप थे जिन्होंने सभी तीन राज्यों में काफी सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। परियोजना साथ ने स्कूल बाह्य बच्चों (ओओएससी), पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों तथा अधिगम के परिणामों पर विशिष्ट फोकस के साथ शिक्षा में पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से सफलता हासिल की है।

एसडीजी का स्थानीयकरण

ऐसी किसी रणनीति के लिए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण महत्वपूर्ण है जिसका उद्देश्य एजेंडा 2030 को प्राप्त करना है। वास्तव में, एसडीजी के स्थानीयकरण में संगत संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय से स्थानीय स्तरों तक एसडीजी को समझना, अनुकूलित करना, योजना बनाना, लागू करना तथा निगरानी करना शामिल होता है। इसमें संस्थागत तंत्र स्थापित करना, विजन दस्तावेज तैयार करना, योजनाओं और विभागों के साथ एसडीजी का मानचित्रण करना, राज्य/जिला और ब्लॉक संकेतक रूपरेखा का विकास करना, एसडीजी डैशबोर्ड का विकास करना, बजट को एसडीजी के साथ लिंक करना, अधिकारियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण में सीएसओ/सीएसआर को शामिल करना शामिल है।

नोडल एसडीजी के रूप में नीति आयोग

"स्थानीयकरण के भारतीय मॉडल" पर रिपोर्ट जुलाई 2022 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) में उपाध्यक्ष, नीति आयोग द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट एसडीजी के स्थानीयकरण में उप राष्ट्रीय अनुभवों को प्रलेखित करती है और इसकी सफलताओं और चुनौतियों सहित सीखे गए पाठों का विवरण प्रदान करती है।

एचएलपीएफ में 'स्थानीयकरण के भारतीय मॉडल' पर रिपोर्ट का विमोचन

एसडीजी के स्थानीयकरण का भारतीय मॉडल

स्थानीयकरण और संवेदीकरण कार्यशालाएं

नीति आयोग के एसडीजी वर्टिकल ने प्रगति की निगरानी, कार्यों के मूल्यांकन और एसडीजी की प्राप्ति की प्रगति में तेजी लाने के लिए सुधारों के कार्यान्वियन पर 28 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों के साथ परामर्शों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

राज्य के साथ परामर्शों में नेतृत्व के स्तर से बड़ी भागीदारी देखी गई, जो उच्चतम स्तर पर एसडीजी एजेंडा को अपनाने का संकेत देती है। अधिकांश मामलों में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशालाओं की अध्यक्षता की गई है। अन्य राज्यों में कार्यशालाओं की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव (राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रमुख) द्वारा की गई है। इन कार्यशालाओं में संबद्ध विभागों के वरिष्ठ सचिवों, विभागाध्यक्षों, एसडीजी से संबंधित विभागों के मध्यम स्तर के अधिकारियों और सांख्यिकीय अधिकारियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई। परामर्शों में जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। इन कार्यशालाओं में, नीति आयोग का प्रमुख एसडीजी भारत सूचकांक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख निगरानी और मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है।

राज्यों के साथ जुड़ाव

राज्यों के साथ डीएमईओ का जुड़ाव

नीति आयोग का विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) समय-समय पर ज्ञान साझाकरण वेबिनार, क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों के साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन अध्ययन पर दिशानिर्देश और टूलकिट साझा करने के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जुड़ता रहा है। डीईएमओ ने 2022 में डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक, ओडिशा की आउटपुट आउटकम निगरानी रूपरेखा, कर्नाटक की सामाजिक रजिस्ट्री (कुटुंब परियोजना), गुजरात की व्यवहार परिवर्तन पर विषयगत रिपोर्ट और मुख्यमंत्री के निगरानी डैशबोर्ड पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पांच वेबिनार आयोजित किए। इन वेबिनारों ने राज्यों को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने और एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए मंच प्रदान किया।

इसके अलावा, डीएमईओ ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वेब आधारित गोलमेज की एक श्रृंखला शुरू की। निगरानी और मूल्यांकन के संबंध में राज्यों के बीच सीखने को सक्षम करने के लिए, डीएमईओ ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से गुवाहाटी, असम में भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। इस गोलमेज में पूर्वोत्तर परिषद ने भी भाग लिया जिससे सतत विकास लक्ष्यों और विजन 2047 के संदर्भ में इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा संभव हुई।

डीएमईओ की टीम ने 'ग्रैनुलर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क' के कार्यान्वियन पर कार्यशाला का आयोजन करने के लिए मेघालय का दौरा किया। मेघालय को सीखने वाले राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अगस्त 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और मेघालय सरकार की साझेदारी में एक ग्रीष्मकालीन स्कूल का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने राज्य मुख्यालयों से लेकर दूर-दराज के और कम विकसित जिलों तक शासन के सभी स्तरों पर निगरानी और मूल्यांकन क्षमता के निर्माण के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की संभावनाएं उत्पन्न की।

डीएमईओ ने मूल्यांकन को मजबूत करने के उपायों को संस्थागत बनाने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता के लिए एक नैदानिक उपकरण का भी विकास किया है। डीएमईओ की टीम ने 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साक्षात्कार किए हैं। फीडबैक के लिए 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मसौदा रिपोर्टों को साझा किया गया है। वर्तमान में अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मसौदा रिपोर्ट और राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निगरानी और मूल्यांकन क्षमताओं को सुदृढ़ करना

देश भर में निगरानी और मूल्यांकन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, डीएमईओ ने 2022-23 के दौरान कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए:

- मई 2022 में भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवाओं के लिए एक सत्र आयोजित किया गया।
- 52 रिसर्च एसोसिएट्स को प्रशिक्षण देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया।
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जून 2022 में एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।
- जून 2022 में महाराष्ट्र सरकार के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों और संयुक्त निदेशकों के लिए यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी, पुणे के सहयोग से उत्पाद-परिणाम आधारित निगरानी पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।
- बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से राष्ट्रीय श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान में निगरानी, मूल्यांकन और सर्वोत्तम पद्धतियों पर एक सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- जुलाई और अगस्त 2022 में उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के सहयोग से डीएमईओ द्वारा उत्तराखंड के जिला स्तर के अधिकारियों के लिए दो आभासी क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए गए, इसके बाद अक्टूबर 2022 में 3-दिवसीय वैयक्तिक रूप से प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- डीएमईओ ने राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के साथ मिलकर असम सरकार के लिए बजट प्रबंधन पर एक सत्र आयोजित किया।
- अक्टूबर 2022 में नीति आयोग द्वारा राज्य को दी जा रही सहायता के तहत उत्तर प्रदेश में चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2022 में नीति आयोग में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसंधान अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- अक्टूबर 2022 में राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए योजना और समन्वय विभाग, त्रिपुरा सरकार के सहयोग से उत्पाद-परिणाम आधारित निगरानी, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, मूल्यांकन और सर्वेक्षण पद्धति पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

क्षेत्रीय सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी

शहरी नियोजन क्षमता

नीति आयोग ने सितंबर 2021 में देश में एक संचयी क्षमता- मानव संसाधन, तकनीकी और संगठनात्मक/शासन बनाने के लिए 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' पर एक प्रकाशन जारी किया।

फलस्वरूप, 'शहरी नियोजन' के एजेंडे ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और माननीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में समिति द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों की घोषणा की गई। इसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना शामिल है जो राज्य सरकारों को उनकी शहरी नियोजन क्षमता में सुधार करने, शहरी सुधारों को क्रियान्वित करने और शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए नवाचार लाने में सहायता करने हेतु उत्तरदायी है। नीति आयोग ने गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि राज्य सरकारों के साथ सम्मेलनों और अंतःक्रिया का आयोजन किया, ताकि राज्यों को सबसे आगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और शहरों को नीचे से ऊपर की ओर समाधान के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के सारस्वत, 25 फरवरी 2022 को तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री को 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' पर नीति आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए

उद्योग को बढ़ावा देना

अप्रैल 2022 में डॉ वी के सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के संभावित तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और इसके लिए आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने हेतु उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

नीति आयोग में कर्नाटक सरकार के भारतीय प्रशासनिक अध्येताओं (आईएएफ़) के लिए दो दिवसीय नेतृत्व बूटकैंप

कर्नाटक राज्य सरकार ने नीति आयोग से संपूर्ण अर्थव्यवस्था और नीति आयोग द्वारा की गई नीतिगत पहलों/कार्यनीतियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रशासनिक अध्येताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दो दिवसीय नेतृत्व बूटकैंप आयोजित करने का अनुरोध किया। नीति आयोग में 27-28 अप्रैल 2022 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में बूटकैंप का आयोजन किया गया। बूटकैंप को कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी संबोधित किया। इस समागम का प्रयोजन राज्य के नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक साथ लाकर बड़े पैमाने पर निरंतर प्रभाव को प्रोत्साहित करना है।

नीति आयोग में भारतीय प्रशासनिक अध्येता (आईएएफ), कर्नाटक सरकार के लिए दो दिवसीय लीडरशिप बूटकैंप

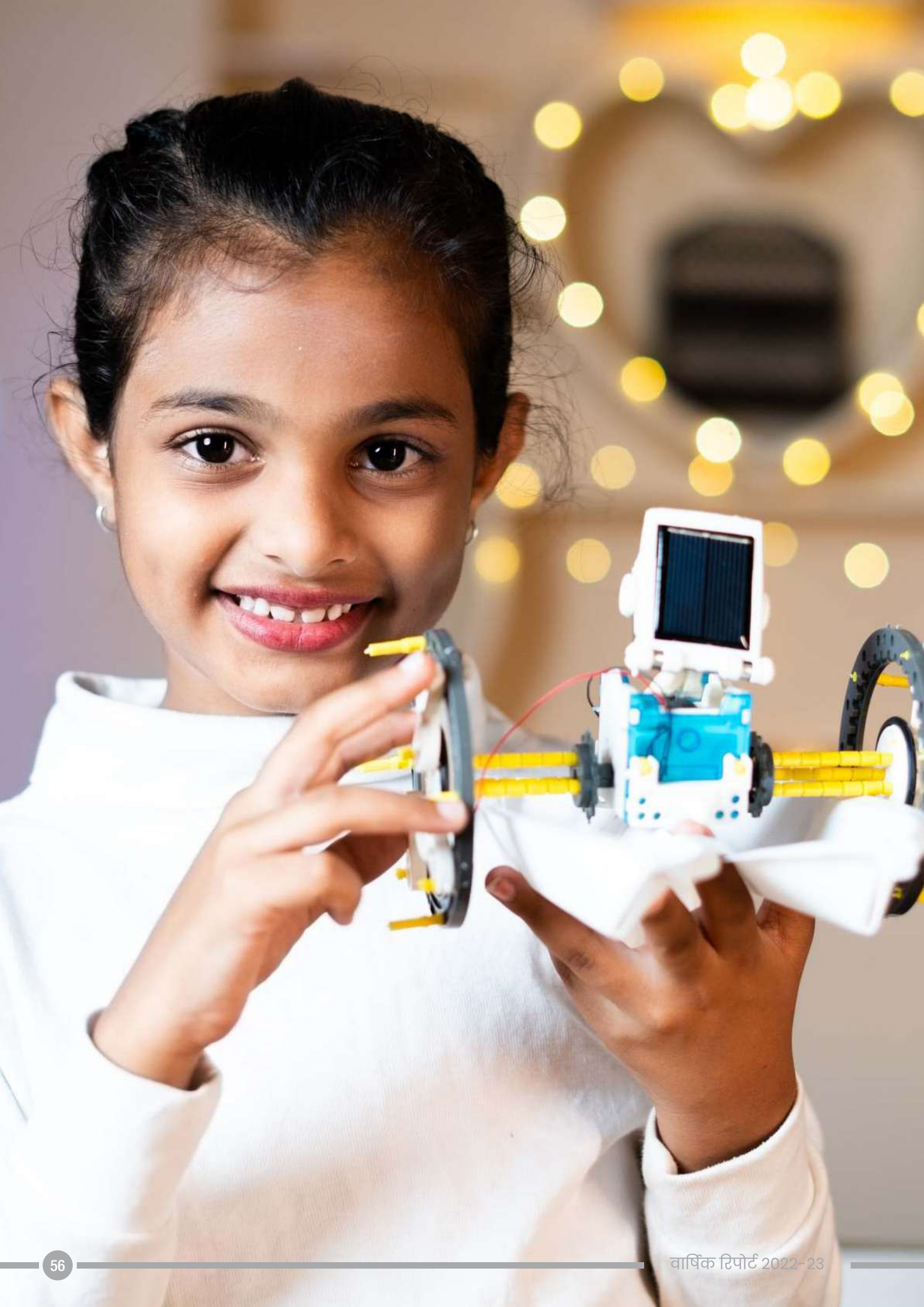

खंड

05

थिंक-टैंक की गतिविधियाँ

प्रस्तावना

वर्ष 2022-23 में, नीति आयोग ने सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी को मुख्यधारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों की कई आर्थिक और सामाजिक संभावनाओं का पता लगाने के अलावा, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप देश को गंभीर चुनौतियों से उबारने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, नीति आयोग ने ज्ञान, नवोन्मेष और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली के सृजन हेतु विभिन्न थिंक-टैंकों, देशों, और शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के साथ पुरानी साझेदारी जारी रखी और नई साझेदारी की।

अर्थशास्त्रियों का जमावड़ा

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2023-24 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसकी चुनौतियों का आकलन करने के लिए 13 जनवरी 2023 को नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की।

माननीय प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में शीर्ष अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की

यह विचार-विमर्श 'वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारत का विकास और लचीलापन' विषय पर आधारित था। प्रधानमंत्री ने भारत डिजिटल कहानी की सफलता, देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाने और समावेशी विकास और इसके वादे की क्षमता की सराहना की। उन्होंने नारी शक्ति को भारत के विकास के प्रमुख संचालक के रूप में रेखांकित किया और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को और सक्षम बनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पोषक वर्ष में मोटे अनाज को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

बैठक में वित्त मंत्री, योजना राज्य मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के सीईओ भी उपस्थित थे।

नीति इन-हाउस व्याख्यान श्रृंखला

नीति आयोग के अधिकारियों और भारत सरकार के अन्य चुनिंदा अधिकारियों के लिए भारत की विकास कार्यनीतियों पर एक आंतरिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई है। इन व्याख्यानों का उद्देश्य प्रतिभागियों को सरकार की प्रमुख पहलों के बारे में संवेदनशील बनाना, उनके ज्ञान को बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना, अधिक उत्पादक और समावेशी वातावरण बनाना, नवीन सोच को प्रोत्साहित करना और राष्ट्र के विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साझा प्रतिबद्धताओं को विकसित करना है।

इस श्रृंखला का पहला व्याख्यान 30 सितंबर 2022 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में–**'कोविड-19 टीकाकरण- भारत की कहानी'** विषय पर आयोजित किया गया था। डॉ. वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग ने मुख्य भाषण दिया, जिसके बाद श्री राजेश भूषण, सचिव (स्वास्थ्य); डॉ कृष्णा एल्ला, संस्थापक, भारत बायोटेक; और सुश्री प्रियम गांधी-मोदी, लेखक और संचार रणनीतिकार ने पैनल चर्चा की और इसे सीईओ, नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया।

डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग 'कोविड19 टीकाकरण - भारत की कहानी' पर पहले नीति हाउस हाउस व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए

श्रृंखला का दूसरा व्याख्यान 31 अक्तूबर, 2022 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में **'भारत की सुधार गाथा–पिछले 8 वर्ष'** विषय पर आयोजित किया गया था। श्री गौतम चिकरमाने (उपाध्यक्ष, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ओआरएफ) ने मुख्य भाषण दिया, जिसके बाद सुश्री अनीता करवाल, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और श्री सुब्रकांत पांडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फिक्की, के साथ एक पैनल चर्चा हुई और सीईओ, नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया गया।

बांए से दांए: फिक्की वरि. उपाध्यक्ष सुब्रकांत पांडा, ऑब्जर्बर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) उपाध्यक्ष गौतम चिकरमाने, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मु.का.अ. परमेश्वरन; स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव अनीता करवाल

नीति आयोग के अधिकारियों और भारत सरकार के अन्य चुनिंदा अधिकारियों के लिए भारत की विकास रणनीतियों पर इन-हाउस व्याख्यान श्रृंखला का तीसरा संस्करण 30 नवंबर 2022 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में **'सरकार का महिला सशक्तिकरण पर ध्यान: सफलताएं और आगे का रास्ता'** विषय पर आयोजित किया गया था। मुख्य भाषण श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीय केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य द्वारा दिया गया, जिसके बाद श्रीमती संगीता रेड्डी, संयुक्त प्रबंध निदेशक, अपोलो अस्पताल; श्रीमती चेतना गाला सिन्हा, संस्थापक और अध्यक्ष, मंडेशी महिला बैंक; और मेजर दिव्या ए, भारतीय सेना के साथ पैनल चर्चा की गई। व्याख्यान दिलचस्प, विचारोत्तेजक था और चर्चा ने उन क्षेत्रों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की जो अनुसंधान के लिए खुले हैं जिन्हें नीति आयोग द्वारा ग्रहण किया जा सकता है।

'महिला सशक्तिकरण पर सरकार का ध्यान: सफलताएं और आगे की राह' पर नीति आयोग के तीसरे इन-हाउस व्याख्यान के पैनलिस्ट

30 दिसंबर, 2022 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में **'खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए पोषक अनाज का लाभ'** पर चौथा इन-हाउस नीति व्याख्यान आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष-2023 के समारोह की शुरुआत करना था और नीति आयोग के कर्मचारियों के बीच सीमांत किसानों के कल्याण, जल संकट, खराब मृदा स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य संकेतकों के कल्याण के लिए मोटे अनाज की क्षमता और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास एजेंडा 2030 की उपलब्धि के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

प्रो. रमेश चंद, सदस्य (कृषि) ने मुख्य भाषण दिया और पैनल चर्चा को भी संचालित किया, जिसमें डॉ अरबिंद कुमार पाढ़ी, प्रमुख सचिव, ओडिशा सरकार; डॉ. हेमलता आर, निदेशक, आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान; इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष शेफ मंजीत गिल; और सुश्री रुजुता दिवेकर, पोषण और व्यायाम विज्ञान विशेषज्ञ शामिल हुए। इसके अलावा, शेफ अनाहिता ढोंडी ने एक मिलेट कुकिंग का लाइव प्रदर्शन सत्र आयोजित किया और मिलेट आधारित स्टार्ट-अप के लिए छह प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए।

'खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए मिलेट का लाभ' पर चौथे इन-हाउस नीति व्याख्यान के पैनल के सदस्य।

शेफ अनाहिता ढोंडी चौथे इन-हाउस नीति व्याख्यान के दौरान लाइव मिलेट कुकिंग के प्रदर्शन सत्र का आयोजन करते हुए

सीमांत प्रौद्योगिकियां

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का जिम्मेदार उपयोग

2018 में, नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एनएसएआई) के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की। एनएसएआई की सिफारिशों के आधार पर, जिम्मेदार एआई के क्षेत्र में अंतर-मंत्रालयी और विभिन्न हितधारकों के परामर्श के बाद दो दस्तावेज़ जारी किए गए- भाग 1: जिम्मेदार एआई के सिद्धांत, और भाग 2: जिम्मेदार एआई के संचालन के सिद्धांत।

जिम्मेदार एआई पर श्रृंखला के तीसरे पेपर को जनता की टिप्पणियों सहित हितधारकों के परामर्श को पूरा करने के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है। 'रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल: एडॉप्टिंग द फ्रेमवर्क–ए यूज केस अप्रोच ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी' शीर्षक वाला यह दस्तावेज़- चेहरा पहचान प्रौद्योगिकी (एफआरटी) से संबंधित उपयोग-मामले में उपर्युक्त सिद्धांतों और तंत्रों की जांच करता है। यह 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घोषित डिजी यात्रा की नीति के तहत हवाई अड्डे पर यात्रियों की निर्बाध ऑनबोर्डिंग के लिए नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक परियोजना का भी उल्लेख करता है।

डिजिटल बैंकों पर रिपोर्ट: भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव

20 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी और सीईओ श्री परमेश्वरन अय्यर द्वारा अन्य सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में डिजिटल बैंकों पर एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट एक सच्चाई बताती है और डिजिटल बैंकों के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था के लिए एक टेम्पलेट और रोडमैप पेश करती है। यह किसी भी नियामक या नीति मध्यस्थता से बचने पर ध्यान केंद्रित करता है और साथ ही प्रतिस्पर्धियों के साथ-साथ अधिकारियों को एक स्तरीय कार्य क्षेत्र प्रदान करता है।

राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बैटरी भंडारण मिशन

भारत में स्वच्छ, कनेक्टेड, साझा, टिकाऊ और समग्र गतिशीलता पहल को आगे बढ़ाने के लिए, मार्च 2019 में नीति आयोग में राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बैटरी भंडारण मिशन की स्थापना की गई। भारत में परिवर्तनकारी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णय और कार्यनीतियां बनाई गईं और सिफारिश की गई।

2022-23 के लिए मुख्य विशेषताएं

- एफ़एएमई-II योजना को फिर से शुरू किया गया, जिससे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर अपनाने की दर पिछले ग्यारह महीनों में प्राप्त लक्ष्य के 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 72 प्रतिशत हो गई है।
- 5450 ई-बसों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस निविदा विकसित की गई और कीमत की खोज के दौरान; इलेक्ट्रिक बसों की कीमतों में 18-24 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- नीति आयोग ने 50,000 ई-बसों की कुल मांग के लिए राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रम शुरू किया। लगभग 19,000 ई-बसें परिनियोजन के विभिन्न चरणों में हैं।
- नीति आयोग में ईवी मिशन के राज्य ईवी त्वरक कार्यक्रम ने 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी संबंधित ईवी नीतियां तैयार करने लिए प्रेरित किया है।
- भारत के परिवहन के लिए त्वरित ई-गतिशीलता क्रांति (ई-अमृत) –- सीओपी 26 में ईवी से संबंधित सभी जानकारी के लिए एक मंच का शुभारंभ किया।
- शून्य- शून्य प्रदूषण वितरण अभियान 140 उद्योग भागीदारों को एक साथ लाने में सक्षम; 70 मिलियन डिलीवरी और 40 मिलियन राइड पूरी की जा चुकी हैं।
- बैटरी स्वैपिंग नीति का एक मसौदा तैयार किया गया है।

सीओपी 27, शर्म अल शेख, मिस्र

नीति आयोग ने आकर्षक और प्रभावशाली समर्थन प्रदान करने के लिए यूके और यूएस के साथ मिलकर सीओपी 27 में एक जेडईवी कंट्री पार्टनरशिप शुरू की है, जो भारत के जेडईवी अपनाने में तेजी लाने में मदद करेगा। भारत ने भी 45 देशों के साथ, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु सड़क परिवहन सफलता के लिए प्राथमिकता कार्रवाई शुरू करने का समर्थन किया। नीति आयोग ने भारत की ईवी क्रांतिकारी यात्रा को उजागर करने के लिए सीओपी 27, इंडिया पवेलियन में एक पैनल की मेजबानी की। अतिरिक्त कार्यक्रमों के दौरान, नीति आयोग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के साथ, भारत के इलेक्ट्रिक टू- और थ्री-व्हीलर फ़्लीट्स के वित्तपोषण पर कार्यकारी सारांश शुरू किया।

सर्कुलर अर्थव्यवस्था

नीति आयोग ने लीथियम-आयन बैटरियों के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान का मसौदा तैयार किया है। कार्ययोजना में बैटरी के निर्माण, उपयोग, संग्रह, विखंडन, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण से लेकर बैटरी के विभिन्न जीवन चक्रों को ध्यान में रखा गया है।

इको लॉजिस्टिक्स योजनाएं

नीति आयोग आईसीएलईआई- संवहनीयता के लिए स्थानीय सरकारें, दक्षिण एशिया पहल के सहयोग से शिमला, पणजी और कोच्चि शहरों को इको-लॉजिस्टिक्स कम कार्बन वाली शहरी माल ढुलाई योजनाओं

के विकास में सहयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय कार्रवाई और राष्ट्रीय समर्थन के माध्यम से कम कार्बन वाले शहरी माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए क्षमताओं, कार्यनीतियों और नीतियों को प्रोत्साहित करना है। परियोजना के दूसरे चरण का विस्तार गंगटोक, इंफाल और रांची शहरों को सहायता देने के लिए किया गया है।

ई-फास्ट इंडिया (इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट–भारत) का शुभारंभ

नीति आयोग ने विश्व संसाधन संस्थान भारत (डब्ल्यूआरआई इंडिया) के सहयोग और विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ), कैलस्टार्ट और आरएमआई इंडिया की सहायता से, आज भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म- ई-फास्ट इंडिया (इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट-इंडिया) शुरू किया। ई-फास्ट प्लेटफॉर्म माल ढुलाई पारिस्थितिकी तंत्र से विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है, जिससे आपूर्ति और मांग पक्ष पर साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ अभिनव माल ढुलाई विद्युतीकरण समाधानों की पहचान और सहायता किया जा सके।

कार्बन कैप्चर, मेथनॉल और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था

कार्बन कैप्चर, उपयोगिता और संग्रहण (सीसीयूएस)

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने आर्थिक विकास से समझौता किए बिना तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के परिणामस्वरूप बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को दूर करे। भारत में बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और अन्य भारी औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में कोयले और पेट्रोलियम उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। हालांकि, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (सीसीयूएस) के माध्यम से दीर्घावधि में, डीप डीकार्बोनाइजेशन परिदृश्य, ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, नीति आयोग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्टिकल ने 30 मार्च 2022 को हाइब्रिड मोड में सीसीयूएस पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला ने भारत के लिए एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को सक्षम करने में सीसीयूएस की भूमिका पर चर्चा करने के लिए सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रमुखों और शिक्षाविदों को एक साथ लाया।

कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यशाला

मेथनॉल अर्थव्यवस्था

भारत 2040 तक 3.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद के साथ वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हालांकि, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की निर्भरता लगातार बढ़ी है। मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (डीएमई) बढ़ते आयात को कम करने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा, भारत मेथनॉल उत्पादन और उपयोग में एक प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसके व्यापक अनुप्रयोगों को देखते हुए इसके पास बड़ी संभावना है। नीति आयोग भारत में मेथनॉल अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रहा है।

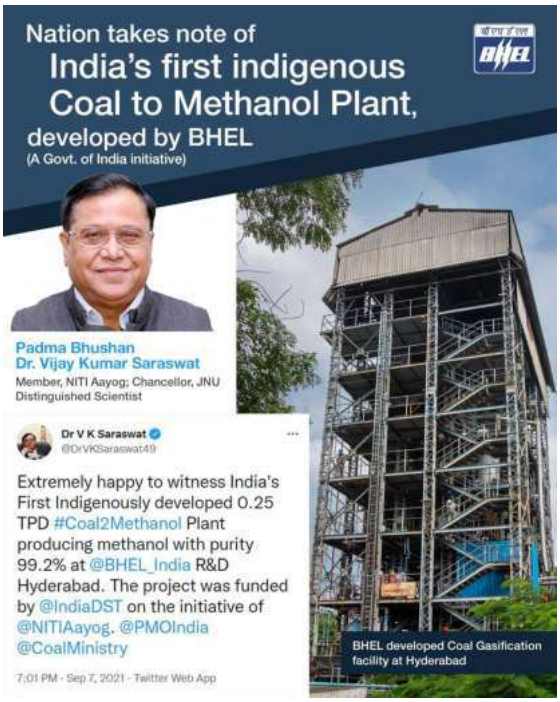

देश में एम15 कार्यक्रम शुरू करने के लिए, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) में दोपहिया वाहनों के लिए स्थायित्व और संभाव्यता परीक्षण प्रोटोकॉल की स्थिति और एम-15 परियोजना गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए 14 फरवरी 2022 को डॉ वी के सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। परीक्षण प्रोटोकॉल के आधार पर, एआरएआई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हीरो मोटोकॉर्प ने ई0, एम15 और ई0+एम15 जैसे ईंधन के साथ बीएसVI/बीएसIV/बीएसIII दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर विभिन्न परीक्षणों को पूरा कर लिया है। परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे हैं।

हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था

नीति आयोग हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था पर प्रयासों का समन्वय कर रहा है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सभी प्रासंगिक हितधारकों को आमंत्रित करते हुए हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था पर विचार-मंथन सत्र आयोजित किया था। इसके अलावा, 22 अप्रैल 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के समक्ष क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों द्वारा हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था पर एक प्रस्तुति दी गई थी। सुझावों के आधार पर, एस एंड टी वर्टिकल और अटल इनोवेशन मिशन ने पारिस्थितिकी तंत्र में हितधारकों और नवप्रवर्तकों को सक्षम करने के लिए संयुक्त रूप से रूपरेखा तैयार की है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारत-अमेरिका कार्यनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (एससीईपी): भारत-अमेरिका एससीईपी के सतत विकास स्तंभ के तहत गठित अंतर-मंत्रालयी समितियों की निम्नलिखित रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया है और जारी किया गया है:

क. **ऊर्जा डेटा प्रबंधन पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट:** समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के सलाहकार (ऊर्जा) ने की थी। इसने डेटा परिभाषाओं, डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग के लिए प्रारूपों/पद्धतियों, कैलोरी मान, आर्थिक/सांख्यिकीय इकाइयों और ऊर्जा/वस्तु संतुलन के संबंध में जांच की है और सिफारिशें की हैं।

ख. **कम कार्बन प्रौद्योगिकियों पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट:** समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ सलाहकार (एस एंड टी), नीति आयोग ने की। रिपोर्ट में इस्पात और सीमेंट के संबंध में डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप की पहचान की गई है। रिपोर्ट में नीतिगत हस्तक्षेपों, तकनीकी हस्तक्षेपों और अपेक्षित प्रोत्साहनों के संबंध में एक चरणवार योजना प्रस्तुत की गई है।

ग. **कोयले से उचित रूपांतरण संबंधी पर अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट:** समिति की अध्यक्षता कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की थी। इसने खदानों को बंद करने और उचित रूपांतरण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने की सिफारिशें की हैं।

इंडिया क्लाइमेट एंड एनर्जी मॉडलिंग फोरम (आईसीईएमएफ)

इंडिया क्लाइमेट एंड एनर्जी मॉडलिंग फोरम को मूल रूप से 2 जुलाई 2020 को इंडिया-यूएस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (एससीईपी) के सतत विकास स्तम्भ (एसजी पिलर) के तत्वावधान में इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम (आईईएमएफ) के रूप में संस्थापित किया गया था। ग्लासगो में सीओपी 26 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई "पंचामृत" प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, आईईएमएफ के दायरे को जलवायु और आर्थिक मॉडलिंग को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था, जिससे आईसीईएमएफ को पुनर्गठित किया जा सके। फोरम का उद्देश्य मॉडलिंग और दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन अभ्यास के लिए शोधकर्ताओं, ज्ञान भागीदारों, थिंक टैंक तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों, और विभागों को जोड़ना है। एलटीईएस परिदृश्य विकसित करने के लिए फोरम को संलग्न किया गया है।

भारत-सऊदी अरब कार्यनीतिक साझेदारी

भारत-सऊदी अरब कार्यनीतिक साझेदारी के तहत, नीति आयोग को सऊदी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (एससीआईएसपी) के साथ जुड़ने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चिह्नित किया गया है। दोनों पक्षों के संबंधित मंत्रालय और विभाग दोनों देशों में निवेश के प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं।

नीति आयोग, भारत-सऊदी अरब सामरिक भागीदारी के तहत गठित कार्यनीतिक साझेदारी परिषद (एसपीसी) के अर्थव्यवस्था और निवेश स्तंभ का सचिवालय होने के नाते, 15 सितंबर, 2022 को सीईओ स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक का आयोजन किया, जिसकी सह-अध्यक्षता नीति आयोग के सीईओ और सीईओ, सऊदी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (एससीआईएसपी), सऊदी अरब ने की। उद्योग, ऊर्जा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, और प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित चार संयुक्त कार्य समूहों ने सहयोग के अपने-अपने क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया। इस बैठक के बाद 18-19 सितंबर, 2022 को रियाद में आयोजित "अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक" हुई। अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया, जिसने ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खाद्य गलियारे, जल संयंत्रों के विलवणीकरण, व्यापार आदि की पहचान दोनों पक्षों के बीच सहयोग के संभावित तरीकों के रूप में की है।

नीदरलैंड दूतावास के साथ सहयोग

नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास के बीच हस्ताक्षर किए गए एसओआई के तहत, संयुक्त अध्ययन के लिए दो परियोजनाओं का चयन किया गया था। हेवी-ड्यूटी मोबिलिटी फ्यूल रिपोर्ट के रूप में एलएनजी को पूरा कर लिया गया है और विद्वत् समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। उन्नत जैव ईंधन रिपोर्ट तैयार की जा रही है और शीघ्र ही विद्वत् समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

एसईडी के प्रमुख कार्यक्रमों की झलकियां

कार्यनीतिक आर्थिक संवाद (एसईडी) वर्टिकल विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विदेशी सरकारों/ गणमान्य व्यक्तियों, दूतावासों और उच्च आयोगों के साथ नीति की बातचीत को चलाने की भूमिका निभाता है। 2022-23 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम हुए:

- व्यापार, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और द्विपक्षीय व्यापार जैसे पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए 1 अप्रैल 2022 को डेनमार्क के दूतावास और नीति आयोग के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य अनुकूल रूपरेखा स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार पर प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करना था।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की संसदीय समिति (आईएनटीए) के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय श्री बर्नड लांगे, आईएनटीए अध्यक्ष- एसएंडडी (जर्मनी) और उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश क्षमता पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए आगामी वार्ता के संदर्भ में किया।

- 21 अप्रैल 2022 को, आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संघीय मंत्रालय के राज्य सचिव श्री जोचेनफ्लासबार्थ के नेतृत्व में और नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में जर्मन प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई। एसडीजी, ऊर्जा, व्यापार, कृषि और जलवायु से संबंधित क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

- 22 अप्रैल 2022 को, "व्यापार, आर्थिक और निवेश में भारत-रूस सहयोग के कार्यक्रम" क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए रूसी सुदूर पूर्व प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई। दुर्लभ पृथ्वी, कृषि से संबंधित क्षेत्रों और सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करने पर चर्चा हुई।

- डॉ वी के सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग के नेतृत्व में, 26 अप्रैल 2022 को माननीय मंत्री जेरेमी हैरिसन, व्यापार और निर्यात विकास मंत्री (टीईडी) के नेतृत्व में सस्केचेवान प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई। उनके बीच दुर्लभ पृथ्वी, कृषि, व्यापार और उद्योग संबंधित क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इसी तरह के कार्यक्रम क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, जेईटीआरओ, सतत आधुनिकीकरण प्रतिनिधिमंडल और भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए।

- 5 सितंबर 2022 को विकास सहयोग पर पहला नीति-बीएमज़ेड संवाद आभासी रूप में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग और जर्मन पक्ष का नेतृत्व माननीय संघीय मंत्री सुश्री स्वेंजा शुल्ज़ ने किया। नीति-बीएमजेड संवाद सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा संक्रमण, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और कृषि-पारिस्थितिकी। दोनों पक्षों ने चल रहे अनुबंधों पर विचार-विमर्श किया और उन क्षेत्रों में संभावित सहयोग की पहचान की जो भारत और जर्मनी के लिए ठोस परिणाम और अनुभव सकते हैं।

भागीदारी

प्रमुख थिंक टैंकों के साथ चर्चा

नीति आयोग ने देश के प्रमुख थिंक टैंकों के साथ बातचीत के दौर की एक श्रृंखला शुरू की है। इन बैठकों के पीछे का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर थिंक टैंक और नीति आयोग के बीच विचार-विमर्श और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। फरवरी 2021 में आयोजित पहली बैठक के लिए 16 आमंत्रितों के साथ इसकी शुरुआत हुई। देश के प्रमुख थिंक टैंकों के साथ जुड़ाव की श्रृंखला में छठी बैठक 18 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष ने कोविड के बाद की रिकवरी और 2036-37 के विजन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन मार्ग और पीएम-किसान की प्रभावशीलता पर हाल के अध्ययन के निष्कर्षों पर थिंक टैंक के साथ बातचीत की। बैठक में राष्ट्रीय थिंक टैंक के रूप में नीति कैसे थिंक टैंक के साथ बेहतर ढंग से जुड़ सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में डेटाबेस अंतराल और डेटा अखंडता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

18 मई 2022 को नेशनल थिंक टैंक के साथ बैठक

महिला उद्यमिता मंच

महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) अपनी तरह का पहला एकीकृत-एक्सेस पोर्टल है जो सूचना विषमता पर काबू पाकर महिला उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना चाहता है। यह एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, सभी प्रासंगिक सूचनाओं के लिए एक ज्ञान का केंद्र प्रदान करता है, महिला उद्यमिता से संबंधित पहलों को प्रदर्शित करता है, और बड़े उद्यमी समुदाय तक पहुंच की अनुमति देता है। अपने सबसे हाल के चरण में, डब्ल्यूईपी में उन्नत सामग्री, स्मार्ट-मैचमेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महिला उद्यमियों और भागीदारों के उन्नत विश्लेषण-आधारित जुड़ाव के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित नई सुविधाएँ हैं। डब्ल्यूईपी की सामग्री व्यापक शोध कार्य के आधार पर विकसित की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी योजनाएं, इनक्यूबेटर, एक्सीलरेटर, अन्य पहल आदि शामिल हैं। रोल मॉडल बनाने के लिए, डब्ल्यूईपी ने 75 असाधारण महिला उद्यमियों को आज़ादी का अमृत महोत्सव– भारत@75 के हिस्से के रूप में 'समर्थ और सशक्त भारत' में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस

समारोह में विज्ञान, वित्त, प्रौद्योगिकी, खेल और सशस्त्र बलों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया।

वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी)

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान श्रम और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित हुआ है और वर्षों से दुनिया भर में पहचान प्राप्त की है। इस संस्था के प्राथमिक उद्देश्यों में समावेशी विकास और कल्याण पर ध्यान देने के साथ अनुसंधान, परामर्श, शिक्षा और प्रशिक्षण और निगरानी और मूल्यांकन शामिल हैं।

आम परिषद की बैठक

एनआईएलईआरडी की आम परिषद की 53वीं बैठक 14 नवंबर 2022 को श्री सुमन के. बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग और अध्यक्ष, जनरल काउंसिल, एनआईएलईआरडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में वर्ष के दौरान एनआईएलईआरडी में आयोजित अनुसंधान परियोजनाओं और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया और दिसंबर 2022 में संसद के दोनों सदनों में रखे गए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यकारी परिषद की बैठक

एनआईएलईआरडी की 103 वीं कार्यकारी परिषद की बैठक 29 जून 2022 को श्री अमिताभ कांत, तत्कालीन सीईओ, नीति आयोग और अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद, एनआईएलईआरडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। कार्यकारी परिषद ने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों और आगे के विकास के लिए रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया, विशेष रूप से विभिन्न मंत्रालयों के साथ भविष्य के सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया।

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान की कार्यकारी परिषद की 103वीं बैठक

2022-23 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

i. महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से तैयार एक सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 19–23 दिसंबर 2022 के दौरान मुद्दे, चुनौतियाँ और नीति का संचालन किया गया। महिला मामलों के मंत्रालय, कंबोडिया सरकार की महामहिम श्रीमती कुंग सोरिटा के नेतृत्व में एक 20 सदस्यीय वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम में भाग लिया।

महिला सशक्तिकरण: मुद्दे, चुनौतियां और नीति पर आवासीय प्रशिक्षण के प्रतिभागी

ii. एसडीजी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम: विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक एकीकृत दृष्टिकोण 04 जनवरी, 2023 को शुरू हुआ। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया सहित 27 देशों के 27 अधिकारियों ने भाग लिया। यह एक महीने का आवासीय पाठ्यक्रम है। उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने नीति आयोग में विशेष सत्र के दौरान मुख्य भाषण दिया।

सतत विकास लक्ष्य पर आवासीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की उपाध्यक्ष के साथ बातचीत

iii. विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मानव क्षमताओं के विकास पर जून, 2022 के दौरान चार सप्ताह का आवासीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 17 देशों के 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iv. डीएमईओ, नीति आयोग के सहयोग से 18-23 जुलाई, 2022 तक राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निगरानी मूल्यांकन और अनुभव पर एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 17 राज्यों के 31 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

मानव क्षमताओं के विकास पर आईटीपी

निगरानी मूल्यांकन और अनुभव पर प्रशिक्षण

v. दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम, 2016 पर एक ऑनलाइन जागरूकता सृजन और संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 15-16 सितंबर, 2022 को किया गया। 2022-23 के दौरान विभिन्न हितधारकों के लिए इस तरह के पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 पर जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के भागीदार

vi. आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 23 नवंबर 2022 को स्वास्थ्य में डिजिटल गवर्नेंस पर चार सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह पाठ्यक्रम भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में चयनित राष्ट्रीय स्तर की ई-गवर्नेंस पहलों पर प्रत्यक्ष रूप से स्पष्टीकरण करने पर केंद्रित है।

आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2022-23 के लिए विदेश मंत्रालय की आईटीईसी योजना के तहत 1) वित्तीय समावेशन और डिजिटल रूपांतर, 2) सार्वजनिक नीति और शासन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

डीएमईओ, नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से फरवरी 2023 में राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए निगरानी और मूल्यांकन पर दूसरा राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

अनुसंधान अध्ययन

संस्थान ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। 2022-23 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन पूरे हो चुके हैं या चल रहे हैं:

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान योजना के तहत रुग्ण/बंद एमएसएमई का आकलन।

ii. डीएमईओ द्वारा अधिकृत रबर बोर्ड का मूल्यांकन

iii. डीएमईओ द्वारा अधिकृत कॉफी बोर्ड का मूल्यांकन

iv. डीएमईओ द्वारा अधिकृत मसाला बोर्ड का मूल्यांकन

v. भारी उद्योग मंत्रालय के लिए पारदर्शिता लेखा परीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसमें महानिदेशक, एनआईएलईआरडी के अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

महानिदेशक, एनआईएलईआरडी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया

हिंदी पखवाड़ा

संस्थान ने अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सक्रिय भागीदारी के साथ हिंदी पखवाड़ा (31 अगस्त-14 सितंबर) को सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ 14 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस मनाया गया।

14 सितंबर, 2022 को एनआईएलईआरडी में हिंदी दिवस समारोह

खंड

06

अटल इनोवेशन मिशन

प्रस्तावना

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) देश में नवोन्मेष और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयोजन से भारत सरकार की प्रमुख पहल है। वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद से, एआईएम ने विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब, 69 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, 14 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए हैं और 24 अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किए हैं। निष्पादित की गई 40 से अधिक साझेदारियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) से, एआईएम ने 75 लाख से अधिक छात्रों को सफलतापूर्वक शामिल किया है, 2900 से अधिक स्टार्टअप (900+ महिला स्टार्टअप सहित) की सहायता की है और 32000 से अधिक रोजगारों का सृजन किया है।

नवोन्मेष जीवन-चक्र (इनोवेशन लाइफ साइकल) में एआईएम की सहायता

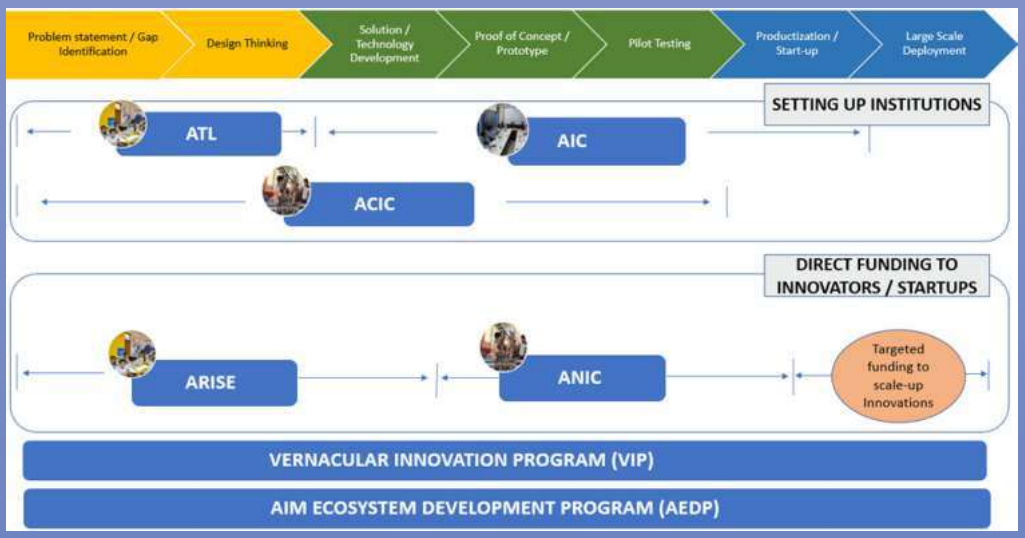

अटल टिंकरिंग लैब्स

एआईएम के आने से, नवोन्मेष और उद्यमिता हमारे राष्ट्रीय मिशन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, और स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) की स्थापना से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों भी प्रौद्योगिकी नवोन्मेष की दुनिया से रूबरू हो रहें है। एटीएल, एआईएम, भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जो पूरे भारत के उच्च विद्यालयों के छात्रों के बीच एक नवोन्मेषी मानसिकता का पोषण करती है।

भारत के राष्ट्रपति के साथ एटीएल अन्वेषक

एटीएल के अंदर, छात्र सोचने और अन्वेषण करने, विफल रहने पर भी कोशिश करने, यहां तक कि लीक से हटकर कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को 21वीं सदी के कौशल जैसे डिजाइन चिंतन, क्रिटिकल चिंतन, कम्प्यूटेशनल चिंतन, डिजिटल संनिर्माण, सहयोगात्मक कौशल आदि से सुसज्जित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

एटीएल योजना के तहत, एटीएल की स्थापना करने के लिए चयनित विद्यालयों को बीस लाख रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। एटीएल कार्यक्रम को मोटे तौर पर चार प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

चयन	स्थापना	समर्थ	सराहना
• डिजिटल अनुप्रयोग • चुनौती आधारित चयन • अविरत अनुपालन और अनुदान प्रबंधन	• एटीएल एसओपी दिशानिर्देश • क्षमता निर्माण – शिक्षक, मेंटर, छात्र प्रशिक्षण • एटीएल पाठ्यक्रम और वीडियो शिक्षण	• गतिविधियों का एटीएल कैलेंडर • गुणवत्तायुक्त मापन (क्यूसीआई + डैशबोर्ड) • एटीएल का अंगीकरण • मेंटर ऑफ चेंज	• प्रसिद्धि की दीवार • सम्मान मंच • माह का एटीएल और मेंटर • क्षेत्रीय मेंटर और परिवर्तन के बदलते शिक्षक
सुदृढ़ प्रणाली संचालित दोतरफा संचार			
7 सदस्यी दल – 4 नवाचार लीड + 3 यंग प्रोफेशनल भागीदारों द्वारा समर्थित			

एटीएल कार्यक्रम का ढांचा

(i) चयन

अक्तूबर 2022 तक, भारत के 700 जिलों और 99 आकांक्षी जिलों के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में 10,000 एटीएल संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश सह-शिक्षा और बालिकाओं के स्कूलों में स्थापित किए गए हैं।

(ii) स्थापना

एआईएम ने इसके भागीदारों के साथ, इससे जुड़े संसाधनों की क्षमता का निर्माण करने के लिए एटीएल 'अनबॉक्स टिंकरिंग' जैसे कई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अब तक 5000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आयोजित किए गए अन्य शिक्षक प्रशिक्षणों में आईपीआर, ऐप डेवलपमेंट, एटीएल गेम डेवलपमेंट, एथिक्स एंड लीडरशिप इन इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग ट्रेनिंग आदि शामिल हैं।

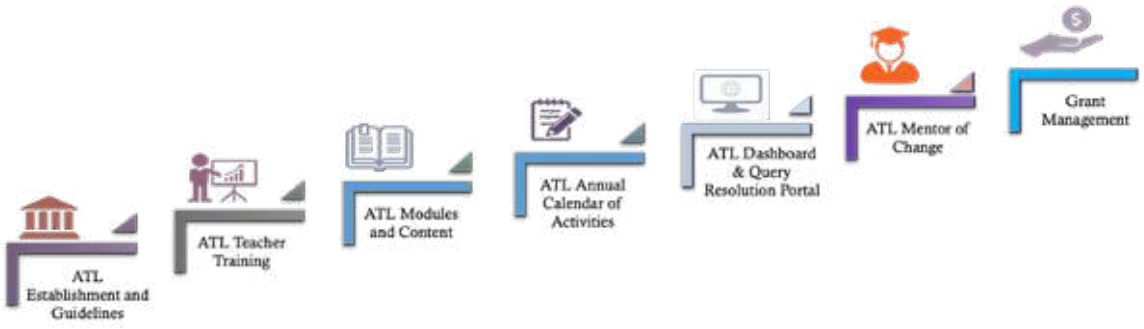

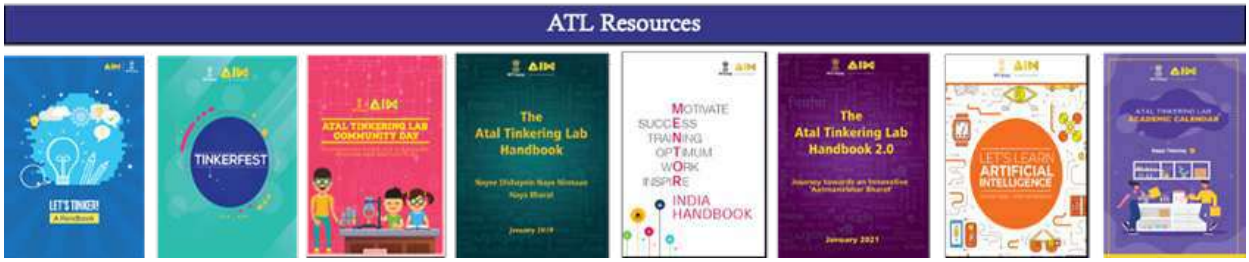

(iii) समर्थ (इनेबल)

एटीएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल, एटीएल गेमिंग मॉड्यूल, एटीएल कॉलेबकेड मॉड्यूल, एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, एटीएल पायथन लर्निंग मॉड्यूल, छात्रों के लिए आयोजित 30+ चुनौतियां, 31,000+ छात्रों की भागीदारी सहित छात्रों के लिए नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी कौशल संबंधी कई ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किए गए। एआईएम ने एटीएल मैराथन, एटीएल टिंकरप्रेन्योर, एटीएल कम्युनिटी डे जैसी अपनी प्रमुख प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम शुरू किए।

(iv) सराहना

एआईएम सभी छात्रों, शिक्षकों और मेंटरों को उनके नवोन्मेषी प्रयासों और अच्छे काम के लिए कई मंचों और पहलों जैसे वॉल ऑफ फेम, परिवर्तन के आदर्श शिक्षक, माह का एटीएल, छात्र नवोन्मेषक कार्यक्रम (एसआईपी), छात्र उद्यमिता कार्यक्रम (एसईपी) के माध्यम से सम्मान और प्रोत्साहन प्रदान करता है।

मेंटर इंडिया

एटीएल के सफल कार्यान्वियन का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न नवोन्मेष संबंधी कौशल पर छात्रों का मार्गदर्शन करने की दिशा में मेंटरों, उद्योग के पेशेवरों और पूर्व छात्रों सहित विभिन्न हितधारकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए उनके साथ बनाई गई मजबूत साझेदारी है। इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने में विभिन्न भागीदारों की क्षमता, संसाधन, तकनीकी ज्ञान पर आधारित स्थायी संस्थागत ढांचे महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, चूंकि एक अवधारणा के रूप में छेड़छाड़ करना (टिंकरिंग) हमारे देश में अभी भी नया है, इसलिए इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट जगत, शिक्षा जगत, उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकार आदि के सलाहकारों के सतत समर्थन की आवश्यकता है। यह देखते हुए कि एटीएल की प्रकृति गैर- निर्देशात्मक है, मेंटरों से प्रशिक्षकों के बजाय इनेबलर्स के रूप काम करने की अपेक्षा की जाती है। तकनीकी ज्ञान, नवोन्मेष और डिजाइन, व्यवसाय और उद्यमिता जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रतिपालकों से योगदान की अपेक्षा की जाती है। एआईएम ने 5800+ मेंटर और 90 क्षेत्रीय परिवर्तन मेंटर (आरएमओसी) को शामिल किया है।

साझेदार इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करके और एटीएल छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके छात्रों के तकनीकी क्षितिज का विस्तार करने में भी मदद करते हैं।

एआईएम ने मेंटर राउंड टेबल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, जो शीर्ष मेंटर को सम्मानित करने के लिए और उनकी सराहना करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है और बदलते मेंटरों (मेंटर्स ऑफ चेंज) द्वारा किए गए असाधारण कार्य को साझा करने और सराहना करने के लिए जीईएम पुस्तिका प्रकाशित की।

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर कार्यक्रम को वर्ष 2017 में बिजनेस इन्क्यूबेटरों के ईकोसिस्टम पारि-प्रणाली के निर्माण की दृष्टि से शुरू किया गया था, जहां उद्यमी भौतिक अवसंरचना, प्रशिक्षण और शिक्षा सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, और निवेशकों, अन्य नवोन्मेषकों और सलाहकारों सहित प्रमुख हितधारकों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। एआईसी/ईआईसी को 5 वर्ष की अवधि में 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। एआईएम ने अन्य के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और कॉर्पोरेट में 69 एआईसी का संचालन किया है। अब तक, इस एआईसी कार्यक्रम के तहत 2900 से अधिक

प्रचालनतग स्टार्टअपों को सहायता दी गयी है, जिन्होंने प्रत्यक्षत: 15,000 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। 33.70 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से बाद की अठारह किश्तों को संसाधित किया गया है।

एआईसी का भौगोलिक प्रसार

अब तक की यात्रा

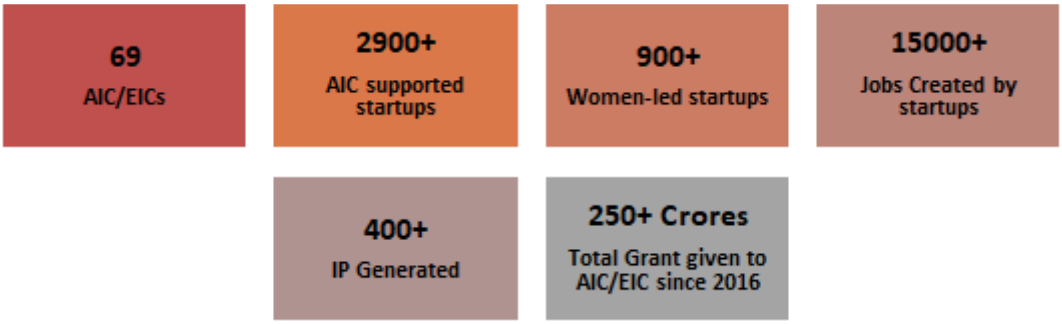

विशेषताएं (हाइलाइट) 2022-23

1. निधियन/स्टार्ट अप मान्यता

StringBio EIC C-CAMP incubatee has raised USD 20 million, as part of Series B funding.	**Instoried** Amrita TBI incubatee has raised a Funding of USD 200 million as a part of multiple rounds of series with GEM Global Yield, an alternative investment group	**Rasulpur Coffee Estates and Roasters** AIC CCRI incubatee received GI Tag for its products 'Coorg Arabica Coffee'.	**Bugbase** AICMUJ, Jaipur incubatee fetched a funding of USD 500,000 as a pre-Seed Round, led by 2am VC
Digantara EIC SID, IISc Bengaluru incubatee raised USD 2.5 million from Kalaari Capital	**Sunfox** AIC Aartech, incubatee, raised USD 20 million in multiple rounds of funding	**Ippo Pay** AIC RAISE incubatee raises USD 2.1 million from multiple VC funds	**Buyo fuel** AIC RAISE incubatee raises USD 1.5 million from multiple VC funds

2. अटल इनोवेशन मिशन ने 28 अप्रैल 2022 को 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया। इस कार्यक्रम में एआईएम द्वारा समर्थित 20 से अधिक स्टार्टअप ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ अजय सूद द्वारा कॉफी टेबल बुक 'इनोवेशन फॉर यू, सेक्टर फोकस- ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी' के तीसरे संस्करण का विमोचन किया गया था।

अटल इनोबेशन मिशन ने डॉ. अबेंडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), दिल्ली में एक भव्य नवाचार उत्सव में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया।

3. एआईएम ने जीआईजेड और धृति फाउंडेशन के सहयोग से महिला केंद्रित इनक्यूबेशन सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित एक कार्यक्रम, विनक्यूबेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा समूह लॉन्च किया।

4. एआईएम ने औषध विनिर्माता फाइजर और सोशल अल्फा के साथ मिलकर यूएन हेल्थ इनोवेशन एक्सचेंज (यूएनएचआईईएक्स) को एक ज्ञान साझीदार के रूप में साथ रखकर हेल्थकेयर स्टार्टअप्स के लिए फाइजर इंडोवेशन इनक्यूबेशन पहल के पहले संस्करण की घोषणा की। इसका फोकस ऑन्कोलॉजी और डिजिटल स्वास्थ्य पर है। जिन छह विजेताओं को 65-65 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, उन्हें एआईएम से इनक्यूबेशन सहायता प्राप्त होगी। फाइजर इन स्टार्ट-अप्स को अनुदान के साथ-साथ मेंटरशिप और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और सोशल अल्फा कार्यक्रम त्वरण सहायता प्रदान करेगा।

5. गांधीनगर में 18-22 अक्तूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित किया गया था। 20 से अधिक एआईसी समर्थित स्टार्टअप्स ने इस डिफेंस एक्सपो में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस आयोजन ने स्टार्टअप्स को भारतीय सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक सौदे करने में मदद की।

6. दो एआईसी सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 27-30 अक्तूबर 2022 के दौरान जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित एशियान स्टार्टअप्स फेस्टिवल में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस शिखर सम्मेलन में 10 एसियान देशों के सरकारी निकायों, स्टार्टअपों और अन्य नवोन्मेषी पारि-प्रणाली हितधारकों ने शिरकत की थी। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा आसियान देशों में भारतीय स्टार्टअपों के लिए बाजार पहुंच को सक्षम बनाना था।

7. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के तहत 48 अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों को सीड फंड ग्रांट्स-इन-एड से सहायता प्रदान की गयी है। ये एआईसी ऋण या सीसीडी के रूप में स्टार्टअपों को सीड फंड वितरित करेंगे।

8. एआईएम ने 'इनोवेशन फॉर यू' नामक प्रकाशनों की अपनी श्रृंखला के तहत एआईएम सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स के 4 संकलन लॉन्च किए हैं। नवीनतम संकलन जिसका शीर्षक 'भारत के 75 वीमेनप्रेनर' है, को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था।

9. एआईएम ने एआईसी–पीईसीएफ, पांडिचेरी तकनीकी विश्वविद्यालय में अपना पहला वार्षिक एआईएम सम्वाद कार्यक्रम आयोजित किया। 2 दिन (27-28 सितंबर 2022) की अवधि के दौरान इनक्यूबेटर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसके दौरान एआईसी/ईआईसी में से प्रत्येक के संबंधित सीईओ, इनक्यूबेशन प्रबंधकों और उनके मेजबान संस्थान के सदस्यों द्वारा वास्तविक/वर्चुअल प्रतिनिधित्व किया गया था।
10. एआईएम एआईसी कार्यक्रम ने नए एआईसी के चयन के लिए एप्लिकेशन पोर्टल लॉन्च किया। एआईएम को वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 101 इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने का अधिदेश है।

अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर

अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) देश के वंचित क्षेत्रों में नए समाधानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नवोन्मेष को संचालित करने का एक साधन है। एसीआईसी का उद्देश्य एक पीपीपी आधारित सहभागी मॉडल विकसित करके एसडीजी समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित नवोन्मेषों के लाभों को बढ़ावा देना और प्रचारित करना है जिसमें एआईएम द्वारा अनुदान सहायता स्वरूप योगदान की गयी राशि के बराबर की राशि अंशदान करना अपेक्षित होता है।

एसीआईसी से निम्नलिखित अपेक्षा की जाती है:

1. इन्क्यूबेशन सेंटर और मेकर्सस्पेस की संचालन सुविधाओं के लिए उपयुक्त बुनियादी ढाँचा;
2. उभरती प्रौद्योगिकियों में उभरते नवोन्मेषकों की क्षमता का निर्माण और उनके नवोन्मेषों को विचार से लेकर प्रभावशाली समाधान तक डिजाइन करना।
3. प्रत्येक के लिए उनकी पृष्ठभूमि और उम्र के निरपेक्ष समाधान खोजने, विचार करने और समाधान तैयार करने का अवसर।

वर्तमान हस्तक्षेप

1. **कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप:** यह एक वर्षीय गहन अध्येतावृति कार्यक्रम है, जिसमें इच्छुक सामुदायिक नवोन्मेषकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के निरपेक्ष आवेदन कर सकते हैं। इस अध्येतावृति के दौरान, प्रत्येक अध्येता की अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में मेजबानी की जाएगी और वह अपने विचार पर काम करते हुए एसडीजी जागरूकता, उद्यमिता कौशल और जीवन कौशल हासिल करेगा। सीआईएफ का कोहोर्ट 1 लॉन्च किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के 14 एसीआईसी के 24 अध्येता शामिल हैं। एक अध्येता की साल भर की यात्रा को पांच चरणों में संरचित किया गया है, प्रत्येक के अलग-अलग उद्देश्य और परिणाम होते हैं। अध्येता को मेजबान एसीआईसी टीम, मेंटर्स और एआईएम टीम द्वारा लगातार सहायता प्रदान की जाती है।

2. **प्रचालन नियम पुस्तिका:** एसीआईसी को एसडीजी को पूरा करने में भारत के विकास में तेजी लाने के लिए समाज को विकसित करने और नवोन्मेष का समर्थन करने पर ध्यान देने के साथ एक नवोन्मेष केंद्र विकसित करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और विकसित करने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने के लिए नवोन्मेष केंद्रों के लिए एक टूलकिट। प्रचालन नियम पुस्तिका को विशिष्ट रूप से एक सफल नवोन्मेष ईकोसिस्टम संचालित करने के लिए आवश्यक विभिन्न स्तंभों (अर्थात् बुनियादी ढाँचा, लोग, ज्ञान, नेटवर्क, वित्त, निगरानी और मूल्यांकन) को संकलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नियोजित अंतर्क्षेप

1. **डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म:** उद्यमिता, नवोन्मेष, एसडीजी और 21वीं सदी के कौशल से संबंधित विभिन्न विषयों पर क्यूरेटेड पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों के लिए साझा मंच (वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म)। इस मंच को नवोन्मेषकों के लिए, नवोन्मेषकों का एक मंच बनकर ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करने की दृष्टि से अभिकल्पित किया गया है।

2. **बदलाव की कहानियां:** बदलाव की कहानियां नवोन्मेषकों द्वारा अपने समुदायों में बनाए गए प्रभाव की कम-सुनी कहानियों को सबसे आगे लाने के लिए एक अभियान है। भारत (या दुनिया भर में) में नवोन्मेष की कहानियां केवल कुछ 'विकसित' क्षेत्रों से होने के कारण शहर-केंद्रित होने प्रदर्शन करती हैं और जिन्हें सबसे अधिक दोहराया और सुनाया जाता है। एआईएम, एसीआईसी के साथ समन्वय कर, वीडियो, लेख और पॉडकास्ट के रूप में जमीनी नवोन्मेषकों की सफलता की कहानियों को उनके स्वयं के क्षेत्र में पहचान दिलाना और दस्तावेजीकरण करना चाहता है।

मुख्य बिन्दु

1. 9 राज्यों में चौदह एसीआईसी चालू हो गए हैं, और 15 अनुपालन जांच से गुजर रहे हैं।
2. समुदाय नवोन्मेषक अध्येता (कम्युनिटी इनोवेटर फेलो) का प्रथम कोहोर्ट 26 जुलाई 2022 को शुरू की गई चरणबद्ध यात्रा से गुजर रहा है। प्रथम कोहार्ट में 14 एसीआईसी के 24 सीआईएफ शामिल हैं।
3. एआईएम का इरादा मार्च, 2023 तक 50 से अधिक एसीआईसी स्थापित करने का है।

भारत में परिचालनरत एसीआईसी की वर्तमान सूची:

क्र.सं.	प्रचालनरत शैक्षणिक मेजबान संस्थान/संगठन का नाम	क्षेत्र
1.	बीएमएल मुंजल विश्वविद्यालय	गुड़गांव, हरियाणा
2.	चैतन्य भारती प्रौद्योगिकी संस्थान	रांगा रेड्डी, तेलंगना
3.	चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज	मोहाली, पंजाब
4.	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद	धनबाद, झारखंड
5.	कालासालिंगम अनुसंधान और शिक्षा अकादमी	विरुद्धुनगर, तमिलनाडु
6.	कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन	गुंटूर, आंध्र प्रदेश
7.	मेरठ आभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, मेरठ	मेरठ, उत्तर प्रदेश
8.	विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी (बांगरिया एजुकेशन ट्रस्ट एक इकाई)	जयपुर, राजस्थान
9.	जीआईईटी विश्वविद्यालय	रायगढ़, ओडिशा
10.	मार एफ्रायम कॉलेज	कन्याकुमारी, तमिलनाडु
11.	आदिशंकरा आभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	नेल्लोर, आंध्र प्रदेश
12.	मेपको श्लेंक अभियांत्रिकी महाविद्यालय	सिवकाशी, तमिलनाडु
13.	एसजीटी विश्वविद्यालय	बुधेरा, गुड़गांव, हरियाणा
क्र.सं.	**प्रचालनरत एनजीओ मेजबान संस्थान/संगठन का नाम**	**क्षेत्र**
1.	जागृति सेवा संस्थान	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

आज तक परिचालित एसीआईसी

1. पूरे भारत में परिचालित एसीआईसी को कुल 8.79 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं
2. 100 से अधिक स्टार्टअपों को सहायता प्रदान की गयी है, जिनमें से 40 से अधिक का नेतृत्व महिलाएं/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग कर रहे हैं।
3. एसीआईसी द्वारा 180 से अधिक आउटरीच और धन जुटाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

एसीआईसी–विशिष्ट कार्यक्रम

निम्नलिखित एसीआईसी का उद्घाटन कार्य पूरा हो चुका हैं:

- एसीआईसी जागृति उद्यमिता फाउंडेशन–देवरिया, उत्तर प्रदेश
- एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन–धनबाद, झारखंड
- एसीआईसी कलासलिंगम इनोवेशन फाउंडेशन, तमिलनाडु
- एसीआईसी एमआईईटी फाउंडेशन, मेरठ, उत्तर प्रदेश

एसीआईसी जागृति उद्यमिता फाउंडेशन, देवरिया, उत्तर प्रदेश का 10 सितंबर को उद्घाटन किया गया

ज्ञान और क्षमता निर्माण

एसीआईसी के लिए ज्ञान और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ये कार्यक्रम न केवल हमारे सीईओ को विशेषज्ञों द्वारा उनके सत्रों के दौरान साझा किए गए टूलकिट से सुसज्जित करते हैं अपितु समकक्ष शिक्षण और सहयोग को भी संचालित करते हैं।

ज्ञान और क्षमता निर्माण कार्यक्रम निम्नलिखित तरीकों से चलाए जाते हैं:

- सतत उद्यमिता एक्सप्रेस (एसईई)
- वित्तीय क्षमता निर्माण
- शुक्रवार मंच
- शून्य से एक सत्र
- विनक्यूबेट

सतत उद्यमिता एक्सप्रेस (एसईई)

एसीआईसी सीईओ की कोर टीमों के लिए 27 से 29 सितंबर, 2022 के दौरान एआईसी -पांडिचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 दिवसीय वास्तविक बूट शिविर आयोजित किया गया था। यह बूट शिविर एसीआईसी टीमों को टूलकिट और फ्रेमवर्क प्रदान करने और उन्हें जमीनी नवाचार इकोसिस्टम विकसित करने में उनकी

सहायता करने पर केंद्रित था। बूट शिविर दिवसों को एक अनोखे तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि टीमों को अपने स्वयं के ऊष्मायन कार्यक्रमों को डिजाइन करने का एक व्यापक अनुभव प्रदान किया जा सके।

स्वतंत्र रूप से इन्क्यूबेशन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए व्यापक अनुभव के लिए 4 दिवसीय वास्तविक बूट कैम्प

वित्तीय क्षमता निर्माण: पीएफएमएस और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रशिक्षण

जीएफआर सन्नियमों की गहरी समझ बनाने के लिए एसीआईसी के सीईओ को पीएफएमएस पोर्टल समझाने के लिए एआईएम की वित्त टीम द्वारा सावधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। साथ ही, एसीआईसी के मुद्दों के समाधान और पृच्छाओं का उत्तर देने के लिए वित्त टीमों द्वारा एक नियमित अंतर्क्षेप किया जा रहा है।

शुक्रवार मंच (फ्राइडे फोरम)

एआईएम, हितधारकों को निरंतर विकासशील नवाचार इकोसिस्टम में संसूचित और शामिल रखने के लक्ष्य से एसीआईसी और एआईसी के साथ साप्ताहिक वेबिनार की एक श्रृंखला 'फ्राइडे फोरम' आयोजित करता है। नवाचार/उष्मायन (इनक्यूबेशन) के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने अनुभव और टूलकिट टीमों के साथ साझा करते हैं और एआईसी/एसीआईसी को चर्चा में शामिल करते हैं। इस मंच का उपयोग एआईसीएस/एसीआईसी के साथ नए कार्यक्रमों, योजनाओं और ऐसे अन्य विकासों के विवरण साझा करने के लिए भी किया जाता है।

इन सत्रों में हाल ही में कवर किए गए विषयों में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, मिलेट ईयर 2023, डीपटेक इनोवेशन, इन्वेस्टर्स मीट आदि शामिल हैं। इस वर्ष, आज तक, पूरा इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए नवोन्मेष और उद्यमिता में सक्षताओं और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए 6 फ्राइडे फोरम का आयोजन किया गया है। .

शून्य से एक

एसीआईसी टीम एसीआईसी के सीईओ के लिए एक पाक्षिक पीयर लर्निंग सत्र आयोजित करती है ताकि नवाचार इकोसिस्टम विकसित करते समय अपने ज्ञान और सीख को साझा करने और प्रसारित करने के लिए टीमों का प्रवर्द्धन और प्रोत्साहन किया जा सके। अब तक, एसीआईसी सीईओ के लिए 6 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। ये सत्र सीईओ को उनके विचारों, प्रक्रियाओं, शक्तियों और चुनौतियों को प्रस्फुटित करने में मदद कर रहे हैं।

विनक्यूबेट

'धृति–द करेज विदिन' के सहयोग से जीआईजेड की परियोजना 'हर एंड नाउ', एसीआईसी के लिए महिला केंद्रित ऊष्मायन कार्यक्रमों की आवश्यकता और दायरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए और एक सफल

महिला केंद्रित कंपनियों की स्थापना करने के लिए आवश्यक तत्व और पूर्वापेक्षाएँ को जानने हेतु एक स्व-केंद्रित प्रशिक्षण सत्र है। पहले चरण के प्रशिक्षण को काफी सराहा गया। अधिष्ठापन प्रशिक्षण के बाद एसीआईसी की व्यक्तिगत जरूरतों की पहचान करने के लिए एक स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पादित की जाती है, और फिर धृति और हर एंड नाउ के साथ आमने-सामने के सत्र में उनके मॉडल को एकीकृत और बेहतर बनाने के संभावित तरीकों पर चर्चा की जाती है।

निगरानी और प्रतिक्रिया

एसीआईसी की नियमित निगरानी और मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि एसीआईसी को लक्ष्य उपलब्धि संचालित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो एसीआईसी कार्यक्रम की अभिकल्पना के आधार पर दोष सुधार किया जाता है। वर्तमान में निगरानी विभिन्न तरीकों से की जा रही है, एसीआईसी की प्रगति में सहायता करने के लिए मासिक टच बेस कॉल, पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सहायता करने के लिए त्रैमासिक समीक्षा कॉल की जाती और प्रतिपुष्टि उपलब्ध करवायी जाती है। साथ ही, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से मिलने और बातचीत करने और जमीनी स्तर पर काम को समझने के लिए टीम द्वारा वास्तविक स्थानों पर नियमित दौरे किए जाते हैं।

एक ऑनलाइन निगरानी और मूल्यांकन डैशबोर्ड तैयार किया गया है और यह अंतिम चरण से गुजर रहा है जो टीम को बेहतर प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम बनाते हुए एसीआईसी की प्रगति के स्वचालित ट्रैकिंग और मूल्यांकन को सक्षम करेगा।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेषों की तलाश, चयन, समर्थन और पोषण करना है जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हैं।

एएनआईसी कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य भारत के विकास और इसकी संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों– शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, गतिशीलता, अंतरिक्ष अनुप्रयोग आदि में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है।

एएनआईसी प्रोटोटाइप चरण में नवाचारों की मांग करता है और 1 करोड़ रुपये तक का वित्त पोषण और एआईएम नवाचार इकोसिस्टम से अन्य संबद्ध सहायता प्रदान कर 12 से 18 महीनों के दौरान व्यावसायीकरण चरण तक चयनित स्टार्ट-अप की सहायता करता है।

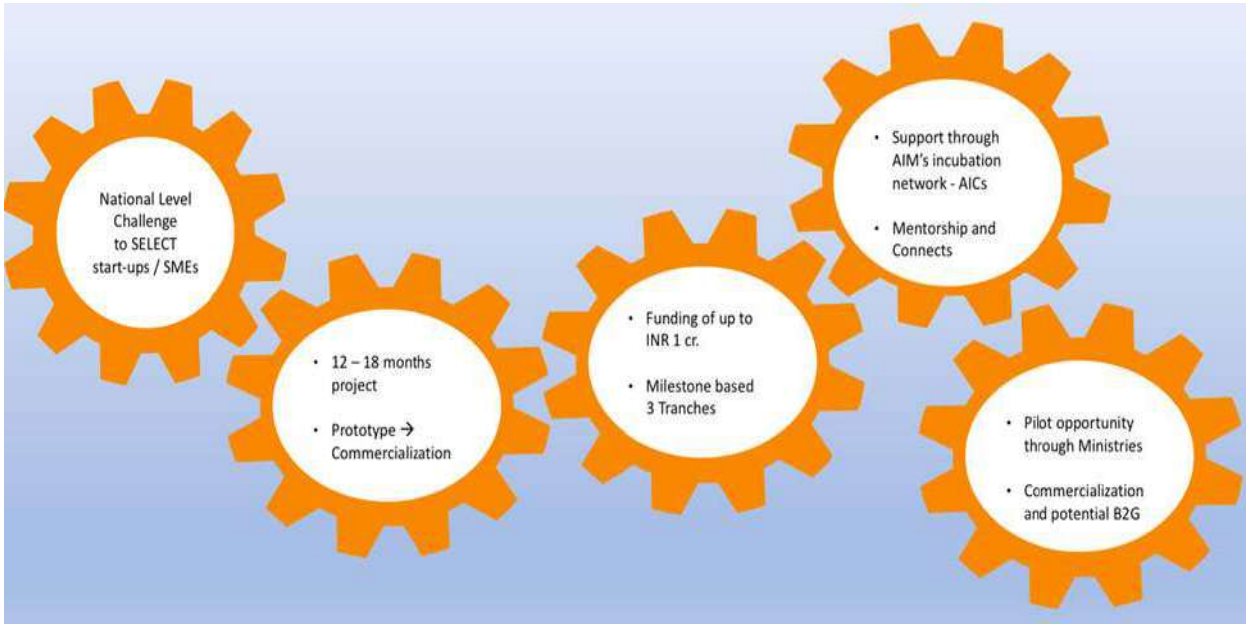

वर्ष 2022 में, 12 सेक्टरों को कवर करते हुए 2 चरणों में एएनआईसी 2.0 के तहत 36 चैलेंजों का शुभारंभ किया गया

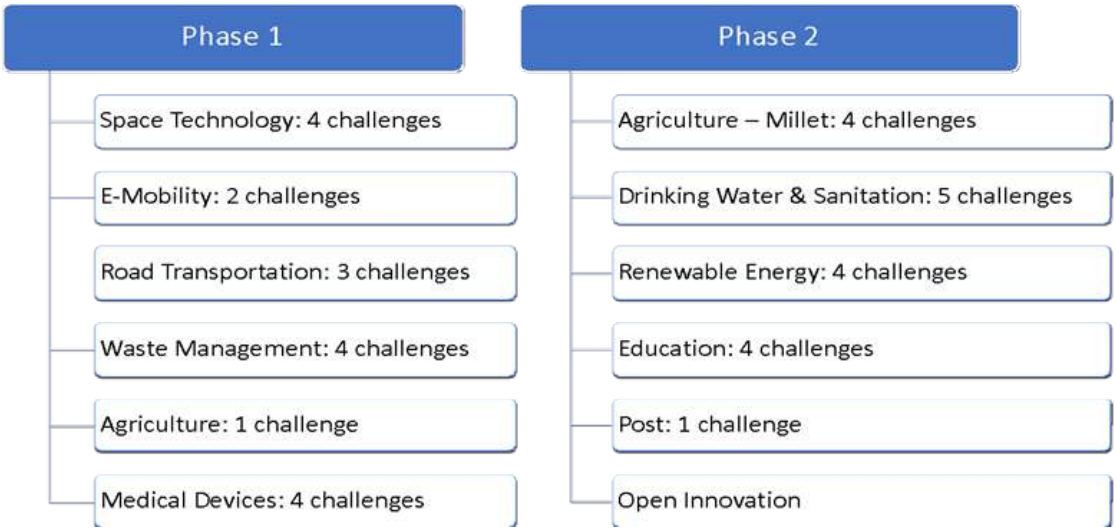

आज तक

- एआई से निधियन और अन्य संबद्ध सहायता के लिए एएनआईसी 2.0–चरण 1 के तहत 82 स्टार्ट-अप/एमएसएमई का चयन किया गया है।
- एएनआईसी 2.0–चरण 2, आवेदन के प्रस्ताव अभी भी आमंत्रित किए जा रहें हैं।
- एएनआईसी 1.0 और एएनआईसी – एराइज (एआरआईएसई) के तहत, एआईएम ने 9 मंत्रालयों के साथ मिलकर 39 चुनौतियों को लॉंच किया था।
- वर्तमान में 33 करोड़ रुपए की अधिक की अनुदान सहायता और अटल इनक्यूबेशन केंन्द्रों (एआईसी) से 51 स्टार्ट-अप/एमएसएमई को सहायता प्रदान की जा रही है
- स्टार्ट-अपों का प्रथम समूह (कोहोर्ट) सफलता के संकेत दे रहें हैं जिन्होंने 400 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं और 150 करोड़ रुपए से अधिक की वाह्य निधि जुटाई गई है।

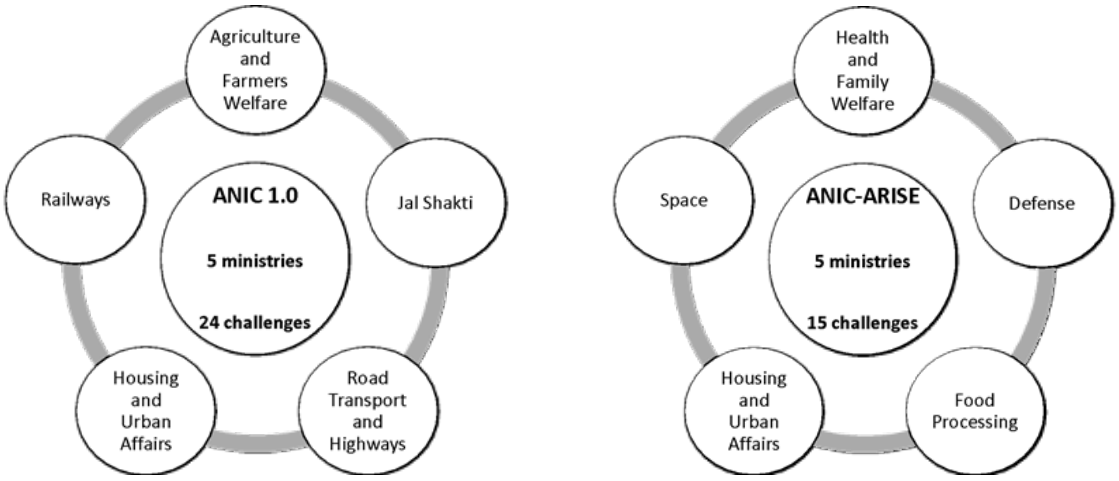

एआईएम ईकोसिस्टम विकास कार्यक्रम (एईडीपी)

एईडीपी संरचित कार्यक्रमों के ढांचे से परे एआईएम लाभार्थियों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने के लिए संबंधित हितधारकों के नेटवर्क का निर्माण करके नवाचार और उद्यमिता ईकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है।

1. कार्यनीतिक कार्यक्रम

क. **'नवोन्मेष हेतु सीएसआर':** भारत में नवोन्मेष पारि-प्रणाली में सीएसआर वित्त-पोषण को बढ़ावा देने और उसका लाभ उठाने के लिए, एआईएम ने सत्त्व कंसल्टिंग के साथ भागीदारी की है–जो कॉरपोरेट्स, इन्क्यूबेटर्स, एक्सीलेटर्स, आरएंडडी संस्थानों और अन्य प्रमुख हितधारकों को इस पारि-प्रणाली में एक साथ लाने और देश में नवोन्मेष के पोषण के लिए–सीएसआर सहयोग को सक्षम बनाएगा।

ख. **एआईएम- आई-लीप:** एआईएम- आई-लीप (इनोवेटिव लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरियल एजिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी) को दो प्रमुख बाधाओं–बाजार और निवेशक पहुंच पर काबू पाने में स्टार्टअप्स की सहायता करने के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया था। एआईएम- आई-लीप, उद्यम और निवेशक डेमो डे की एक श्रृंखला को अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग द्वारा स्टार्टअप रेसॉ और वीसा के साथ साझेदारी में एक संरचित कार्यक्रम के माध्यम से अपनी विभिन्न पहलों, कार्यक्रमों और लाभार्थियों की सहायता करने के लिए आयोजित की जाती है।

एआईएम- आई-लीप ने अब तक निम्नलिखित विविध क्षेत्रों में छह समूहों (कोहोर्ट) को सफलतापूर्वक संपन्न किया है :

1. फिन-टेक
2. साइबर सुरक्षा
3. होम बेस्ड हेल्थकेयर सॉल्यूशन
4. नवाचार के माध्यम से वायु प्रदूषण शमन
5. ऑडियो-टेक में नवाचार
6. स्पोर्ट्स-टेक में नवाचार।

ग. **एआईएम प्राइम:** एआईएम-प्राइम प्लेबुक 10 मई 2022 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में मुख्य अतिथि श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग; और विशिष्ट अतिथि डॉ भारती प्रवीन पवार, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच

एंड एफडब्ल्यू); और डॉ. वी के पॉल, सदस्य, नीति आयोग की उपस्थिति में लॉंच किया गया था। एआईएम प्राइम (प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप) कार्यक्रम का उद्देश्य मिश्रित शिक्षण पाठ्यक्रम का उपयोग करके 12 महीने की अवधि में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से प्रारंभिक चरण के विज्ञान-आधारित, गहन प्रौद्योगिकी विचारों को बढ़ावा देना है।

घ. **एआईएम-आईसीडीके:** इंडो-डेनिश बाइलेटरल ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में, एआईएम ने इनोवेशन सेंटर डेनमार्क (आईसीडीके)–डेनमार्क दूतावास के तहत एक इकाई और डेनमार्क तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) की साझेदारी में भारत में जल नवोन्मेष चुनौतियों को डिजाइन, नियोजित और कार्यान्वित किया। एआईएम-आईसीडीके जल नवोन्मेष चुनौती का दूसरा संस्करण जनवरी और फरवरी 2022 में आयोजित किया गया था।

ङ. **एआईएम–यूएनसीडीएफ:** एआईएम और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) ने अपने महत्वाकांक्षी नवोन्मेषी कृषि–तकनीक कार्यक्रम के लिए अपना पहला एग्रीटेक चैलेंज कॉहोर्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों को महामारी के बाद उनकी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करना है। यह आयोजन 21 दिसंबर, 2021 को किया गया था।

2. नई साझेदारी

एआईएम ने विभिन्न कॉरपोरेट्स और फाउंडेशनों के साथ 50 से अधिक साझेदारियां की हैं और उद्योग जगत के अग्रणियों और संकाय के साथ काम किया है जो बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी, बाजार और निवेशक पहुंच, मॉड्यूल के निर्माण और एटीएल को अपनाकर एआईएम लाभार्थियों की सहायता करते हैं। एआईएम ने पिछले एक वर्ष में 19 नई साझेदारियां की हैं।

एआईएम–समृद्ध (एसएएमआरआईडीएच) साझेदारी के भाग के हिस्से के रूप में 'रिइमेजिंग हेल्थकेयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस' पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। यह श्वेत पत्र भारत में मिश्रित वित्त और स्वास्थ्य देखभाल के संवर्द्धन में इसकी भूमिका पर, मिश्रित वित्त दृष्टिकोण को कैसे अनुप्रयोग किया जाए, यह बता कर और बड़े पैमाने पर मिश्रित वित्तपोषण हासिल करने की वर्तमान चुनौतियों पर वृत्त अध्ययन के साथ एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

क. **एनजीडब्ल्यूए और आईडब्ल्यूए:** नीति आयोग में 12 मई, 2022 को 'नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन (एनजीडब्ल्यूए) ग्लोबल मल्टी-हब प्री-इवेंट' आयोजित किया गया, जिसके बाद वर्चुअल एनजीडब्ल्यूए ग्लोबल मल्टी-हब फाइनल्स 2022 आयोजित किया गया। एनजीडब्ल्यूए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है जिसका लक्ष्य आईडब्ल्यूए (इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन) वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एक्जीबिशन 2022 से पहले, उसके दौरान और बाद में प्रमुख विश्वविद्यालयों और नवोन्मेष केन्द्र से युवा प्रतिभाओं को शामिल करना है। यह आयोजन 5 देशों–मैक्सिको, भारत, दक्षिण कोरिया, केन्या और डेनमार्क में एक साथ आयोजित किया गया। विजेता छात्र टीमों ने और चयनित स्टार्टअप टीमों ने सितंबर, 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित आईडब्ल्यूए वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एक्जिबिशन (विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी) 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

आईडब्ल्यूए 2022 में श्वेत पत्र लॉन्च : 12 सितंबर, 2022 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में अंतर्राष्ट्रीय जल संघ (आईडब्ल्यूए) विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी, 2022 में 'भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य' विषय पर एक श्वेतपत्र जारी किया गया।

एआईएम-नीति आयोग, डेनिश दूतावास, एनएमसीजी और आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञों द्वारा क्यूरेट किया गया यह श्वेतपत्र समग्र रूप से भारत में अपशिष्ट जल शोधन की वर्तमान स्थिति और भावी शोधन संरचनाओं, सह-निर्माण और सहयोग के संभावित मार्गों का विवरण प्रस्तुत करता है।

ख. **आसियान-इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल (एआईएसएफ):** एआईएम ने अपने इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअपों के साथ एआईएसएफ में भाग लिया, जिसमें 10 आसियान देशों के सरकारी निकाय, स्टार्टअप पारि-प्रणाली और उद्योग ने भागीदारी की। यह आसियान-भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रमुख परियोजना है।

ग. **टीएचके फ्यूचर नॉलेज समिट @ जी20:** एआईएम के प्रतिनिधियों ने नवंबर 2022 में जी20 लीडर्स समिट के दायरे में बाली में आयोजित टीएचके फ्यूचर नॉलेज समिट में भाग लिया। टीएचके फ्यूचर नॉलेज समिट जागरूकता आधारित तकनीक के माध्यम से नवोन्मेष के साथ सभी के लिए एक स्थायी और खुशहाल भविष्य प्राप्त करने में मदद करने वाला एक मंच है।

घ. **दुबई/जीआईटीईएक्स:** जीआईटीईएक्स सबसे बड़े और अपनी तरह का एक युवा उद्यमिता, नवोन्मेष और नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, जो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटरसंयुक्त अरब अमीरात में 10-13 अक्तूबर के दौरान (https://www. Northstardubai.com/) आयोजित किया जा रहा है। मिशन निदेशक, एआईएम ने जीआईटीईएक्स यूथएक्स के विशेष अतिथि और वक्ता के रूप में वहां का दौरा किया।

4. राज्य नवोन्मेष मिशन

अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा नवोन्मेष ईकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद करने के लिए एआईएम – राज्य साझीदारी शुरू की है। एआईएम राज्य में एक समग्र नवोन्मेष और उद्यमिता ईकोसिस्टम के निर्माण में बुनियादी ढांचे, प्रक्रियाओं, मानव संसाधन और नीतियों के लिए एक रणनीति बनाने हेतु राज्यों के साथ संयुक्त प्रयासों का प्रस्ताव कर रहा है, और ऐसा करने का प्रस्ताव ज्ञान के हस्तांतरण, विशेषज्ञता, सलाह, और अंतर्संबंध के माध्यम से करता है।

वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (प्रादेशिक नवोन्मेष कार्यक्रम)

वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (वीआईपी) एआईएम की एक पहल है, जिसका लक्ष्य भारत की प्रत्येक अनुसूचित भाषा में संसाधनों और सुदृढ ईकोसिस्टम का निर्माण करके भारत के नवोन्मेष ईकोसिस्टम में लेनदेन की भाषा से रचनात्मक अभिव्यक्ति को अलग करना है।

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र होने के नाते, यह प्रत्येक नवप्रवर्तक को अभिव्यक्ति की अपनी भाषा में नवोन्मेष करने और विचार करने का अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त है और वीआईपी उसी दिशा में एक कदम है। एक समर्थकर्ता के रूप में, वीआईपी का उद्देश्य भाषाओं की बाधाओं को कम करके और क्वांटम लीप के लिए आवश्यक ज्ञान का सही समुच्चय प्रदान करके जमीनी स्तर पर नवोन्मेष को सशक्त बनाना है।

कार्यक्रम संरचना: इस कार्यक्रम को चरणों में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एआईएम न केवल नवोन्मेषक को ज्ञान प्रदान करता है बल्कि इसे एक संपन्न स्थानीय नवोन्मेष ईकोसिस्टम बनाने के लिए भी आगे ले जाता है। यह कार्यक्रम विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाएगा और पिचिंग के लिए तैयार नवोन्मेषक को स्थानांतरित करने के लिए एक क्रमिक कदम उठाएगा।

विवाटेक में भारत

अटल इनोवेशन मिशन ने पेरिस, फ्रांस में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन वीवा टेक्नोलॉजी (विवाटेक) में भारतीय दल का नेतृत्व किया। चूँकि भारत ने अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाया है, यह सम्मेलन भारत वर्ष के अपने पहले आधिकारिक देश के रूप में उत्सब मनाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा।

इस वर्ष, विवाटेक जिसे पेरिस, फ्रांस में 15-18 जून 2022 के दौरान आयोजित किया गया जिसमें, 1,40,000 से अधिक आगंतुकों ने शिरकत किया और यह 149 देशों के 119 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचा। इस कार्यक्रम के इन आगंतुकों में से 26,000 व्यक्तिगत रूप से शामिल थे, और दुनिया भर के 500 से अधिक असाधारण नवोन्मेष, 1400 प्रदर्शक, जिनमें 60% व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, और 400 वक्ताओं की प्रतिभागिता के कारण सृजित समृद्ध संग्रह के परिणामस्वरूप इसे 1.7 बिलियन व्यू मिले।

इस संस्करण में भारत की भागीदारी के आकर्षण के रूप में, भारतीय स्टार्ट-अप की सफलता की गाथाओं का एक विशेष प्रदर्शन और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक अन्य मंडप था, जिसमें भारतीय तकनीकी क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण लोग एक साथ आए थे।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव (भारत सरकार में रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) ने किया। भारतीय मंडप का उद्घाटन एआईएम के प्रबंध निदेशक डॉ. चिंतन वैष्णव द्वारा किया गया था जिन्होंने वीवाटेक के मुख्य मंच पर एक विशेष अभिभाषण भी दिया।

भारतीय मंडप में सभा को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

भारत एक मुक्त, समावेशी और इंटरऑपरेबल वेब पर पहला प्रस्तावक रहा है। द इंडिया स्टैक अपनी पूरी आबादी को डिजिटल युग में लाने के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इंडिया स्टैक के रूप में मुख्य विषय के साथ, जोर डिजिटल सार्वजनिक कल्याण पर था।

इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के अतिथि वक्ताओं और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार की वार्ताओं, जैसे कि फायरसाइड चैट, पैनल चर्चा, सीईओ वार्ता, निवेशक वार्ता आदि में भाग लिया। भारतीय मंडप को सार्वजनिक और निजी संस्थानों के गणमान्य व्यक्तियों जैसे डॉ राम सेवक शर्मा, सीईओ–राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, डॉ कृष्णा एला–संस्थापक और अध्यक्ष–भारत बायोटेक, श्री सौरव रॉय, सीएसआर प्रमुख–टाटा स्टील फाउंडेशन, श्री शरद शर्मा–सह-संस्थापक, आईएसपीआईआरटी, श्री देवांग मोदी, सीईओ – बजाज फिनसर्व हैल्थ आदि और इसरो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नासकॉम, सीआईआई, आईआईटी बेंगलुरु, यूएनडीपी के प्रतिनिधियों ने सुशोभित किया।

भारतीय स्टार्ट-अप प्रतिनिधिमंडल में 15 स्टार्ट-अप शामिल थे जिन्होंने अपने–अपने उत्पादों को वास्तविक रूप से प्रदर्शित किया और 40 स्टार्ट-अप्स ने ई-बूथ के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। स्टार्ट-अप्स को भारतीय मंडप में समर्पित पिचिंग सत्रों में पिच करने का अवसर भी मिला।

फ्रांस और भारत वर्ष 1998 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं; दोनों देश एक साझा डिजिटल संस्कृति साझा करते हैं और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस साझेदारी के आधार पर, वीवा टेक में भारत ने तीन महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों की घोषणा की, जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने की -

क. डिजिटल लोक कल्याण पर साथ मिलकर काम करने के लिए नीति आयोग और फ्रांस के डिजिटल एंबेसडर के कार्यालय के बीच एसओआई

ख. भारतीय मेड टेक स्टार्ट-अप में निवेश को बढ़ावा देने, यूरोपीय बाजारों में भारतीय मेड टेक उत्पादों तक बाजार पहुंच बढ़ाने और संवर्धित वास्तविकता, सिंथेटिक जीव विज्ञान और नवोन्मेष में

उन्नति पर संयुक्त रूप से काम के लिए आंध्र प्रदेश मेड टेक ज़ोन (एएमटीजेड) और एफआईईएन (फेडरेशन इंडो यूरोपियन डू न्यूमेरिक)-फ्रांस बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन।

ग. फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड की स्वीकृति' के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल और फ्रांस के लायरा नेटवर्क के बीच एनडीए आदान-प्रदान किया गया।

भारत का प्रासंगिक स्टार्टअप-2022

खंड 07

कार्यक्षेत्र की उपलब्धियां

प्रस्तावना

विभिन्न वर्टिकल, प्रभाग और एकक, नीति आयोग के सुचारु कार्यकरण के लिए आवश्यक स्तम्भ हैं। प्रत्येक वर्टिकल के पास एक विशेष डोमेन में विशेषज्ञता है और उसे उस क्षेत्र पर तकनीकी इनपुट और विशेषज्ञता प्रदान करने, संबद्ध मंत्रालय/विभाग के साथ संव्यवहार करने और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है।

वर्टिकल आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में नीति आयोग के विकास के लिए आवश्यक अपेक्षित सहायता प्रदान करते हैं जिससे इसे तेजी से कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए कार्यनीतिक नीति विज़न प्रदान करने और प्रासंगिक मुद्दों के समाधान में सहायता मिलेगी।

कृषि

'अभिनव कृषि' पर राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला

आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, नीति आयोग में कृषि वर्टिकल ने 25 अप्रैल 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "अभिनव कृषि" पर एक राष्ट्र-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में श्री परुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन और डेयरी कार्य मंत्री; श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री; श्री आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, गुजरात; श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश; श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश; और श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान, प्राकृतिक खेती में राज्यों की पहल और नवाचारों, मृदा स्वास्थ्य बहाली और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के शमन पर चर्चा की गई। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योग-जगत, किसानों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 1,250 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। यू-ट्यूब पर इस कार्यशाला का लाइव प्रसारण भी किया गया था।

25 अप्रैल 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'अभिनव कृषि' पर राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

प्राकृतिक खेती की उपलब्धियों का सार-संग्रह

जलवायु परिवर्तन और विकृत होते जा रहे मृदा-स्वास्थ के दौर में इस सतत कृषि पद्धति की प्रासंगिकता का एहसास कराते हुए, नीति आयोग वर्ष 2018 से विभिन्न पहलों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा अपनाई गई प्राकृतिक खेती की परिपाटियों का प्रलेखन करने और व्यापक किसान समुदाय के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, वर्टिकल ने

प्राकृतिक खेती की उपलब्धियों का सार-संग्रह जारी किया। द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में उपलब्ध इस सार-संग्रह में धान, गेहूं, बाजरा, फल, सब्जियां, गन्ना और मिश्रित फसल जैसी विभिन्न फसलों की कृषि पद्धतियों को कवर करते हुए 13 राज्यों की 110 उपलब्धियां शामिल हैं।

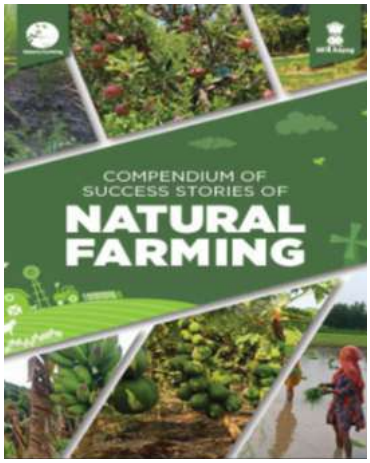

प्राकृतिक खेती की उपलब्धियों के सार-संग्रह का लोकार्पण

पशुधन सुरक्षा के लिए टेलीमेडिसिन

मानव स्वास्थ्य-सेवाओं में, उपचार की टेलीमेडिसिन विधि, विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान, समयोचित सहायता प्रदान करने में सिद्ध हुई है। इसी तरह की विधि को पशुधन क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रस्ताव है। देश के पशु चिकित्सकों और पशु चिकित्सा संस्थानों के ब्यौरों को शामिल करते हुए एक डाटाबेस का निर्माण किया जा रहा है। एक 'पशुधन कल्याण प्रणाली' के सृजन का भी प्रस्ताव है, जहां किसान और चिकित्सक अपना पंजीकरण करा सकते हैं, तथा निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ सूचना सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रायोगिक परियोजना को देश के चुनिंदा राज्यों में संचालित किए जाने, और इस तरह वेबसाइट के डिजाइन और होस्टिंग के कार्य में प्रगति करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में, यह प्रणाली तीन भाषाओं में उपलब्ध है।

मिलेट्स का संवर्धन

भारत सरकार के प्रस्ताव के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। नीति आयोग ने बेहतर खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए जलवायु-अनुकूल परिपाटियों का समर्थन करते हुए भारत के भीतर और बाहर ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता के सुदृढ़ीकरण की सुविधा के माध्यम से मिलेट्स को मुख्यधारा में लाने पर फोकस करते हुए,20 दिसंबर 2021 को विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के साथ एक आशय पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। 19 जुलाई 2022 को अच्छी परिपाटियों की मैपिंग और आदान-प्रदान (एमईजीपी) की पहल शुरू की गई थी। इसके शुभारम्भ समारोह के दौरान, विभिन्न मिलेट्स हितधारकों से तीन श्रेणियों–मिलेट मूल्य श्रृंखला, मिलेट को मुख्यधारा में लाना और मिलेट व्यंजनों में प्रविष्टियां आमंत्रित करते हुए एक वेब पोर्टल का अनावरण किया गया था। एमईजीपी कार्यक्रम क्षेत्रीय सम्मेलनों और एक सार-संग्रह के प्रकाशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों को समानुक्रमित करने और एक साथ लाने का प्रयास करता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

नीति आयोग, नीति आयोग की कैंटीन में मिलेट आधारित व्यंजनों की शुरुआत, मिलेट आधारित व्यंजन बनाने के लिए अनेक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन और 'खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए मिलेट के लाभ उठाने' पर व्याख्यान, रेडी टू ईट और रेडी टू कुक मिलेट उत्पादों की बिक्री के लिए एक मिलेट कार्नर और वेंडिंग मशीन की संस्थापना जैसी आंतरिक मिलेट संवर्धन पहल भी कर रहा है।

बंजर भूमि का हरितकरण और बहाली के लिए कृषि-वानिकी (एग्रोफेरेस्ट्री)

कृषि-वानिकी, एक कृषि-पारिस्थितिकी-आधारित भूमि-उपयोग प्रणाली है जो एक साथ वर्तमान युग की बहुत-सी पारिस्थितिक संबंधी चुनौतियों जैसे खाद्य, प्राकृतिक संसाधन, मृदा क्षरण और पर्यावरण सुरक्षा का समाधान कर सकती है। कृषि-वानिकी द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के महत्व के कारण, भारत सरकार के केंद्रीय बजट घोषणा (वित्त वर्ष-2022-23) में कृषिवानिकी और निजी वानिकी के संवर्धन को अधिमान्य रूप में रेखांकित किया गया है।

नीति आयोग ने रिमोट सेंसिंग डाटासेट और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके, विशेष रूप से कृषि-वानिकी अंतःक्षेपों के लिए उपयुक्त बंजर भूमि की मैपिंग करने और प्राथमिकता देने के लिए "बंजर भूमि का हरितकरण और बहाली के लिए कृषि-वानिकी" पर एक जिओ-पोर्टल विकसित किया है।

मांग और आपूर्ति अनुमानों संबंधी कार्य समूह

'फसल, पशुधन, मत्स्य पालन और कृषि आदानों के मांग और आपूर्ति अनुमान' के संबंध में नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में एक कार्यबल का गठन किया गया था। यह कार्य समूह, प्रोफेसर पीएस बर्थल, निदेशक, आईसीएआर-एनआईएपी की अध्यक्षता में, वर्ष 2025-26, 2030-31 और 2035-36 के लिए फसल, पशुधन, मत्स्य पालन और कृषि आदानों की मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन करेगा और अनुमान प्रस्तुत करेगा।

कृषि में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्यांकन के लिए फ्रेमवर्क का विकास

हालिया वर्षों में, सघन खेती प्रणाली, जिनमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम और पूंजी के रूप में काफी मात्रा में कृषि आदानों का उपयोग किया गया है, इसने हमारी आबादी की वर्तमान कैलोरी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्य के उत्पादन को संभव बनाया है। हालांकि, खेती में आदानों का अविवेकी उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन का एक प्रमुख चालक बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षति और बहुत-सी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का क्षरण हुआ है। किसानों को सतत फसलों/कृषि प्रणालियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने से अग्रिम लागतों में वृद्धि हो सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अनुमान, नीति निर्माताओं को प्राकृतिक खेती जैसी सतत उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देने के दौरान पर्यावरणीय रूप से सतत निर्णय लेने में मदद करेंगे।

नीति आयोग प्राकृतिक खेती में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित कर रहा है। कृषि में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्यांकन में मदद करने वाले टूलकिट विकसित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया गया है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था

आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए, नीति आयोग ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से, रैखिक अर्थव्यवस्था से चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलने में सहायता प्रदान करने के लिए 11 क्षेत्रों नामतः नगरपालिका ठोस और तरल अपशिष्ट; स्क्रैप धातु (लौह और अलौह); लिथियम आयन (ली-आयन) बैटरी; टायर और रबर की रीसाइक्लिंग; जिप्सम; जीवनांत वाहन; इलेक्ट्रॉनिक कचरा; विषाक्त और खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट; प्रयुक्त तेल अपशिष्ट; कृषि अपशिष्ट; और सौर पैनल की पहचान की है। स्वतंत्रता दिवस 2021 पर अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया था।

मार्च 2022 तक 10 कार्यक्षेत्रों में कार्य योजनाओं, जिनमें विनियामक और विकासात्मक दोनों पहलों को शामिल किया गया है, को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद, 16 सितंबर 2022 को नीति आयोग में चक्रीय अर्थव्यवस्था मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इस प्रकोष्ठ के विभिन्न कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था कार्य योजना

10 क्षेत्रों के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित चक्रीय अर्थव्यवस्था कार्य योजना के संबंध में संबंधित नोडल मंत्रालयों द्वारा उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई-अपशिष्ट, टायर, बैटरी और प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) नियम अधिसूचित किए गए हैं; अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नियम तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अग्रलिखित दो खंड: (i) समेकित कार्य योजना और (ii) चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भारत की कार्यनीति (संश्लेषण रिपोर्ट) के साथ कार्यनीतिक कार्य योजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और जारी करने का कार्य चल रहा है।

दीर्घकालिक अल्प-उत्सर्जन विकास कार्यनीतियाँ

नीति आयोग ने 'भौतिक दक्षता और पुनर्चक्रण का अभिवर्धन: चक्रीय अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण' पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे वर्ष 2070 तक निवल-शून्य तक पहुंचने के विजन के साथ यूएनएफसीसीसी सचिवालय को नवंबर, 2022 में प्रस्तुत की गई 'दीर्घकालिक अल्प-उत्सर्जन विकास कार्यनीतियों' के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति के संचालन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सहायता

वाहन स्क्रैपिंग नीति पर चर्चा करने के लिए 17 अक्टूबर 2022 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में नोडल मंत्रालयों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और संचालन के लिए आगे की योजनाओं को समेकित करते हुए एक चर्चा पत्र विकसित किया गया है। राज्य स्तर पर वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्य योजना में शामिल करने हेतु, उनके साथ एक बैठक आयोजित की जानी है।

ज्ञान पोर्टल का निर्माण (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से प्रबंधित)

यह परिकल्पना की गई है कि अगले दो वर्षों में, संबंधित मंत्रालयों के अलग-अलग डाटा पोर्टलों के साथ अंतःक्रिया को सुकर बनाने वाले एक एनालिटिक्स इंजन द्वारा प्राप्त वास्तविक समय विज़ुअलाइज़ेशन के माध्यम से प्राप्त वृत्तीय-स्थिति की सीमा के बारे में नीतिगत मार्गदर्शन और जागरूकता प्रदान करने के लिए एक ज्ञान पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह पोर्टल अन्य प्रासंगिक सामग्री के अतिरिक्त, चक्रीय अर्थव्यवस्था के कार्यान्वयन के संबंध में नीतिगत घोषणाओं पेश करने और उपलब्धियों को साझा करने के लिए एक यूट्यूब चैनल/पॉडकास्ट/ब्लॉग होस्ट करेगा। इसके लिए, मार्च 2023 तक एक संकल्पना पत्र विकसित किए जाने की उम्मीद है।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अनुबंध

नीति आयोग ने 14 नवंबर 2022 को मिस्र में सीओपी27 में भारतीय मंडप में एक सहअवधि कार्यक्रम–भारत की जलवायु अनुकूल सतत जीवन शैली: सतत उपभोग के मार्ग, चक्रीय अर्थव्यवस्था और एक अल्प-कार्बन समाज के लिए परिवर्तनकारी समाधान–में भाग लिया।

एक संघटित वृत्तीय-स्थिति माप फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए फिक्की के साथ एक अन्य पहल की गई थी, जिसका वर्तमान में अभाव रहा है। नवंबर 2022 में ऑटोमोटिव, एफएमसीजी और इस्पात क्षेत्रों के प्राथमिक/द्वितीयक उत्पादकों और रिसाइकलरों के साथ एक हितधारक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी। संघटित वृत्तीय-स्थिति माप फ्रेमवर्क पर एक परामर्श पत्र तैयार किया जा रहा है।

23 दिसंबर 2022 को आयोजित मुख्य सचिवों के वर्चुअल सम्मेलन में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था मिशन का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें वृत्तीय-स्थिति पर तीन सत्र–(i) जैविक और शुष्क अपशिष्ट, (ii) प्रयुक्त जल और (iii)) विशेष श्रेणी अपशिष्ट शामिल थे।

नीति आयोग रेड मड, फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग और ई-अपशिष्ट के लिए तैयार की गई क्षेत्रीय कार्यनीति योजनाओं के संचालन में नोडल मंत्रालयों की सहायता करता है।

भारत द्वारा जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता और विषय की प्रासंगिकता को देखते हुए, यह प्रकोष्ठ, संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जी -20 चर्चाओं के लिए संक्षिप्त विवरण और संकल्पना पत्र तैयार करने में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सहायता प्रदान करेगा।

डाटा प्रबंधन, विश्लेषण और सीमांत प्रौद्योगिकी

यह वर्टिकल मुख्य रूप से (क) डाटा प्रबंधन, बेहतर सांख्यिकीय प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से संबंधित मुद्दों, और (ख) अनुसंधान को बढ़ावा देने और सीमांत प्रौद्योगिकियों को अपनाने से संबंधित है। इसके मुख्य प्रकार्यों में व्यापक रूप से निम्नलिखित को कवर किया जाता है:

- सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग-जगत के विशेषज्ञों के सहयोग से नीति दस्तावेज और कार्यनीति दस्तावेज तैयार करना तथा संगोष्ठी और कार्यशाला आयोजित करना।
- सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संस्थानों और उद्योग निकायों के सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित उपयोग-मामलों को हल करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रौद्योगिकियों में प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रबंधन करना। परियोजनाओं के अनुभवों को नीति दस्तावेज़ के रूप में प्रलेखित करना।
- ज्ञान और नवाचार समर्थन प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचार-मंच, शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाजों और उद्योग के साथ सहयोग करना।
- डाटा प्रबंधन और उपयोग का प्रलेखन करना, और बेहतर सांख्यिकीय प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- सरकार में क्षमता निर्माण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

कार्यक्षेत्र की विभिन्न उपलब्धियाँ नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

ड्रोन के संबंध में अनुभव स्टूडियो

सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने हेतु, माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा

10 मई 2022 को नीति आयोग में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत की उपस्थिति में ड्रोन के संबंध में एक अनुभव स्टूडियो का शुभारम्भ किया गया। इसके शुभारम्भ के बाद उद्योग-जगत के प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा की गई।

ड्रोन के संबंध में अनुभव स्टूडियो का शुभारम्भ

ड्रोन मिशन

भारत के बाजार आकार और उदार विनियामक व्यवस्था का लाभ उठाने, ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और उत्प्रेरक के रूप में सरकार की भूमिका को सक्षम करने के लिए नीति आयोग में भारत के लिए एक ड्रोन मिशन स्थापित किया गया है। यह मिशन विनियामक संवाद, केंद्र-राज्य संचार, सार्वजनिक खरीद को कारगर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

राष्ट्रीय डाटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एनडीएपी)

नीति आयोग ने 13 मई 2022 को राष्ट्रीय डाटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म (एनडीएपी) का शुभारम्भ किया। इस प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य डाटा को सुलभ, अंतर-प्रचालनात्मक, संवादमूलक और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराकर, सार्वजनिक सरकारी डाटा तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण करना है। यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों के डाटासेट को होस्ट करता है, उन्हें सुसंगत रूप से प्रस्तुत करता है, तथा एनालिटिक्स और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए टूल प्रदान करता है। इसके सार्वजनिक स्तर पर शुभारम्भ के बाद अगस्त 2021 में प्लेटफ़ॉर्म का बीटा संस्करण रिलीज किया गया, जिस तक परीक्षण और फीडबैक के लिए सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं को पहुँच प्रदान की गई थी।

एनडीएपी यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग-मामला आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है कि प्लेटफ़ॉर्म पर प्रदर्शित किए गए डाटासेट सरकार, शिक्षा, पत्रकारिता, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के डाटा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। सभी डाटासेट को एक सामान्य स्कीमा के लिए मानकीकृत किया जाता है, जिससे डाटासेट को सम्मिश्रित करना और परस्पर-कार्यक्षेत्रीय विश्लेषण करना आसान हो जाता है।

प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ उपाध्यक्ष, नीति आयोग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग; डॉ. अनंत नागेश्वरन, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार; और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। यह वेबसाइट https://ndap.niti.gov.in पर उपलब्ध है।

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी)

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मई 2020 में नीति आयोग को विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की भूमिका का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था। लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी), नीति आयोग द्वारा परिकल्पित प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों में से एक था। सभी हितधारकों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने और अलग-अलग स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा प्रणालियों में बहु-मोडल परिवहन की दृश्यता का अभिसरण करने के उद्देश्य से नीति आयोग में इसकी परिकल्पना और विकास किया गया था। यूएलआईपी प्लेटफॉर्म की परिकल्पना, उद्योग-जगत के प्लेयर्स को विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध लॉजिस्टिक और संसाधनों से संबंधित जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए की गई है।

परियोजना को कार्यान्वियन हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) को सौंप दिया गया था। वर्तमान में, हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए 1600 से अधिक डाटा फील्ड को कवर करते हुए 100 से अधिक एपीआई के माध्यम से सात मंत्रालयों की 32 प्रणालियों को एकीकृत किया गया है। यूएलआईपी का एक विशिष्ट पोर्टल है जो डाटा अनुरोध की प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाता है। यह पोर्टल https://goulip.in/ पर उपलब्ध है। यूएलआईपी को 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के हिस्से के रूप में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारम्भ किया गया था।

फिनटेक ओपन शिखर सम्मेलन

नीति आयोग ने 7 से 28 फरवरी 2022 तक 'फिनटेक ओपन' नामक शीर्षक से तीन सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल फिनटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। फिनटेक ओपन, जो अपनी तरह की सर्वप्रथम पहल है, के माध्यम से सहयोग , विचारों के आदान-प्रदान और नवाचार के लिए, विनियामकों, फिनटेक पेशेवरों और उत्साही लोगों, उद्योग जगत के दिग्गजों, स्टार्ट अप समुदाय और डेवलपरों को एक मंच पर लाया गया।

इस शिखर सम्मेलन का शुभारम्भ माननीय केंद्रीय रेलवे, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष, की उपस्थिति में किया।

अर्थ एवं वित्त प्रकोष्ठ

अर्थ और वित्त प्रकोष्ठ का आशय यह सुनिश्चित करना है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एक स्थायी पथ पर अग्रसर रहे। यह प्रकोष्ठ उत्पादकता बढ़ाने, पूंजी निर्माण में तेजी लाने, कार्यनीतिक क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, वित्त तक पहुंच में सुधार करने, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी लागत कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है।

वृहद आर्थिक विश्लेषण

अर्थव्यवस्था की स्थिति

नीति आयोग में वरिष्ठ अधिकारियों को भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के वास्तविक समय के प्रदर्शन विश्लेषण के संबंध में एक आवधिक अभ्यास प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन 9 कार्यक्षेत्रों में 40-50 की उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों के विश्लेषण पर आधारित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था: वैश्विक अनिश्चितता के बीच समर्थ्य और नेतृत्व

नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 4 नवंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष वैश्विक स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों का आकलन प्रस्तुत किया। वैश्विक प्रतिकुलताओं का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न विकासशील परिदृश्य और कार्यनीतियां तैयार की गई और इएंडएफ सेल द्वारा घरेलू भावनाओं का विश्लेषण किया गया।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए समग्र आर्थिक परिदृश्य और रोडमैप

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2022 को वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) के समक्ष मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। लोकसभा सचिवालय को एक पृष्ठभूमि नोट प्रदान किया गया।

भारत की निवेश और बचत दर तथा चालू खाता शेष

कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव इंडिया@75 में भारत के बचत और निवेश अंतर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुतीकरण दिया गया था। इस प्रस्तुतीकरण में घरों, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दर का विश्लेषण और निजी क्षेत्र के निवेश में मंदी को उजागर किया गया था।

सीपीएसई का कार्यनीतिक विनिवेश और प्रदर्शन में सुधार

अर्थ और वित्त प्रकोष्ठ को कार्यनीतिक क्षेत्र के सीपीएसई के विनिवेश के संबंध में विश्लेषण करने और सिफारिशें करने का अधिदेश दिया गया है। इसकी सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ चर्चा की जाती है और तदोपरांत ये सिफारिशें निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत की जाती हैं।

गैर-कार्यनीतिक क्षेत्र में, विशिष्ट मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन सीपीएसई के निजीकरण, विलय या नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करने वाले अधिकारियों के समूह (सीजीओ) की समिति को बंद करने की सिफारिश की जाती है।

जी20 और बहुपक्षीय संस्थानों के साथ विभिन्न अनुबंध

भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता

नीति आयोग का जी20 प्रकोष्ठ भारत द्वारा आगामी जी20 की अध्यक्षता के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में कार्यरत है। इनमें जी20 सचिवालय (मसौदा इश्यू नोट्स और अन्य प्रमुख दस्तावेजों पर) के साथ-साथ लॉजिस्टिक सहायता (कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेना, कार्यशालाओं का आयोजन करना, आदि) को महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना शामिल है।

जीG20 प्रकोष्ठ ने 23 जुलाई, 2022 को जी20 सचिवालय, विदेश मंत्रालय के सहयोग से जी20 कार्यकारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए एक उच्च-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, डॉ पीके मिश्रा द्वारा किया गया तथा विभिन्न मंत्रालयों और नीति आयोग के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुच्छेद IV परामर्श

भारत अनुच्छेद IV परामर्श 2022 के लिए 21 सितंबर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को मसौदा समापन टिप्पणी के संबंध में आईएमएफ मिशन पर इनपुट प्रदान किए गए थे।

एडीबी की भारत देश भागीदारी कार्यनीति, 2023-2027

भारत-एडीबी साझेदारी के लिए कार्यनीतिक दिशाओं और रोडमैप की संकल्पना पर एक नोट तैयार किया गया था। वित्तीय, तकनीकी, सलाहकार और ज्ञान समर्थन में अपनी बहुपक्षीय विशेषज्ञता से भारत को लाभान्वित करने के संबंध में एडीबी के अनुरूप नीतियां और विचार तैयार किए गए थे।

सतत और समावेशी विकास के लिए दक्षिण एशिया का मार्ग: आईएमएफ

दक्षिण एशियाई क्षेत्र के मुद्दों और चुनौतियों के वर्तमान संदर्भ को रेखांकित करते हुए एक नोट तैयार किया गया था और महामारी के दौरान क्षेत्र की छोटी अर्थव्यवस्थाओं के जीवन और आजीविका की सुरक्षा में भारत की भूमिका और विकासात्मक सहायता के साथ-साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सतत विकास की योजना तैयार करने के लिए एक नोट तैयार किया गया था।

अर्थनीति संबंधी सलाहकार समूह की बैठक

नीति आयोग ने 21 अक्टूबर 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 'अर्थशास्त्री हडल' शीर्षक से एक वर्चुअल गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें शिक्षा-जगत, उद्योग-जगत, विचार-मंच और बहुपक्षीय संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे।

मूडीज की वार्षिक समीक्षा श्रेष्ठ क्रेडिट रेटिंग पर चर्चा

भारत की श्रेष्ठ बांड रेटिंग की वार्षिक समीक्षा के लिए आर्थिक कार्य विभाग के साथ-साथ मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस (एमआईएस) के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। अर्थनीति और वित्त प्रकोष्ठ ने वैश्विक प्रतिकूलताओं का मुकाबला करने में भारत की मुख्य ताकत और समर्थ्य के कारकों को उजागर करते हुए भारत की क्रेडिट रेटिंग की फिर से पुष्टि करने पर मूडीज को महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और राय प्रदान की।

शिक्षा

शिक्षा वर्टिकल, नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से एक अनुकूल ज्ञानार्जन परिवेश की सुविधा प्रदान करने का आशय रखता है ताकि लोग अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान कर सकें। शिक्षा वर्टिकल, स्कूल तत्परता, सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा, महत्वपूर्ण और उच्च-क्रम सोच, और बच्चों के बीच ग्रेड-स्तर की योग्यता की सुविधा के लिए प्रयास करता है। यह उच्च गुणवत्ता, सुलभ, न्यायसंगत, जवाबदेह और सस्ती शिक्षा प्रणाली के माध्यम से युवाओं को रोजगार कौशल, अनुसंधान प्रवृत्ति और विषय वस्तु विशेषज्ञता के साथ सशक्त बनाने का आशय रखता है।

स्कूली शिक्षा

साथ शिक्षा 2.0 परियोजना

तीनों राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, साथ-ई 2.0, परियोजना का दूसरा चरण, दो वर्ष के लिए अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया। यह अक्टूबर 2022 में संपन्न हुआ और साथ 2.0 के तहत छात्र और शिक्षक ज्ञानार्जन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं जो इस प्रकार हैं:

झारखंड:

- सहायक आचार्य संवर्ग में 50,000 नए पदों की पेशकश की गई।
- अत्याधुनिक स्कूल उन्नयन के साथ 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं और प्रधानाध्यपक/प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं।
- जेसीईआरटी में 72 प्रतिशत पद भरे जा चुके हैं।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन छात्र ज्ञानार्जन (पोस्ट-कोविड) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- शिक्षकों को ज्ञानार्जन परिणाम-आधारित सुधारात्मक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।
- सुधारात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए साथ परियोजना के चरण I और चरण II के माध्यम से ज्ञानसेतु और स्तर-आधारित सुधार किए गए हैं।
- कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के लिए शिक्षक पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के लिए निर्देश पुस्तकें तैयार की गई हैं।
- छात्र ज्ञानार्जन परिणामों में सुधार के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक पहल की गई है।
- कोविड के दौरान ज्ञानार्जन सुनिश्चित करने के लिए स्तर-आधारित शिक्षा का विकास किया गया और डिजिटल सामग्री परिचालित की गई है।

केजीबीवी और जिला स्कूलों का विकास और उन्नत अवसंरचना

सामुदायिक पीटीएम और खेल आयोजन

शिक्षकों का क्षमता निर्माण

व्यावसायिक शिक्षा

मध्य प्रदेश:

- कोविड के दौरान, पूरे शैक्षणिक कैलेंडर में 4 चरणों में ज्ञानार्जन की पुन:प्राप्ति के प्रयास किए गए हैं। उचित स्तर पर ज्ञानार्जन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षाकक्ष में कक्षा पाठ्यचर्या का संचालन किया जाता है।
- जमीनी स्तर पर डाटा-आधारित निर्णय लेने के लिए जिला रिपोर्ट कार्ड का उपयोग महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और जिला परियोजना समन्वयक (डीपीओ) को महत्वपूर्ण साथ मॉड्यूल के बारे में अनुकूलित किया गया है। ब्लॉक, क्लस्टर और डीपीओ के लिए रिक्त पदों को भरा गया है।
- प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी तक पहुंचने के लिए वर्चुअल फील्ड सपोर्ट (वीएफएस) प्रणाली आधारभूत रही है।
- सिविल अवसंरचना, सीएम राइज लॉन्च और स्टाफिंग के लिए मास्टर प्लान के साथ जमीनी स्तर पर सीएम राइज स्कूल पहल को लागू किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक 360 सीएम राइज स्कूल कार्यशील हो जाएंगे।
- कोविड के बाद हमारा घर हमारा विद्यालय 2.0 का भी शुभारम्भ किया गया।

विभागीय बैठकों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना

वर्चुअल फील्ड सपोर्ट

सीएम राइज स्कूल

ओडिशा:

- राज्य ने कक्षा 1-9 के लिए अपना ज्ञानार्जन पुन:प्राप्ति कार्यक्रम शुरू किया है।
- राज्य ने सभी निर्देशिकाओं में डाटा शामिल करके जिला स्कोरकार्ड का दायरा बढ़ाया है। इसके संबंध में 32 संकेतकों का आकलन किया जाना है।
- राज्य के सभी शिक्षकों को ज्ञानार्जन पुन:प्राप्ति कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- शिक्षक, छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए डिजिटल माध्यमों और एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।
- कोविड के दौरान ज्ञानार्जन को बढ़ावा देने के लिए बहुत-सी पहलें जैसे कि यूट्यूब लाइव, रेडियो पाठशाला, वीडियो कॉल के माध्यम से शिक्षक-छात्र कनेक्ट आदि शुरू की गईं।

ज्ञानार्जन पुन:प्राप्ति कार्यक्रम

क्षमता निर्माण कार्यशालाएं

विभागीय बैठकों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना

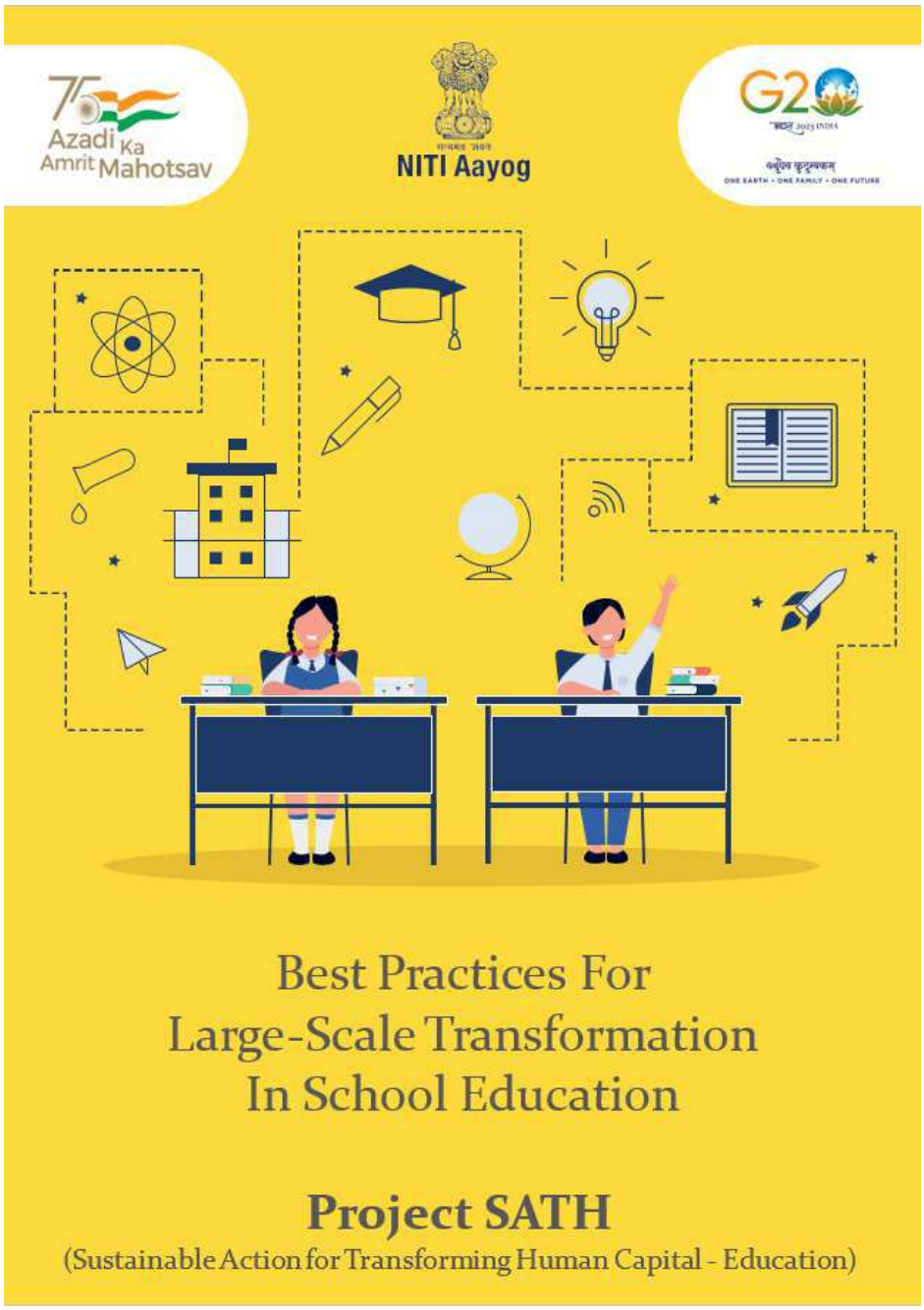

नीति आयोग स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को जारी करने की प्रक्रिया में है।

साथ परियोजना–अरुणाचल

जुलाई 2022 में नीति आयोग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और रीच टू टीच के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि नीति आयोग की राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाओं (डीएसएसएस) के तहत सभी सरकारी स्कूलों को कवर करते हुए बड़े पैमाने पर स्कूली शिक्षा का कायाकल्प किया जा सके। तीन वर्ष (2022-25) की साझेदारी वाली परियोजना में, नीति आयोग ने ज्ञान भागीदार रीच टू टीच के साथ, अरुणाचल प्रदेश में कक्षा 1–12 से ज्ञानार्जन वृद्धि के लिए डिजाइन और परियोजना प्रबंधन सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिसमें राज्य के 2 लाख से अधिक बच्चे शामिल हैं। मुख्य अंतःक्षेपों में राज्य पीएमयू की स्थापना, स्कूल तत्परता कार्यक्रम (एसआरपी) (कक्षा 1-5), विजनिंग और पोस्ट एनएएस रोडमैप कार्यशाला–राज्य और जिला रोडमैप, कक्षा 10 और 11 के लिए बोर्ड परीक्षा पैक की शुरुआत करना, बच्चों की ज्ञानार्जन हानि को समझने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण करना शामिल है।

नीति आयोग, अरुणाचल प्रदेश के माध्यमिक छात्रों और शिक्षकों के लिए राज्य टूलकिट तथा रीच टू टीच के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर

कॉनवोक 2021-2022

भारती फाउंडेशन के साथ नीति आयोग ने एक अनूठा मंच, कोनवोक 2021-2022 का निर्माण किया, जहां शिक्षाशास्त्री और शिक्षाविदों ने अपनी सर्वोत्तम परिपाटियों और शोध पत्रों को साझा किया।

कॉनकोव 2021-22 में चार सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न विषयों जैसे कोविड के दौरान आने वाली चुनौतियाँ, तकनीकें-जो शिक्षण-ज्ञानार्जन प्रक्रियाओं में सुधार कर सकती हैं, शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई।

विजन 2047 और रोडमैप

वर्ष 2022 में आजादी के 75 वर्ष पूरे कर भारत अब 2047 में आजादी के 100 साल की राह पर है, जिसे प्रधानमंत्री ने देश का अमृतकाल नाम दिया है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे भारत को वर्ष 2047 तक एक आर्थिक और ज्ञान महाशक्ति, और एक विकसित राष्ट्र बनने के उद्देश्य से सुदृढ़ किया जाना चाहिए। वर्टिकल ने भारत सरकार द्वारा गठित 'सचिवों के क्षेत्रीय समूह' के साथ कार्य किया, जो कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए भारत का विजन 2047 और रोडमैप तैयार करने के लिए क्षेत्रीय विश्लेषण और कार्यनीतियों के संबंध में कार्य करता है।

ऊर्जा

यह वर्टिकल भारत को ऊर्जा-सुरक्षित बनाने के लिए सभी हितधारकों को उच्च-गुणवत्ता वाली नीतिगत सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य एक कुशल, सतत और स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देना है। यह वर्टिकल ऊर्जा आयात को कम करने, ऊर्जा की वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करता है। यह ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अंतर-कार्यक्षेत्रीय मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है। नीतिगत ढांचे को इस तरह तैयार किया गया है कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कुशल बाजारों के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति की जाए।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पहल–हरित हाइड्रोजन कार्यनीति

जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए तकनीकी सफलताओं की आवश्यकता होगी। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा विकल्प है जो कठिन से कठिन क्षेत्रों–विशेष

रूप से उर्वरक, रिफाइनरियों, स्टील और हैवी ड्यूटी परिवहन जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजिंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। माननीय प्रधान मंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनना चाहिए। नीति आयोग नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की पहल के माध्यम से हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग ने आरएमआई के परामर्श से 'हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए कार्यनीति (स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन)' रिपोर्ट भी जारी की है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

जलविद्युत कार्यक्षेत्र संबंधी सलाहकार समूह: हाइड्रो पावर पर एक सलाहकार समूह का गठन डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य (ऊर्जा), नीति आयोग के नेतृत्व में किया गया है, जो हाइड्रो परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार और देश में अप्रयुक्त हाइड्रो पावर क्षमता का दोहन करने के उपायों का सुझाव देगा। यह सलाहकार समूह (क) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में नदी घाटी विकास और जलविद्युत परियोजना के लिए एक कार्य योजना और (ख) वित्त पोषण के तौर-तरीकों के डिजाइन पर कार्य कर रहा है, ताकि जलविद्युत परियोजनाएं, जहां डीपीआर/तकनीकी-आर्थिक मंजूरी/वित्तीय समापन औसत, राष्ट्रीय विद्युत खरीद शुल्क के बराबर हासिल किया जाना बाकी है, के दीर्घावधि उत्पादन प्रशुल्क बनाए रखा जा सके।

विद्युत संकट के कारण विश्लेषण और रोकथाम के कदम: 2022-23 की पहली तिमाही में, उच्च मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयले की उपलब्धता की कमी के कारण भारत को विद्युत संकट का सामना करना पड़ा। नीति आयोग ने विद्युत की कमी के संभावित कारणों पर एक विस्तृत अध्ययन किया और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए निवारक कदमों का सुझाव दिया।

भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र

नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ईसरो) के साथ मिलकर भारत का एक व्यापक भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। इसमें नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय विद्युत संयंत्रों, तेल और गैस डाउनस्ट्रीम क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जीवाश्म ईंधन संसाधनों और भारत में अन्य ऊर्जा संपत्तियों पर स्थानिक और गैर-स्थानिक डाटा का परिदृश्य शामिल है। ये मानचित्र संसाधनों की योजना के लिए उपयोगी हैं जिनमें आगामी सोलर पार्कों, कोयला ब्लॉकों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए अवसंरचना योजना शामिल हो सकती है।

टाइम्स-वेदा का उपयोग करते हुए ऊर्जा प्रणाली मॉडल

नीति आयोग, टाइम्स-वेदा का उपयोग करते हुए एक आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र लागत अनुकूलन मॉडल विकसित कर रहा है। इस मॉडल में अधोमुखी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है और अर्थव्यवस्था के सभी पांच क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों को शामिल किया जाता है।

नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) लक्ष्य नियोजन

नीति आयोग ने राज्यवार क्रय ऊर्जा (आरई) क्षमता का अनुमान लगाया है जो राज्य में उपलब्ध क्षमता के भीतर से उत्पन्न की जा सकती है और विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित आरपीओ लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर नीति आयोग द्वारा की गई यह कवायद अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा- जिसकी आरपीओ लक्ष्य और आवश्यक भंडारण क्षमता को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसे विस्तृत इनपुट भी प्रदान करती है।

कोयले से विद्युत उत्पादन की लागत और इसकी परिवहन की तुलना में एक राज्य से दूसरे राज्य में कोयले की परिवहन लागत का शोध अध्ययन: नीति आयोग ने ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराए जा सकने वाले परिवहन के इष्टतम मोडल संयोजन का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कोयला गैसीकरण: स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में कोयले के वैकल्पिक स्वच्छ उपयोग को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोयले के जलने की तुलना में कोयला गैसीकरण को एक स्वच्छ विकल्प माना जा सकता है क्योंकि यह कोयले की रासायनिक विशेषताओं का उपयोग करता है। कोयला गैसीकरण पर प्रयासों में तेजी लाने के लिए सदस्य (वीकेएस) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति ने विशेष रूप से कोयला गैसीकरण पर कई नीतिगत सिफारिशें की हैं। सीआईएल की चार और एनएलसीआईएल की एक कोयला गैसीकरण परियोजना वर्तमान में निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है।

शासन और अनुसंधान

शासन प्रभाग, केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की नीतियों और कार्यक्रमों, नौ केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों-उर्वरक विभाग, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य विभाग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग के संबंध में उनके कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित मुद्दों की देख रेख है। अनुसंधान प्रभाग, नीति आयोग (या आरएसएनए) की अनुसंधान योजना की देखरेख करता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न शोध अध्ययनों का समर्थन करना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत कवरेज और लाभार्थी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम प्रदान करके खाद्य सुरक्षा के मुद्दों का निपटान करता है। एनएफएसए अधिनियम ने लाभार्थियों को अत्यधिक रियायती कीमतों पर उचित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया।

नीति आयोग ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थी पहचान मानदंडों के सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए एनएफएसए के तहत लाभार्थी समावेशन/वर्जन मानदंड का अध्ययन किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थी पहचान मानदंड के सामंजस्य से सही लाभार्थियों के कवरेज में अंतर को कम करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार एनएफएसए के तहत लक्ष्यीकरण में सुधार होगा।

खाद्य और पोषण सुरक्षा पर उच्च स्तरीय नेपाल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संवादात्मक बैठक

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) भारत ने खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रगति को समझने के लिए माननीय कृषि और पशुधन विकास मंत्री, नेपाल के नेतृत्व में "नेपाल अध्ययन मिशन" के रूप में नेपाल सरकार के एक उच्च-स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। तदनुसार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 02 जून 2022 को नीति आयोग में एक संवादात्मक बैठक का आयोजन किया गया। माननीय कृषि और पशुधन विकास मंत्री, नेपाल ने भारत के प्रयासों की सराहना की और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत और नेपाल के बीच सहयोग और समन्वय का आह्वान किया।

उर्वरक क्षेत्र से संबंधित मुद्दे

उर्वरक विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, और भूमि संसाधन विभाग के सचिवों के साथ प्रस्तावित **"उर्वरक में डीबीटी के लिए किसान पंजीकरण"** पर चर्चा करने के लिए 01 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। प्रस्तावित किसान पंजीकरण, सब्सिडी-वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल और पारदर्शी बना देगा।

एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन (आईपीएनएम) अधिनियम 2022 का उद्देश्य एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देकर भारत की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना है जो उर्वरक उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा/मृदा स्वास्थ्य, इष्टतम उपज और किसानों के आर्थिक कल्याण का ध्यान रखता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने प्रस्तावित 'एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन अधिनियम 2022' पर चर्चा करने के लिए उर्वरक विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

उर्वरक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति , जिसमें नीति आयोग भी एक प्रमुख सदस्य है, का गठन किया गया है, जो प्रत्येक पोषक तत्व नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटेशियम (के) और सल्फर (एस) के लिए प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर की सिफारिश करती है और नीति आयोग ने वर्ष के दौरान आयोजित की गई समिति की बैठकों में भाग लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य उचित समय पर उचित मूल्य पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश में उर्वरक के सुचारू उत्पादन को बढ़ावा देना और कमी/अभाव की स्थिति में उर्वरकों के निर्बाध और समय पर आयात और अंत में उर्वरक के संतुलित/सही ढंग से उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

उद्योग-जगत और शिक्षा-जगत के साथ अनुबंध

i. नीति आयोग के सहयोग से, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 23 मार्च, 2022 को कॉलेज के छात्रों के लिए शहीद सुखदेव स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। 'ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया–नीति आयोग की भूमिका' के अवसर पर मुख्य भाषण वरिष्ठ सलाहकार (जी एंड आर), नीति आयोग द्वारा दिया गया।

ii. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के सहयोग से, नीति आयोग ने राष्ट्र निर्माण में नीति आयोग की भूमिका, कार्यों और कार्यनीतियों से अवगत कराने के लिए बांग्लादेश सरकार के 27 वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। इस विचार-विमर्श के दौरान, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने अध्यक्षता की।

iii. नीति आयोग के समर्थन से, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) ने 23-25 मार्च 2022 के दौरान मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूरु में कुलपतियों की 96वीं वार्षिक बैठक और कुलपतियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी 2022 का आयोजन किया। विश्वविद्यालयों के भाग लेने वाले कुलपतियों के लाभ के लिए वरिष्ठ सलाहकार (जी एंड आर) द्वारा समानता और सतत समाज सुनिश्चित करने के लिए 'उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से एसडीजी को साकार करना' पर एक विशेष व्याख्यान (एचईआई) दिया गया था।

बंद यूरिया इकाइयों का पुनरुत्थान

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति, रामागुंडम, तालचेर, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में पांच नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है और इस प्रक्रिया के दौरान आने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान कर रही है। इनमें उर्वरक निगम इंडिया लिमिटेड की तीन बंद यूरिया इकाइयां और हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड की दो बंद इकाइयां शामिल हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संघ द्वारा स्थापित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान अंतर-मंत्रालयी समिति की कई बैठकें आयोजित की गईं। एफसीआईएल, टीएफएल और तलचर परियोजना के ऋणदाताओं के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले प्रतिस्थापन करार की मंजूरी के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति (ईसीओएस) की एक बैठक आयोजित की गई थी।

विभिन्न संगठनों के साथ नेटवर्किंग और साझेदारी फ्रेमवर्क के लिए दिशानिर्देश

सरकार के एक शीर्ष थिंक-टैंक के रूप में, नीति आयोग की भूमिका बेहद व्यापक है और इसमें सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम फ्रेमवर्क और पहलों को डिजाइन करने, उनकी प्रगति और प्रभावकारिता की निगरानी करने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों और अन्य भागीदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का सृजन करने को कवर किया जाता है। इस संदर्भ में, नीति आयोग और प्रमुख ज्ञान, अनुसंधान, परोपकारी, कॉर्पोरेट, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों के बीच नेटवर्किंग और साझेदारी के लिए अनुबंध फ्रेमवर्क के लिए दिशानिर्देश विकसित और जारी किए गए हैं। दिशानिर्देशों को नीति आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

कोविड-19 प्रबंधन

निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ साझेदारी को मजबूत करने के माध्यम से कोविड-19 प्रबंधन के लिए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह-7 का गठन किया गया था। सीएसओ, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ और सभी हितधारकों के साथ मज़बूत सहयोग के माध्यम से 39 बैठकें आयोजित की गई हैं।

नीति आयोग की नई अनुसंधान योजना (आरएसएनए) दिशानिर्देश 2021

स्वयं को ज्ञान और नवाचार हब के रूप में स्थापित करने के नीति के अधिदेश के अनुरूप, दिशानिर्देशों का नया सेट, अर्थात् 'नीति आयोग की अनुसंधान स्कीम 2021' का आरम्भ किया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों की सहायता करने के साथ-साथ विभिन्न आयोजनों के लिए नीति के प्रतीक चिह्न (लोगो) के उपयोग के माध्यम से गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा संस्थागत और व्यक्तिगत आधारित अनुसंधान सहित व्यापक-आधार अनुसंधान कार्य करना है। वर्ष 2022-23 (31 दिसंबर, 2022 तक) के दौरान कुल ₹ 173.81 लाख का अनुदान जारी किया गया। वर्ष के दौरान 09 नए अनुसंधान अध्ययनों (तालिका 1.1) और 10 चालू अध्ययनों

के वित्त पोषण के प्रस्ताव पूरे किए गए (तालिका 1.2)। इसके अलावा, विषयों और क्षेत्रों के व्यापक दायरे में कार्यक्रमों के लिए 45 संस्थानों को प्रतीक चिह्न (लोगो) समर्थन (तालिका 1.3) प्रदान किया गया।

अध्ययन रिपोर्ट और संगोष्ठी की कार्यवाही हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रतियों में प्राप्त होती है। इन रिपोर्टों और कार्यवाहियों की प्रतियां, नीति के भीतर संबंधित वर्टिकल को परिचालित की जाती हैं, जो आगे इन रिपोर्टों की जांच करते हैं और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करते हैं।

[अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों, पूर्ण किए गए अध्ययनों और प्रदान किए गए प्रतीक चिह्न (लोगो) समर्थन की सूची अनुलग्नक में दी गई है]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास और प्रबंधन में शामिल प्रमुख हितधारकों को सलाह और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ सहकार्य करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नीतिगत दृष्टिकोणों पर दीर्घकालिक प्रभाव बनाने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रभाग प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग करता है।

भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आयुष-आधारित परिपाटियों का संग्रह

नीति आयोग ने जुलाई 2022 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आयुष-आधारित परिपाटियों का एक सार-संग्रह जारी किया, जिसमें कोविड-19 के प्रकोप को रोकने और प्रबंधित करने के लिए भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई विभिन्न आयुष-आधारित पहलों और परिपाटियों के बारे में जानकारी दी गई है। सार-संग्रह का लोकार्पण नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी और माननीय आयुष एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई कालूभाई ने किया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष और माननीय आयुष एवं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की उपस्थिति में आयुष आधारित पद्धतियों के सार-संग्रह का लोकार्पण

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग

नीति आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग के लिए दिशानिर्देशों के विकास में योगदान दिया, जिसे अप्रैल 2022 में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

श्री मनसुख एल. मांडविया द्वारा जारी किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि संवर्ग, नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों का सीमांकन करके सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य और अस्पताल सेवाओं दोनों के प्रबंधन को मजबूत करेगा।

फार्मा कंपनियों द्वारा विपणन परिपाटियां

फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा विपणन परिपाटियों में डॉक्टरों/चिकित्सकों के नुस्खापर्ची लिखने के पैटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है जिसे फार्मा उद्योग की ओर से अनुचित माना जा सकता है और ऐसा करना चिकित्सा पेशेवरों द्वारा अनैतिक आचरण/परिपाटी के समान हो सकता है। फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली अनैतिक परिपाटियों को रोकने के लिए फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए 1 जनवरी 2015 से फार्मास्युटिकल विपणन परिपाटियों के लिए एकसमान संहिता (यूसीपीएमपी) प्रचलित है। यूसीपीएमपी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और फार्मा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली विपणन परिपाटियों को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू तंत्र की आवश्यकता की जांच करने के लिए सितंबर 2022 में सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता में फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने इस विषय पर तीन बैठकें आयोजित की हैं।

औषध अनुसंधान और विकास की सुविधा के लिए अनुसंधान संसाधनों का पूल बनाना

भारत में औषधि नियामक प्रणाली में सुधार के लिए समिति की रिपोर्ट के आधार पर औषध अनुसंधान और विकास की सुविधा के लिए अनुसंधान संसाधनों का पूल बनाने के लिए एसओपी का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने औषध अनुसंधान एवं विकास के लिए अवसंरचना का लाभ उठाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया और विभिन्न एजेंसियों/विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी और हितधारक परामर्श के माध्यम से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की।

राष्ट्रीय आयुष अनुसंधान संघ (एनएआरसी)

आयुष के अंतर्गत, भारत में प्रचलित चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियाँ शामिल हैं। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को अपनाने में वृद्धि आई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, इस वृद्धि का लाभ उठाने के लिए वैश्विक स्तर पर औषधियों के रूप में आयुष उत्पादों के लिए बाजार प्राधिकरण प्राप्त करने के संदर्भ में आयुष औषधियों के फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, सुरक्षा आदि संबंधी डाटा आवश्यक है।

नीति आयोग ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय आयुष अनुसंधान संघ (एनएआरसी) के गठन की परिकल्पना की है और एक संस्थागत तरीके से हितधारक मंत्रालयों और उनके विभागों/संस्थानों के बीच वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से आयुष अनुसंधान को प्राथमिकता देने और आयुष देखभाल के वैश्विक उत्थान को बाधित करने वाली मूलभूत समस्या का समाधान करने के लिए एक संकल्पना नोट तैयार किया है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को बढाना और सुधार करना

आबादी के वृद्ध होते जाने की तेज गति के साथ, आयु बढ़ने और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के बारे में हमारी सोच को फिर से बदलने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि देश में बुजुर्गों की आबादी (60 वर्ष और उससे अधिक) वर्ष 2025 तक बढ़कर 158 मिलियन हो जाएगी, और आगे वर्ष 2050 तक 319 मिलियन (कुल जनसंख्या का 19.5%) बढ़ने का अनुमान है।

सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रयासों के बावजूद, वरिष्ठ नागरिक देखभाल के लिए प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण में सहायक का समर्थन करने के

बुनियादी ढांचे और क्षमताओं की कमी शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पहलों के तहत कई कार्यनीतिया हैं जिन्हें सरकार और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। सशक्तिकरण, सेवा वितरण और समावेशन के संदर्भ में चार क्षेत्रों: स्वास्थ्य और चिकित्सा, सामाजिक और कानूनी, आर्थिक/वित्तीय, और डिजिटल में विशिष्ट अंत:क्षेप आवश्यक हैं। नीति आयोग ने भारत में वरिष्ठ नागिरकों की देखभाल को बढ़ा के और सुधार करने पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की है।

टॉकिंग मेंटल हेल्थ: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी

नीति आयोग ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022 के उपलक्ष्य में एक आंतरिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा पर केंद्रित सत्र मुख्य रूप से नीति आयोग के कर्मचारियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता और संवेदीकरण के विषय पर लक्षित था। सत्र की अध्यक्षता सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने की, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य तथा लोगों के समग्र आरोग्य और कामकाज पर इसके व्यापक प्रभाव को समझने और इसके बारे में बात करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके बाद दो प्रसिद्ध मनोचिकित्सकों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया, और नीति आयोग के अधिकारियों ने भी मानसिक रोग के साथ अपने जीवन अनुभव और स्वास्थ्य-लाभ के अपने दृष्टिकोण साझा किए।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नीति आयोग के कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य पर कार्यशाला

उद्योग-I

उद्योग-I वर्टिकल नई नीतियां विकसित करके व्यापार और उद्योग के निरंतर विकास पर फोकस करता है। यह वर्टिकल, इष्टतम खनिज दोहन को प्रोत्साहित करते हुए, विभिन्न खनिजों के आयात को कम करते हुए, और मूल्यवर्धन के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हुए भारत में औद्योगिक और खनिज क्षेत्र के समग्र विकास की परिकल्पना करता है। यह वर्टिकल भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए उपलब्धि हासिल करने में राज्यों और प्रासंगिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण और कार्यान्वियन के मूल में नवाचार, प्रौद्योगिकी और कुशल प्रबंधन को एक साथ लाना है।

'ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई का एकीकरण' पर अध्ययन

एक डिजिटल अवसंरचना प्लेटफॉर्म, जो छोटे विक्रेताओं और व्यापारियों को मौजूदा राष्ट्रव्यापी बाजार स्थानों से जोड़ेगा, का निर्माण कर सार्वभौमिक ई-कॉमर्स पहुंच हासिल की जा सकती है। उद्योग-I वर्टिकल ने

विभिन्न ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पर भारतीय एमएसएमई के ऑन-बोर्डिंग की सुविधा के लिए 'ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई का एकीकरण' पर एक अध्ययन किया था। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पूरे भारत में एमएसएमई के एकीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए अध्ययन में भारत में मौजूद पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शामिल है। इस अध्ययन की रिपोर्ट जुलाई 2022 माह में सभी संबंधित हितधारकों के साथ साझा की गई थी।

उद्योग-II

उद्योग II वर्टिकल स्टील, कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पादों और वृक्षारोपण फसलों, पूंजीगत माल और इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, सर्कुलर इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है।

नीली अर्थव्यवस्था

नीति आयोग ने अप्रैल 2021 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नीली अर्थव्यवस्था समन्वय समिति का गठन किया। छह उप-समूहों की स्थापना की गई थी, और इन समूहों में पहलों का समन्वय उनके संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, नीति आयोग ने बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह (एमएसजी) नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा बुलाई गई बैठकों और राष्ट्रीय लेखा ढांचे पर उप-समूह की बैठकों में भाग लिया।

नीली अर्थव्यवस्था और महासागर अभिशासन पर भारत-फ्रांस रोडमैप

फरवरी 2022 में विदेश मंत्री (ईएएम) की फ्रांस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था और महासागर अभिशासन पर भारत-फ्रांस रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया था। इस रोडमैप में, नीति आयोग को नीली अर्थव्यवस्था और महासागर अभिशासन पर एक वार्षिक द्विपक्षीय संवाद आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है।

भारत-फ्रांस रोडमैप के तहत वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक प्रारंभिक बैठक 13 जून 2022 को फ्रांस के पेरिस के विदेश मंत्रालय में ध्रुव और समुद्री कार्य राजदूत के साथ आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में नीति आयोग के विशेष सचिव के नेतृत्व में सचिव, विदेश मंत्रालय और पांच अधिकारी शामिल थे। इस संवाद ने भारत को नीली अर्थव्यवस्था और महासागर अभिशासन के क्षेत्र में फ्रांस के सक्रिय मंत्रालयों और एजेंसियों की बेहतर समझ हासिल करने का अवसर प्रदान किया।

अवसंरचना-कनेक्टिविटी

अवसंरचना-कनेक्टिविटी वर्टिकल, एक ऐसी परिवहन प्रणाली बनाने का प्रयास करता है जो सामान्य, कनेक्टेड, सुविधाजनक, संकुलन मुक्त, स्वच्छ और अत्याधुनिक हो। यह वर्टिकल नीतिगत इनपुट प्रदान करता है और संबंधित मंत्रालयों को चर्चा और नीति पत्रों के रूप में हस्तक्षेप का सुझाव देता है। यह विधायी विधेयकों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट भी प्रदान करता है।

लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार–लॉजिस्टिक पार्क नेटवर्क

यह अध्ययन लॉजिस्टिक्स प्रभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में), नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड और अन्य प्रासंगिक संबंधित मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ चर्चा के साथ किया गया था। भारत में 192 आईसीडी और सीएफएस का स्थानिक विश्लेषण किया गया और 38 जर्मन फ्रेट विलेज और टीईएन-टी के साथ इनकी तुलना की गई। इससे मिले ज्ञान/अनुभव को प्रासंगिक मंत्रालयों द्वारा उनकी योजनाओं में शामिल किया जा रहा है, और गति-शक्ति प्लेटफॉर्म का मार्गदर्शन किया जा रहा है।

गति शक्ति

यह एक बहु-क्षेत्रीय जीआईएस-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है और लॉजिस्टिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली योजना साधन है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है, जिसकी तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस वर्टिकल को विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स के नेतृत्व में नेटवर्क आयोजना समूह के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है।

भूमि मान संकलन और साझाकरण तंत्र को तेजी से अपनाना

यह ओईसीडी और लिंकन इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रह के लिए संयुक्त रूप से प्रलेखित (नीति, जीआईजेड और एएससीआई) भारतीय परिदृश्य है, जिसके बाद दिसंबर 2021 (नीति, जीआईजेड और एएससीआई) में एक अनुभव-साझाकरण कार्यशाला (नौ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और 16 राज्यों की भागीदारी) का आयोजन किया गया। वर्तमान में एएससीआई (एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया) के माध्यम से राज्य की तैयारी का अध्ययन किया जा रहा है।

भवन सूचना मॉडलिंग को तेजी से अपनाना

निर्माण क्षेत्र में डिजिटलीकरण और सूचना साझा करने को तेजी से अपनाने के लिए विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय, यूनाइटेड किंगडम सरकार (एफसीडीओ) के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम अवसंरचना निर्माण क्षेत्र के लिए व्यापक हितधारकों की बातचीत पर लक्षित है और अवसंरचना परियोजना अवधि-चक्र में समय और लागत बचत के संदर्भ में इसकी बड़ी संभावना है। अब तक तीन कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं और एक मसौदा रोड मैप तैयार किया गया है।

सुदृढ़ अवसंरचना (अवसंरचना को जोखिम-मुक्त बनाना)

सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्विस री इंस्टीट्यूट के साथ एक शोध अध्ययन किया गया है। ये लचीला पहलू, अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा प्रतिरोध पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें जोखिम रजिस्टर विकसित करने और अवसंरचना बीमा करने के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। मसौदा रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही जारी की जाएगी।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी)

यह वर्टिकल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। 1504 किमी के साथ पश्चिमी कॉरिडोर (जेएनपीटी से दादरी) और 1856 किमी के साथ पूर्वी कॉरिडोर (दनकुनी से लुधियाना) कार्यान्वयन के अधीन हैं। परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डीएफसीसीआईएल बोर्ड में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व है।

अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधाओं पर अध्ययन

संबंधित हितधारकों की अध्यक्षता में 'भारत में एमआरओ: प्रवृत्तियां, चुनौतियां और आगे का रास्ता' पर ब्रीफ (बीआरआईईएफ) द्वारा एक अध्ययन आयोजित किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हवाई अड्डों का अवसंरचना विकास

अवसंरचना-कनेक्टिविटी वर्टिकल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा किए गए अवसंरचना विकास की निगरानी करता है और तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। तदनुसार, हवाई अड्डों में अवसंरचना विकास की तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई और प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई।

शहरीकरण प्रबंधन

शहरीकरण प्रबंधन (एमयू) प्रभाग, भारत के शहरीकरण को प्रबंधनीय, आर्थिक रूप से उत्पादक, पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त और न्यायसंगत बनाने के लिए डाटा-आधारित नीति इनपुट प्रदान करता है। यह शहरी नियोजन, विकास और प्रबंधन में शामिल प्रमुख हितधारकों को सलाह और नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्रभाग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय सरकारों के साथ नीतियां, कार्यक्रम, पहल और सुधार तैयार करने में कार्यरत है। यह शहरीकरण के प्रबंधन के लिए नीतिगत दृष्टिकोणों पर दीर्घकालिक प्रभाव बनाने की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ भी सहयोग करता है।

शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों के अभिशासन का सुदृढ़ीकरण

भारत में शहरीकरण एक अभूतपूर्व स्तर पर हो रहा है क्योंकि शहर–विकास, नवाचार और रचनात्मकता के केंद्र बन रहे हैं। इस तीव्र शहरीकरण का समर्थन करने और शहरों में अनुमानित आर्थिक विकास का लाभ उठाने के लिए, नागरिकों के स्वास्थ्य और आरोग्य को सुनिश्चित करना और सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना आवश्यक है। एक बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए प्रणालीगत स्तर पर शहरी स्वास्थ्य के मौजूदा परिदृश्य को समझने के लिए इस वर्टिकल द्वारा एक शोध परियोजना शुरू की गई है। प्रस्तावित कार्य के व्यापक अध्ययन के लिए आठ शहरों का चयन किया गया है।

विकास के इंजन के रूप में शहर

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की तकनीकी सहायता से नीति आयोग एक शोध परियोजना चला रहा है जो शहरी अर्थशास्त्र में इसकी नींव के साथ शहर नियोजन के लिए एक नए दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कई परामर्श आयोजित किए गए हैं जिनमें नीति आयोग और एडीबी की टीमों ने कई राज्यों के 130 से अधिक हितधारकों के साथ बातचीत की। इसके आधार पर प्रमुख बाधाओं की पहचान की गई है और आर्थिक विकास के इंजन बनने के लिए शहरों की क्षमता को अनलॉक करने के लिए सिफारिशें तैयार की जा रही हैं।

शहरी स्थानीय निकायों में नकद-आधारित से उपार्जन-आधारित लेखा प्रणाली में परिवर्तन

सीमित मानव संसाधन और तकनीकी क्षमताओं के साथ, कई शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक स्तर की सेवाओं को बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट (एमओएचयूए, 2020) में राजस्व और व्यय प्रबंधन, राजकोषीय विकेंद्रीकरण और राजकोषीय जिम्मेदारी के मामले में शहरी स्थानीय निकायों के खराब प्रदर्शन को उजागर किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक स्तर की शर्त के रूप में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के प्रकाशन की सिफारिश की है, इस महत्वपूर्ण सुधार के लिए तात्कालिकता की भावना का परिचय दिया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और एआरएफ (लेखा अनुसंधान प्रतिष्ठान) के साथ एक हस्तपुस्तिका तैयार की गई है, जो नकद आधारित लेखा प्रणालियों से उपार्जन-आधारित लेखा प्रणालियों में परिवर्तन में सीखे गए सर्वोत्तम अभ्यासों और अनुभवों पर आधारित है। अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही जारी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य में आकांक्षी शहर कार्यक्रम (एसीपी)

इस वर्टिकल ने उत्तर प्रदेश में 100 आकांक्षी शहरों की पहचान और निगरानी के लिए संकेतकों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा विकसित की है। कई विचार-विमर्श के बाद, शहरों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 16

संकेतकों के एक सेट और आकांक्षी शहरों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए 32 संकेतकों को अंतिम रूप दिया गया है। संकेतकों को अंतिम रूप देने के लिए इन 32 संकेतकों पर 17 शहरों के लिए एक पायलट भी आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को शुरू करने और 762 शहरी स्थानीय निकायों से आधारभूत डाटा संग्रह शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई वर्टिकल, भारत में एमएसएमई क्षेत्र की नीतियों और कार्यक्रमों के मामलों से संबंधित है। वर्टिकल के मुख्य उद्देश्यों में से एक एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों को विकसित करने और आगे बढ़ाने में सहायता करना है।

इस वर्टिकल ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 'सामान्य अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान देने के साथ उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए एमएसएमई क्लस्टर' पर एक शोध अध्ययन शुरू किया। अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसके अलावा, वर्टिकल ने 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के प्रभाव का आकलन' पर एक शोध अध्ययन भी शुरू किया, जो अभी चल रहा है।

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण

नीति आयोग का प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण (एनआरई) वर्टिकल व्यापक तौर पर तीन प्रमुख खंडों– वन, जैव विविधता और वन्य जीवन, और भारतीय हिमालयी क्षेत्र और द्वीप विकास से संबंधित है। वर्टिकल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ गतिविधियों का समन्वय करता है।

प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकियां: मई 2022 में प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों और प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के आह्वान को ध्यान में रखते हुए, नीति आयोग द्वारा प्लास्टिक विकल्प या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल बनाने वाली प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान के विकास और विश्व स्तर पर अपनाए जा रहे नियामक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यह रिपोर्ट बाजार तत्परता, अवसंरचना आवश्यकताओं और इन उत्पादों को अपनाने के लिए आवश्यक विनियामक ढांचे पर समिति के अध्ययन का एक परिणाम है।

बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के अंतरिम अनुमोदन/अनंतिम प्रमाणीकरण के प्रावधान: यह देखते हुए कि पूर्ण विघटन एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके सारस्वत की अध्यक्षता में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के अनंतिम प्रमाणीकरण के लिए संभावित अंतरिम मानकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में हाल ही में किए गए संशोधन के आलोक में, निम्नीकरण के प्रतिशत के संबंध में मानक निर्धारित करने के लिए विनिर्माण/विकासशील कंपनियों से डाटा एकत्र करने पर भी विचार किया गया था।

प्राकृतिक जलवायु समाधान (एनसीएस) कार्यनीति तैयार करना: यह वर्टिकल, प्रकृति संरक्षण के सहयोग से, एक प्रचालनात्मक एनसीएस कार्यनीति विकसित करने के लिए संभावित मार्गों और उप-मार्गों की पहचान करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, पांच जैव-भौगोलिक क्षेत्रों नामतः हिमालयी क्षेत्र, गंगा के मैदान, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र में निम्नीकृत भूमि को समतल करने, वनों की कटाई, कृषि वानिकी, और वनों की कटाई से बचने जैसे एनसीएस मार्गों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे।

कार्बन कैप्चर और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने में इसका उपयोग: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सहयोग से, यह वर्टिकल सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के साथ कार्बन कैप्चर को एकीकृत करने

के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। यह नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रोलाइज़र के निर्माण को बढ़ाकर निवेश लागत को कम करते हुए वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लगभग 10 एमएमटीपीए का पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा।

जलवायु वित्त: यह वर्टिकल वित्तीय साधनों के उपयोग के माध्यम से ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड, भारत के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण आदि को बढ़ाने के तरीकों की खोज कर रहा है। यह ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2022 के अनुसार नवीकरणीयों का श्रेष्ठ प्रदर्शन, हरित हाइड्रोजन, जैव-ईंधन/ई-ईंधन, स्वच्छ गतिशीलता, ऊर्जा भंडारण और हरित धातु आदि जैसे क्षेत्रों में कार्बन बाजार विकसित करने के लिए एक तंत्र तैयार करने पर भी विचार कर रहा है। .

कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए शमन और अनुकूलन मार्ग विकसित करना: यह वर्टिकल सभी क्षेत्रों में कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए भारतीय परिस्थितियों के लिए शमन और अनुकूलन मार्गों पर एक संकल्पना नोट तैयार कर रहा है। नीतिगत अंत:क्षेप और अवसंरचना, विनिर्माण, परिवहन और विद्युत क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के विकल्प विकसित करने से कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ग्रीन जीडीपी की अवधारणा का भी पता लगाया जाएगा, जिसमें किसी देश के मानक जीडीपी के साथ-साथ जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार लागत जैसे पर्यावरणीय कारकों पर विचार किया जाता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था की सततता सुनिश्चित करने में मदद मिल सके।

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी)

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन, नीति आयोग के परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) द्वारा किया गया एक मुख्य कार्य है। तदनुसार इस प्रभाग को निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन सौंपा गया है:

i. तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना और प्रारूप विकसित करना;
ii. परियोजनाओं और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया में सुधार के लिए अनुसंधान अध्ययन करना;
iii. सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना; और
iv. परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित प्रक्रिया स्थापित करने में केंद्रीय मंत्रालयों की सहायता करना।

सार्वजनिक कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन

यह प्रभाग सार्वजनिक निवेश बोर्ड और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) से संबंधित 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं/योजनाओं का व्यापक मूल्यांकन करता है। 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाले रेल मंत्रालय के प्रस्तावों का मूल्यांकन विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा किया जाना है। प्रभाग द्वारा लागत और समय की वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों और व्यवहार्यता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है।

इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में, पीएएमडी ने अपने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के माध्यम से सार्वजनिक परियोजनाओं और योजनाओं की संरचना और तैयारी के लिए मूल्यांकन तंत्र और प्रक्रियाओं में आमूल-चूल बदलाव/परिवर्तन किया है। नीति आयोग, अपने मूल्यांकन ज्ञापन के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं की प्रभावकारिता एवं वितरण और परिणामों के संदर्भ में व्यय के उद्देश्य से प्रणालीगत सुधार लाने में सहायक रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 2572095 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों में निहित 135 योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। 01 अप्रैल 2022 से 10 जनवरी 2023 तक मूल्यांकित परियोजनाओं का कार्यक्षेत्र-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	2022-23 (1 अप्रैल, 2022 से 10 जनवरी, 2023 तक)		
		संख्या	लागत (करोड़ रुपए)	प्रतिशत
1	कृषि	18	212635.68	8.27
2	ऊर्जा	9	72396.08	2.81
3	परिवहन	36	1133791.22	44.08
4	उद्योग	16	511366.73	19.88
5	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2	8095.58	0.31
6	सामाजिक सेवाएं	17	409165.51	15.91
7	संचार	4	26203.25	1.02
8	अन्य	33	198441.21	7.72
	कुल	**135**	**2572095.26**	**100.00**

सार्वजनिक निजी भागीदारी

यह वर्टिकल अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिमान्य मोड के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह समयबद्ध विश्व स्तरीय अवसंरचना तैयार करने और अवसंरचना में निजी क्षेत्र और संस्थागत पूंजी को आकर्षित करने का आशय रखता है।

स्वास्थ्य सेवा देखभाल में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा शिक्षा में पीपीपी के लिए रियायत करार–मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किया था, और बाद में 'अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए वित्तीय सहायता' की योजना में संशोधन पर आर्थिक कार्य विभाग के साथ मिलकर काम किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय और राज्य पीपीपी परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के अनुदान को सक्षम बनाता है। पीपीपी परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से, कुल परियोजना लागत का 40% तक अनुदान भारत सरकार से किया जा सकता है।

इस संबंध में, नीति आयोग ने वीजीएफ योजना को आगे बढ़ाने के लिए अनेक चर्चाओं और राज्य संवादों का आयोजन किया। नीति आयोग ने परियोजनाओं की पहचान करने, संकल्पना प्रस्तावों को तैयार करने और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावों की जांच करने में भी राज्यों को सहयोग प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य क्षेत्र की कम से कम आठ पीपीपी परियोजनाएं वीजीएफ अनुदान के अग्रिम चरण में हैं। इस वर्ष, योजना के तहत परियोजना मूल्यांकन निकाय के हिस्से के रूप में, नीति आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में दो राज्य परियोजनाओं का मार्गदर्शन किया, जिन्हें बाद में योजना के तहत सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

खाद्यान्न भंडारण में पीपीपी

नीति आयोग (पीपीपी वर्टिकल) ने देश की गेहूं भंडारण अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश और दक्षता का लाभ उठाने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम विभाग के साथ मिलकर कार्य किया। 12 राज्यों में फैले इस पीपीपी कार्यक्रम में 108.375 एलएमटी की कुल भंडारण क्षमता के साथ 249 स्थानों पर साइलो के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित पूंजी लागत 9236 करोड़ रुपए है। डीबीएफओटी (प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि) और डीपीएफओओ (निजी भागीदार / निवेशक द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली भूमि) मॉडल का संयोजन, चरण । परियोजना (80 स्थानों) के लिए बोली प्रक्रिया, इस वर्ष शुरू की गई थी।

विवाद समाधान तंत्र – व्यापार की सुकरता

वित्त वर्ष 2021-2022 के बजट भाषण में सरकार या सीपीएसई के साथ कार्य करने वालों के लिए व्यापार की सुकरता को बढ़ावा देने और निजी निवेशकों एवं संविदाकारों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने एक करार तंत्र स्थापित करने की घोषणा की . जिसके अनुसरण में, मार्च 2021 में प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी के साथ नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

टास्क फोर्स को अन्य बातों के साथ-साथ सरकार (मंत्रालयों, सीपीएसई) और निजी निवेशकों/संविदाकारों/ रियायत प्राप्तकर्ताओं के बीच संविदाओं और कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों के समयोचित और लागत कुशल समाधान के लिए एक प्रभावी सुलह तंत्र विकसित करने का अधिदेश दिया गया था। टास्क फोर्स ने विस्तृत विचार-विमर्श किया। पीपीपी वर्टिकल, नीति आयोग, जो टास्क फोर्स को सेवा प्रदान कर रहा है, ने सभी सदस्यों के इनपुट और सुझावों के आधार पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में 'सरकार और निजी संस्थाओं के बीच विवादों के समाधान के लिए दिशानिर्देश' तैयार करने में सहायता की। टास्क फोर्स की रिपोर्ट/सिफारिशें पूरी की गईं। दिशा-निर्देशों के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।

पीपीपी मोड पर जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम का पुनर्निर्माण

वर्ष के दौरान, नीति आयोग ने संव्यवहार-पूर्व गतिविधियों में युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया और पीपीपी के माध्यम से दिल्ली में जेएलएन स्टेडियम के पुनर्विकास के लिए कार्यनीति को अंतिम रूप दिया ताकि इसकी प्रतिष्ठित खेल संपत्ति के इष्टतम उपयोग से मूल्य अनलॉक किया जा सके। परियोजना को पीपीपी के माध्यम से स्टेडियम के आसपास उपलब्ध मिश्रित-उपयोग/रियल-एस्टेट विकास क्षमता का लाभ उठाकर निष्पादित किया जाना है। नीति आयोग ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ पीपीपी मोड में परियोजना की व्यवहार्यता और प्रारंभिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए परियोजना का व्यवहार्यता-पूर्व विश्लेषण किया। नीति आयोग संव्यवहार के शुभारंभ की तैयारी और अपेक्षित आरम्भ-पूर्व गतिविधियों के संचालन के लिए मंत्रालय के साथ कार्य कर रहा है।

पीपीपी और परिसंपत्ति मुद्रीकरण की दिशा में राज्य समर्थन पहल

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रयासों को परिवर्धित करने और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए स्थायी तरीके से वित्तपोषण बढ़ाने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। सुसंरचित राज्य स्तरीय परिसंपत्तियों के लिए निवेशकों में काफी उत्सुकता है। हालांकि, निवेशक प्रस्तावों की पाइपलाइन की दृश्यता की इच्छा रखते हैं। इसलिए राज्य स्तरीय मुद्रीकरण पाइपलाइन बनाना महत्वपूर्ण है। इस दिशा में, विभिन्न राज्यों के साथ पीपीपी वर्टिकल सहकार्य कर रहा है और राज्य के संबंधित विभागों (परिवहन, विद्युत, शहरी, भंडारण, खेल, वित्त, बंदरगाह) के साथ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के मुद्रीकरण ढांचे पर चर्चा की गई और संभावित परिसंपत्तियों पर मंथन किया गया।

पीपीपी मोड के माध्यम से बीएसएनएल की टावर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

बीएसएनएल देश भर में लगभग 68,049 टावर परिसंपत्तियों का स्वामित्व और संचालन करता है, जिनमें से लगभग 13,567 टावर वर्तमान में सह-स्थित हैं। चूंकि दूरसंचार कंपनियां अपने 4जी नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं और 5जी के आगमन की योजना बना रही हैं, इसलिए बीएसएनएल टावर कई सेवा प्रदाताओं के लिए नेटवर्क और सेवा सघनता में सुधार के लिए उपयुक्त अवसंरचना का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। दूरसंचार परिसंपत्तियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत अभिचिह्नित संभावित परिसंपत्तियों के अनुसरण में, यह वर्टिकल दीर्घअवधि के ब्राउनफील्ड पीपीपी मॉडल के माध्यम से लगभग 10,000 दूरसंचार टावरों के मुद्रीकरण के लिए आवश्यक संव्यवहार-पूर्व कदम उठाने में बीएसएनएल के साथ कार्य कर रहा है। वर्ष के दौरान, व्यवहार्यता और संव्यवहार-पूर्व संरचना की गई और प्रस्ताव को दूरसंचार विभाग द्वारा पीपीपीएसी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

ग्रामीण विकास

नीति आयोग का ग्रामीण विकास वर्टिकल ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी करता है। यह वर्टिकल ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रारूप दस्तावेजों और रिपोर्टों का भी विश्लेषण करता है और अंतिम रूप देने के लिए उन पर नीति आयोग की टिप्पणियां प्रस्तुत करता है।

वित्त वर्ष 2022-23 में, ग्रामीण विकास वर्टिकल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी), महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी), स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-चरण III पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न बैठकों में भाग लिया।

यह वर्टिकल ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ उनके छठे आम समीक्षा मिशन (सीआरएम) से सहसंबद्ध था। सीआरएम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में अच्छी परिपाटियों का प्रलेखन करना था। मिशन के दौरान सभी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई।

उत्तर प्रदेश के लिए 5 वर्षों (2022-2027) में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की कार्यनीति के संबंध में, उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास क्षेत्र के संबंध में वर्तमान विकास दर को पर्याप्त रूप से बढ़ाने और पीपीपी के माध्यम के साथ-साथ निवेश दर में उल्लेखनीय वृद्धि, और इसे प्राप्त करने के तरीकों पर सुझाव दिए गए थे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

यह वर्टिकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी-विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करके केंद्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों के सहयोग से देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का आशय रखता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर परामर्श समूह

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर परामर्श समूह की चौथी बैठक 4 जुलाई 2022 को सदस्य (एसएंडटी), नीति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। समूह की तिमाही बैठक की जाती है और इसे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रबंधन की देखरेख करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में बाधा डालने वाले विभिन्न मुद्दों और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के तरीकों पर चर्चा करने के उद्देश्य से गठित किया गया है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक

नीति आयोग ने वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) और शीर्ष रैंकिंग वाले देशों- विशेष रूप से, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ बातचीत की,ताकि उनकी अच्छी परिपाटियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। शीर्ष रैंकिंग वाले देशों की अच्छी परिपाटियों के आधार पर, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में अपनी अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति के माध्यम से नीति आयोग, जीआईआई में भारत की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को कुछ विशिष्ट उपायों का सुझाव दे रहा है। समिति की चार बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें सबसे हालिया बैठक 28 फरवरी 2022 को हुई, जहां रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लिया गया और संबंधित मंत्रालय/विभागों को सौंप दिया गया। डाटा बिंदुओं, चिंताओं और सुझावों सहित समेकित इनपुट को डब्ल्यूआईपीओ और यूएनआईडीओ तथा यूनेस्को जैसी डाटा स्रोत एजेंसियों को सूचित किया जा रहा है।

29 सितंबर 2022 को, डब्ल्यूआईपीओ ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 जारी किया, जिसमें भारत ने छह स्थान की ऊर्ध्वाधर वृद्धि हासिल की और अब भारत विश्व स्तर पर 40वें स्थान पर है। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी रैंक में लगातार सुधार किया है जो वर्ष 2015 में 81 से सुधर कर वर्ष 2022 में 40 तक हो गई है।

नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने संयुक्त रूप से 30 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के भारत में प्रकाशन का आयोजन किया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक श्री डेरेन टैंग और नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने वक्ताओं के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वियन की निगरानी करना

भारतनेट परियोजना के कार्यान्वियन में प्रगति की एसएंडटी वर्टिकल द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। 2 जनवरी 2023 तक, भारतनेट परियोजना के पहले चरण के कार्यान्वियन की प्राप्ति 99.52 प्रतिशत है, जबकि दूसरे चरण के लिए यह आंकड़ा 43.58 प्रतिशत है।

स्वदेशी कृत्रिम हृदय के विकास और व्यावसायीकरण के लिए मिशन

स्वदेशी कृत्रिम हृदय के विकास और व्यावसायीकरण की डिजाइन और तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और पूर्व प्रमुख डॉ. राजीव नारंग की अध्यक्षता में एक मिशन समिति का गठन किया गया है। मिशन की पहली और दूसरी बैठक क्रमश: 30 सितंबर 2022 और 14 अक्टूबर 2022 को हुई थी। समिति ने आर्थिक मूल्य पर कृत्रिम हृदय के विकास को प्राथमिकता देने के महत्व पर ध्यान दिया क्योंकि भारत में मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन (दिल का दौरा) के मामले बढ़ रहे हैं।

समुद्री शैवाल की खेती

खाद्य स्रोत, औषधि, खाद्य पैकिंग, पशु चारा और उर्वरक के स्रोत सामग्री के रूप में इसके कई उपयोगों के कारण हाल के दिनों में समुद्री शैवाल को महत्व मिला है। एस एंड टी वर्टिकल भारत में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने और देश के खाड़ी क्षेत्रों में समुद्री शैवाल की खेती के बारे में लंबित मुद्दों और चिंताओं का समाधान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ सूक्ष्म निगरानी और कार्य कर रहा है।

पेरोवस्काइट सामग्री अनुसंधान और विकास

पेरोवस्काइट एक कम लागत वाली, उद्योग-स्केलेबल तकनीक है और हाल के वर्षों में उच्च रूपांतरण दक्षता के साथ इसमें उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। भारत में कई अनुसंधान समूह सक्रिय रूप से पेरोवस्काइट

कोशिकाओं के विकास में शामिल हैं। सरकारी मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स आदि की भागीदारी के साथ नीति आयोग में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके सारस्वत की अध्यक्षता में पेरोवस्काइट सामग्री और चल रहे अनुसंधान एवं विकास कार्य पर चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित की गईं।

भारत की परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छोटे पैमाने पर परमाणु रिएक्टर

विभिन्न क्षेत्रों से विद्युत की बढ़ती मांग के साथ, भारत सरकार देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अगले दशक में परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना बढ़ाने की योजना बना रही है। इस अभ्यास के लिए छोटे और मध्यम पैमाने के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने और उनके लाभों और चुनौतियों का और आकलन करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। छोटे पैमाने के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता की जांच के लिए 13 मई 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपनी रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार को सौंप दी है।

रोबोटिक्स और ऑनलाइन गेमिंग

रोबोटिक्स और ऑटोमेशन एक उद्योग के रूप में अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है, जो विनिर्माण और अन्य उद्योगों में क्रांति ला रहा है। 29 जून 2022 को, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत में रोबोटिक्स उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समिति के सदस्यों में से एक हैं। समिति ने 21 सितंबर 2022 को अपनी पहली बैठक आयोजित की।

कौशल विकास और रोजगार

कौशल विकास और रोजगार प्रभाग (i) भारतीय युवाओं और कार्यबल को रोजगारपरक बनाने के लिए नीतिगत पहलों में तेजी लाने के लिए ज्ञान का निर्माण और साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, (ii) रोजगार, नौकरियों और आजीविका सृजन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने के साथ-साथ समाधानों की पेशकश भी करता है। यह प्रभाग कौशल विकास, रोजगार सृजन और समाज कल्याण में शामिल प्रमुख हितधारकों को सलाह और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्रभाग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) के साथ मिलकर कौशल विकास, शिक्षुता और रोजगार के मुद्दों से संबंधित नीति/कार्यक्रम की पहल और सुधार तैयार करता है। यह प्रभाग विभिन्न अनुसंधान संगठनों, विकास भागीदारों और विशेषज्ञों के साथ नीति और कार्यक्रम पहलों पर प्रभाव डालने के लिए अनुसंधान उन्मुखता के लिए भी सहयोग करता है।

'भारत की बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था: कार्य के भविष्य पर दृष्टिकोण और सिफारिशें' पर रिपोर्ट का प्रकाशन

नीति आयोग ने 27 जून 2022 को अपनी तरह का पहला अध्ययन–'भारत की बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था: कार्य के भविष्य पर दृष्टिकोण और सिफारिशें' जारी किया। इस रिपोर्ट में भारत में गिग-प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण, कार्यबल अनुमान और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। रिपोर्ट में क्षेत्र के वर्तमान आकार और रोजगार-सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति प्रदान की गई है।

'भारत की बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था: कार्य के भविष्य पर दृष्टिकोण और सिफारिशें' पर रिपोर्ट का प्रकाशन

रिपोर्ट के जारी होने के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, वर्ष के दौरान कई गोलमेज चर्चाओं का आयोजन किया गया। ये चर्चाएं सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास, सामाजिक समावेशन और डाटा अधिकारों पर विषयगत सत्रों के साथ काम के समावेशी भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित थी। विभिन्न शहरों में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और कार्य के भविष्य पर क्षेत्रीय आउटरीच और प्रसार कार्यशालाओं और नीति संबंधी गोलमेज चर्चाओं की योजना बनाई गई है।

महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में बाधाओं को समझने पर अध्ययन

नीति आयोग का एसडीई वर्टिकल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ पांच नमूना राज्यों नामतः दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी पर एक अध्ययन के लिए सहयोग कर रहा है। अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं के काम को मापने के लिए नवीन सर्वेक्षण साधनों के साथ प्रयोग करते हुए भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी के पीछे मांग और आपूर्ति पक्ष के कारकों को अनपैक करना है।

देखभाल क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर नीति का सार

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, देखभाल अर्थव्यवस्था में वर्ष 2030 तक दुनिया भर में 475 मिलियन रोजगार सृजित करने की क्षमता है, जिसमें 269 मिलियन नए रोजगार शामिल हैं। एसडीई वर्टिकल ने देखभाल क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर कागजातों का सार-संग्रह और नीति का सार विकसित करने के लिए आईएलओ के साथ सहयोग किया है। सार-संग्रह और नीति का सार, देखभाल क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की संभावना को उजागर करेगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य देखभाल सेवाएं शामिल हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के कायाकल्प पर रिपोर्ट

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की नींव हैं। देश में आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए परिवर्तनकारी विचार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, एसडीई वर्टिकल द्वारा एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में पांच राज्यों में 27 आईटीआई के फील्ड दौरे शामिल थे, और इसमें उच्च-श्रेणी और निम्न-श्रेणी के आईटीआई का मिश्रण शामिल था। शोध प्रक्रिया में प्रशिक्षुओं, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रशासनिक कर्मचारियों और डीजीटी अधिकारियों सहित कई हितधारकों के साथ बातचीत और परामर्श शामिल है। अध्ययन रिपोर्ट में आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के लिए भविष्योन्मुखी सिफारिशें प्रस्तुत की गई।

अंतिम आकांक्षी जिला रैंकिंग संकेतक (एडीआर)

नीति आयोग का कौशल विकास और रोजगार वर्टिकल 112 आकांक्षी जिलों के लिए अंतिम आकांक्षी जिला रैंकिंग संकेतक (एडीआर) तैयार करने के लिए कुछ योजनाओं पर कौशलवर्धन डाटा के समन्वय के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकार कार्य कर रहा है। कार्य में अंतिम आकांक्षी जिला रैंकिंग संकेतक (एडीआर) प्रस्तुत करने के लिए कौशल विकास पर आकांक्षी जिलों के रैंकिंग डाटा से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन, सारणीकरण और विश्लेषण शामिल है। इसके बाद डाटा को मासिक आधार पर नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) टीम के साथ साझा किया जाता है।

वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 में भागीदारी

एसडीई वर्टिकल ने 27 और 28 सितंबर, 2022 को फिक्की फेडरेशन हाउस में आयोजित वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लिया। शिखर सम्मेलन का विषय 'एजुकेशन टू एंप्लॉयबिलिटी-मेकिंग इट हैपन' था। सलाहकार एसडीई ने 27 सितंबर को शिखर सम्मेलन में 'द फ्यूचर ऑफ स्किलिंग: न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क' विषय पर विशेष संबोधन दिया।

भारत में उद्यमिता परिदृश्य के कायाकल्प पर विचार-विमर्श

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए पहलों का पता लगाने के उद्देश्य से, विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ विचार-मंथन सत्रों का आयोजन किया गया। यह विचार-विमर्श, मौजूदा उद्यमिता योजनाओं की पहुंच को अधिकतम करने, क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने, बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञ नेटवर्क के साथ उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाने के संभावित तरीकों पर केंद्रित था ताकि उद्यमियों को राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन के माध्यम से व्यवसायों को आरम्भ करने और प्रवर्धित करने में मदद मिल सके। यह विचार-विमर्श, मौजूदा प्रयासों के अभिसरण और केंद्र, राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों के बीच मजबूत सहयोग, जो भारत में उद्यमिता परिदृश्य को फिर से जीवंत करने में मदद कर सकता है, की संभावनाओं पर केंद्रित था।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

इस प्रभाग का विजन हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देने के मूल आधार पर आधारित है, जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित न होने का जोखिम रहता है। यह प्रभाग समाज के कमजोर वर्गों के समावेशी विकास में शामिल विभिन्न हितधारकों-केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ शासित प्रदेशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों-के साथ समय-समय पर समीक्षा करता है। यह एसडीजी प्राप्त करने में हुई प्रगति की निगरानी भी करता है, विकास की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और उचित सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव करता है। यह प्रभाग समावेशी सशक्तिकरण और समाज के वंचित वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति (एससी), सफाई कर्मचारी (एसके), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), धार्मिक अल्पसंख्यक, खानाबदोश, अर्ध-खानाबदोश और गैर-अधिसूचित जनजाति (एनटी, एसएनटी और डीएनटी), और सामाजिक रक्षा समूह जैसे दिव्यांगजन (पीडबल्यूडी), वरिष्ठ नागरिक / वृद्धजन, ट्रांसजेंडर, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार / नशीली दवाओं के व्यसनी, निराश्रित और भिखारी, आदि के मानव पूंजी विकास के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

एनटी, डीएनटी और एसएनटी की पहचान संबंधी समिति

सरकार ने गैर-अधिसूचित जनजातियों (डीएनटी), खानाबदोश जनजातियों (एनटी), अर्ध-खानाबदोश जनजातियों (एसएनटी) और अभी तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं की गई जनजातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति ने भारतीय

मानव विज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआई), कोलकाता के माध्यम से एक नृवंशविज्ञान अध्ययन शुरू किया है। एएनएसआई ने 268 समुदायों में से लगभग 250 का अध्ययन पूरा कर लिया है, और गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों/समुदायों के संबंध तैंतीस समुदायों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, शेष समुदायों के संबंध में अध्ययन पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद अंतिम समेकित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव

नीति आयोग ने 8 जुलाई 2021 को उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 के प्रभाव पर एक अध्ययन शुरू किया। तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से मानव विकास संस्थान को कार्य सौंपा गया। जमीनी स्तर का कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

एससीएसपी और टीएसपी के तहत निधियों के आबंटन की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निधियों के आबंटन और उपयोग के संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ बातचीत की है और इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्टिकल ने एससीएसपी और टीएसपी दिशानिर्देश 2017 की बड़े पैमाने पर समीक्षा की है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निधियों के आबंटन की एक नई व्यवस्था तैयार की जा सके, जिसे 41 दायित्वपूरक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाया गया है जो पर्यावास विकास/लाभार्थी-उन्मुख योजनाएं संचालित करते हैं।

एससीएसपी और टीएसपी की निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना

नीति आयोग, नोडल मंत्रालयों के साथ मिलकर वास्तविक समय के आधार पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक निगरानी ढांचा विकसित करने में लगा हुआ है।–एससीएसपी और टीएसपी के लिए क्रमशः दो पोर्टल–https://e-utthaan.gov.in/ (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) और https://stcmis.gov.in/ (जनजातीय मामलों के मंत्रालय) विकसित किए गए हैं।

जनजातीय विकास पर विशेषज्ञों की बैठक

अठारह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में फैले लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं, जिनकी आबादी घट रही है या स्थिर है, जिनकी साक्षरता का निम्न स्तर है, जिनकी प्रौद्योगिकी का स्तर पूर्व-कृषि पर है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। जनजातीय विकास में चल रही पहलों और बाधाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 28 अक्टूबर 2022 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ लगभग दस क्षेत्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। विशेषज्ञों ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए विशेष उप-योजना, जनजातीय उप-योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए) के सुदृढ़ीकरण, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के सुदृढ़ीकरण आदि जैसे कई उपायों और सुधारों का सुझाव दिया है।

राज्य वित्त एवं समन्वय

राज्य वित्त और समन्वय वर्टिकल राज्यों के साथ समन्वय को मजबूत करने का प्रयास करता है और राज्यों के वित्त और बहु-राज्य मुद्दों से संबंधित सभी मामलों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

राज्यों की वित्तीय समृद्धि के विश्लेषण सहित राज्य वित्त का सार

राज्यों के बजट 2021-22 में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हुए, वर्टिकल ने राज्यों के संबंध में जीएसडीपी वृद्धि, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, स्वयं के करों से उत्पन्न संसाधनों सहित प्राप्तियों, पूंजीगत व्यय सहित व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, राजकोषीय और राजस्व घाटा और इसकी ऋण स्थिति का विश्लेषण किया।

राज्यों के प्रमुख वृहद आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों) का राज्य-बनाम-राज्य विश्लेषण भी किया गया था जिसका उपयोग भावी विकास के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वार्तालाप/बैठकों में किया जा रहा है।

राज्यों को आबंटन

केंद्र सरकार राज्यों को उनकी क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं और परियोजनाओं, जिनके लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद बजट प्रावधान नहीं किया गया है, की 'अधिप्लावित (स्पिलओवर) देनदारियों' को पूरा करने के लिए सहायता करने का प्रयास करती है और सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रयास करती है। राज्य वित्त और समन्वय वर्टिकल, नीति आयोग से व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को 'राज्यों को अंतरण' की मांग के तहत राज्यों को 'विशेष सहायता' के संबंध में की गई सभी सिफारिशों के लिए नोडल के रूप में कार्य करता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त वर्ष 2021 में विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए एकबारगी समर्थन के रूप में 1996 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई थी।

राज्य तथ्यपत्रक

स्वास्थ्य, श्रम और रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग, बीमा, विकास और अर्थव्यवस्था, शहरीकरण, जल और स्वच्छता, महिला और बाल विकास सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में 'एक नज़र' में जानकारी प्रदान करने और भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में राज्यों के प्रदर्शन/उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए, इस वर्टिकल द्वारा एक टेम्प्लेट तैयार किया गया है और नीति आयोग में सभी राज्य वर्टिकल में परिचालित किया गया है। वर्टिकल ने राज्य वर्टिकल को उनके संबंधित राज्यों के लिए राज्य तथ्य पत्रक के विकास में अपेक्षित समर्थन प्रदान किया। इन तथ्यपत्रक का उपयोग नीति आयोग के संबंधित राज्य-वर्टिकल द्वारा राज्यों को साक्ष्य आधारित इनपुट प्रदान करने और राष्ट्रीय प्रदर्शन की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करके नीति निर्माण के लिए किया जा रहा है।

डाटाबेस कोष

यह वर्टिकल प्रमुख वृहत्, सामाजिक और वित्तीय संकेतकों पर एक राज्य-वार डाटाबेस रखता है, जिसका उपयोग नीति आयोग द्वारा विभिन्न नीतिगत मामलों पर राज्यों को महत्वपूर्ण नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय अंतरण की जानकारी मासिक आधार पर अद्यतन की जाती है और नीति आयोग के ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) पर अपलोड की जाती है।

नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई

यह वर्टिकल, नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई कार्रवाई के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और नीति आयोग के भीतर वर्टिकल के साथ समन्वय करता है। नीति आयोग की शासी परिषद की सातवीं बैठक माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 अगस्त 2022 को आयोजित की गई थी। नीति आयोग की शासी परिषद की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया गया और कार्यवृत्त को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए शासी परिषद के सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों को को परिचालित किया गया। नीति आयोग द्वारा इस पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय

यह वर्टिकल पिछले सात वर्षों में नीति आयोग से संबंधित चल रही केंद्रीय बजट घोषणाओं की स्थिति पर आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करता है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर बजट घोषणाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क (यूएनएसडीसीएफ) 2023-27

भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (जीओआई-यूएनएसडीएफ) 2018-2022, भारत की प्रमुख राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और सतत विकास विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि के समर्थन में भारत सरकार और भारत में संयुक्त राष्ट्र की कंट्री टीम के बीच विकास सहयोग कार्यनीति की रूपरेखा तैयार करता है। कार्यान्वियन के अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश करने के बाद, भारत सरकार और भारत में संयुक्त राष्ट्र की कंट्री टीम अगले पांच वर्ष की अवधि 2023-27 के लिए भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचे (यूएनएसडीसीएफ) को नवीनीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए सहयोग फ्रेमवर्क का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख आउटकम और आउटपुट, सरकार, सीएसओ, विचार-मंच और आर्थिक उद्यमों के साथ परामर्श के साथ एक उच्च परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए गए हैं। यह वर्टिकल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क (यूएनएसडीसीएफ) 2023-27 से संबंधित कार्य के समन्वय के लिए नोडल वर्टिकल के रूप में कार्य करता है।

यूएनएसडीएफ 2018-2022 का मूल्यांकन

वर्तमान में क्रियाशील यूएनएसडीएफ (2018-2022) से प्रमुख निष्कर्षों का आकलन करने के लिए प्रो. ए.के. शिव कुमार के नेतृत्व में एक स्वतंत्र मूल्यांकन टीम का गठन किया गया था और इससे प्राप्त अनुभवों को नए सहयोग फ्रेमवर्क (2023 -27) के निर्माण में शामिल किया जाएगा। मूल्यांकन अध्ययन में नीति आयोग, भारत सरकार के अधिकारीगण, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुखगण, सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण सूचनात्मक साक्षात्कारों सहित विभिन्न हितधारकों से डाटा संग्रह की एक व्यापक प्रक्रिया को अपनाया गया है, परिणाम समूहों एवं चयनित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ समूह चर्चाओं (एफजीडी) पर फोकस किया गया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।

कार्यकारी समूहों की स्थापना

सहयोग फ्रेमवर्क के प्रस्तावित छह परिणामों अर्थात, (क) स्वास्थ्य और कल्याण, (ख) पोषण और खाद्य; (ग) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा; (घ) आर्थिक विकास और सभ्य कार्य; (ङ) पर्यावरण, जलवायु, डबल्यूएएसएच और लचीलापन; और (च) लोगों, समुदायों और संस्थानों का सशक्तिकरण के आधार पर सामरिक प्राथमिकता परामर्श के लिए कार्यकारी समूहों का गठन किया गया था। नीति आयोग के संबंधित सदस्यों द्वारा संचालित ये परिणाम-वार कार्यकारी समूह, प्रासंगिक आउटकम मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अन्य संबंधित मंत्रालयों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और नीति आयोग के प्रतिनिधित्व के साथ स्थापित किए गए थे।

राष्ट्रीय वैधीकरण कार्यशाला:

इसे बाद में डॉ. राजीव कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग और श्री शोम्बी शार्प, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की सह-अध्यक्षता में 12 अप्रैल 2022 को रीजेंसी बॉलरूम, हयात रीजेंसी, नई दिल्ली में आयोजित भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क (यूएनएसडीसीएफ) 2023-27 पर राष्ट्रीय वैधीकरण कार्यशाला में विधिमान्य किया गया था। इस उच्च-स्तरीय हाइब्रिड संगोष्ठी में 30 केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों, 26 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुखों, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 250 से अधिक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया।

अगले चरण में, संयुक्त राष्ट्र कंट्री टीम द्वारा एक विस्तृत परिणाम फ्रेमवर्क तैयार किया गया और इसे नीति आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया। परिणाम फ्रेमवर्क में छह परिणामों में से प्रत्येक के लिए परिणाम संकेतकों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया, जो नए सहयोग फ्रेमवर्क की निरंतर निगरानी का आधार बनेंगे।

नया सहयोग फ्रेमवर्क: भारत की आजादी के 75वें वर्ष की समयावधि के दौरान हस्ताक्षर किया जाने वाला नया सहयोग फ्रेमवर्क 2023-27, सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के एजेंडा (2030 एजेंडा) के कार्यान्वयन के समर्थन में देश स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र के सामूहिक समर्थन के पूरे कार्यक्रम चक्र, संचालन योजना, कार्यान्वयन, निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन का मार्गदर्शन करता है। 7 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023-27 के अब तक के विकास और आगे के कदम पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आमंत्रित की गई थी। श्री शोम्बी शार्प, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर द्वारा यूएनएसडीसीएफ 2023-27 के आउटकम फ्रेमवर्क और विकास की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद यूएनएसडीसीएफ के अंतर्गत छह परिणामों पर चर्चा की गई।

सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम परिपाटियां

सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अधिदेश के हिस्से के रूप में और भारत की आजादी के 75 साल के महोत्सव के रूप में, नीति आयोग और यूएनडीपी ने सामाजिक क्षेत्र में 75 सर्वोत्तम परिपाटियों को एक सार-संग्रह के रूप में संकलित किया है। इन सर्वोत्तम परिपाटियों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है। इसका उद्देश्य उन मॉडलों को उजागर करना है जो अभिनव, सतत, अनुकरणीय और प्रभावशाली हैं तथा जमीनी स्तर पर जीवन की गुणवत्ता का विस्तार करने के लिए भविष्य के लिए सीख भी संश्लेषित करते हैं।

सतत विकास लक्ष्य

नीति आयोग को देश में एसडीजी को अपनाने और इनकी निगरानी की देखरेख करने तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दोहरा अधिदेश मिला हुआ है। नीति आयोग के अधीन कार्य, केवल समय-समय पर एसडीजी पर डाटा एकत्र करना नहीं है बल्कि लक्ष्यों और प्रयोजनों को सक्रिय रूप से साकार करना है।

वर्ष 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने विश्व का कायाकल्प: सतत विकास के लिए वर्ष 2030 का एजेंडा (ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट) नामक दस्तावेज को अंगीकार किया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 संबद्ध प्रयोजन शामिल थे। एसडीजी को वर्ष 2030 तक महत्व के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात्: लोग, पृथ्वी, समृद्धि, शांति और साझेदारी को संबोधित करने के लिए विश्व भर में लोगों के लिए एक सार्वभौमिक कॉल-टू-एक्शन के रूप में अंगीकार किया गया था। 17 एसडीजी और 169 प्रयोजन एकीकृत और अविभाज्य हैं तथा सतत विकास के तीन आयामों अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को संतुलित करते हैं। मानवता और पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों और प्रयोजनों

से अगले 15 वर्षों में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा की गई थी। सतत विकास के लिए वर्ष 2030 का एजेंडा: अपने विश्व का कायाकल्प, किसी को पीछे न छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की प्रतिज्ञा है। वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों और प्रयोजनों को लागू करने में हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से देशों की है। भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और 'सबका साथ, सबका विकास' या 'सामूहिक प्रयास, समावेशी विकास' का एजेंडा, एसडीजी के अनुरूप है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक के माध्यम से व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का प्रलेखन और रैंकिंग की जा रही है। नीति आयोग में एसडीजी वर्टिकल ने एसडीजी में प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रगति की निगरानी, कार्यों के मूल्यांकन और सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकार/प्रशासन के साथ परामर्श और कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

राज्य के परामर्शों में नेतृत्वकर्ताओं की बड़ी भागीदारी देखी गई, जो उच्चतम स्तर पर एसडीजी एजेंडे के स्वामित्व का संकेत देती है। राज्य कार्यशालाओं की अध्यक्षता ज्यादातर मामलों में राज्य के मुख्यमंत्री, या राज्य के मुख्य सचिव (राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रमुख) द्वारा की जाती है, जिसमें लाइन विभागों के वरिष्ठ सचिवों, एसडीजी से संबंधित विभागों के प्रमुखों, मध्य-स्तरीय अधिकारियों और सांख्यिकीय अधिकारियों की भागीदारी होती है। इन कार्यशालाओं में, नीति आयोग का प्रमुख एसडीजी भारत सूचकांक वर्टिकल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख निगरानी और मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है।

व्यापार एवं वाणिज्य

भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर कोयले और खनिजों के आयात के प्रभावों के परिमाण निर्धारित करने के लिए अध्ययन

आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के बड़े अवसर सृजित करने में खनिज और कोयला खनन की विशाल क्षमता को देखते हुए नीति आयोग ने पीएमओ के निर्देशन में आयात पर स्वदेशी उत्पादन के लाभों को उजागर करने के लिए एक अध्ययन किया। जीटीएपी-आधारित सीजीई मॉडलिंग का उपयोग न केवल आयात के प्रभाव को समझने के लिए किया गया बल्कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए भी किया गया। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बनाए गए ढांचे के आधार पर आयात और उत्पादन के प्रभाव पर अनुरूपण का विश्लेषण किया जा रहा है; कार्य प्रगति पर है। अध्ययन के लिए तेरह खनिजों, जैसे लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैंगनीज, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, स्वर्ण, चांदी, रॉक फॉस्फेट, हीरा और निकल तथा कोयले की पहचान की गई।

निर्यात संवर्धन परिषदों पर अध्ययन

इस अध्ययन में निर्यात प्रोत्साहन के मौजूदा संस्थागत ढांचे की भूमिका और उपलब्धियों की जांच की गई जो भारत में सभी स्तरों (केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर), विशेष रूप से निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), भारतीय निर्यात संगठन संघों (एफआईईओ) और कमोडिटी बोर्डों में मौजूद हैं।

अध्ययन में, भारत में निर्यात संवर्धन परिषदों और निर्यात संवर्धन के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के तरीकों की सिफारिशें करने के लिए, मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों द्वारा की गई पहल या निर्यात प्रोत्साहन के संबंध में नीतियों में बदलाव सहित निर्यात प्रोत्साहन के संबंध में मौजूदा घरेलू सर्वोत्तम परिपाटियों की जांच की जाती है। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तैयारी की जा रही है।

मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

मुक्त व्यापार करार (एफटीए) दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के बीच की व्यवस्था है जो मुख्य

रूप से उनके बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं। विश्व स्तर पर, एफटीए निष्पादित करने के संबंध में रुझानों में वृद्धि हो रही है। तदनुसार, व्यापार वर्टिकल, व्यापार करारों पर इनपुट प्रदान करने में वाणिज्य विभाग के साथ लगातार मिलकर कार्य कर रहा है। आर्थिक मॉडलिंग के उपयोग के माध्यम से, इस वर्टिकल ने वाणिज्य विभाग को व्यापार करारों (चालू और वर्तमान दोनों) के संभावित लाभ के अनुमान प्रदान किए हैं। इनमें भारत-यूएई सीईपीए और भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए पर इनपुट शामिल हैं, तथा जीसीसी, कनाडा, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ संभावित एफटीए के लिए इनपुट का योगदान दिया है।

वैश्विक व्यापार विश्लेषण परियोजना-संगणनीय सामान्य संतुलन (जीटीएपी-सीजीई) मॉडलिंग

इस वर्टिकल ने भारत के चल रहे एफटीए का विश्लेषण करने के लिए वैश्विक व्यापार विश्लेषण परियोजना (जीटीएपी) पर आंतरिक अनुसंधान किया। इसके अतिरिक्त, इसने नीति आयोग के भीतर संगणनीय सामान्य संतुलन (सीजीई) मॉडलिंग के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के प्रयास किए। इस वर्टिकल ने, सीजीई मॉडलिंग में अनुसंधान करने और आर्थिक मॉडलिंग में अत्याधुनिक अनुसंधान तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, नीति आयोग जीटीएपी कंसोर्टियम का भाग बनने की अनुमति प्राप्त कर ली है।

अन्य अध्ययन

एफटीए पर आईआईएफटी के एक अध्ययन की समीक्षा की गई। व्यापार करारों के प्रभाव पर कार्यप्रणाली और साहित्य के संदर्भ में अध्ययन की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी उत्पादों की जांच के लिए राज्य स्तर के निर्यात का एक अध्ययन किया गया था।

क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन

यह वर्टिकल समय-समय पर प्रासंगिक क्षेत्रों पर विभिन्न संगोष्ठियां/प्रस्तुतियां आयोजित करता है। इन सत्रों का उद्देश्य व्यापार और औद्योगिक नीति के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में मदद करना है।

यूएनईएससीएपी, आईटीसी-जिनेवा, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, यूरोमॉनिटर, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी और यूरोपीय आयोग के साथ कई सार्वजनिक संगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। ये संगोष्ठियां, विभिन्न क्षेत्रों जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डाटा, रूस-यूक्रेन संघर्ष, भौतिक इनपुट-आउटपुट सारणी, व्यापार वार्ता अनुसंधान, वैश्विक चुनौतियों के लिए योग्यता आदि के संबंध में थी। कुछ प्रमुख कार्यशालाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

इनपुट-आउटपुट (आईओ) विश्लेषण पर एडीबी प्रशिक्षण कार्यक्रम

नीति विश्लेषण और अनुसंधान के लिए इनपुट-आउटपुट सारणियों का उपयोग करने और ज्ञानार्जन क्षमता निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, व्यापार और वाणिज्य वर्टिकल ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से नीति आयोग के अधिकारियों के लिए इनपुट-आउटपुट विश्लेषण पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया।

इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के व्यापार और आर्थिक प्रभाव पर सत्र

इस वर्टिकल ने सब्सिडी के मौजूदा स्तर और बैटरी सेल के आयात पर निरंतर निर्भरता के तहत पेट्रोल और डीजल वाहनों को विस्थापित करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), विशेष रूप से हल्के और मध्यम शुल्क खंड में, के संभावित प्रभावों को उजागर करने के लिए एक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में कुछ नए सुझाए गए नीतिगत उपायों के माध्यम से बैटरी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नए विचारों पर समाधान का पता लगाया गया।

पर्यटन और संस्कृति

पर्यटन प्रभाग, पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कार्यनीतिक और दिशात्मक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह प्रभाग विशिष्ट पर्यटन, पारिस्थिकी-पर्यटन और आरोग्य पर्यटन, अवसंरचना विकास, क्षमता विकास और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जिम्मेदार और स्थायी पर्यटन नीतियों के विकास के माध्यम से भारत को पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रयास करता है। संस्कृति प्रभाग, भारत की कला, संस्कृति और विरासत के विकास, संरक्षण और संवर्धन प्रयास करता है।

ब्लू फ्लैग समुद्र तटों के प्रमाणन के लिए सुविधा

नीति आयोग ने ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की प्रमाणन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद की है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की कुल संख्या दस से बढ़कर बारह हो गई है। ये ब्लू फ्लैग समुद्र तट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दीव, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, ओडिशा, पुडुचेरी और तमिलनाडु के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

भारत में विरासत प्रबंधन में सामने आने वाली चुनौतियां और नीतिगत अनिवार्यता

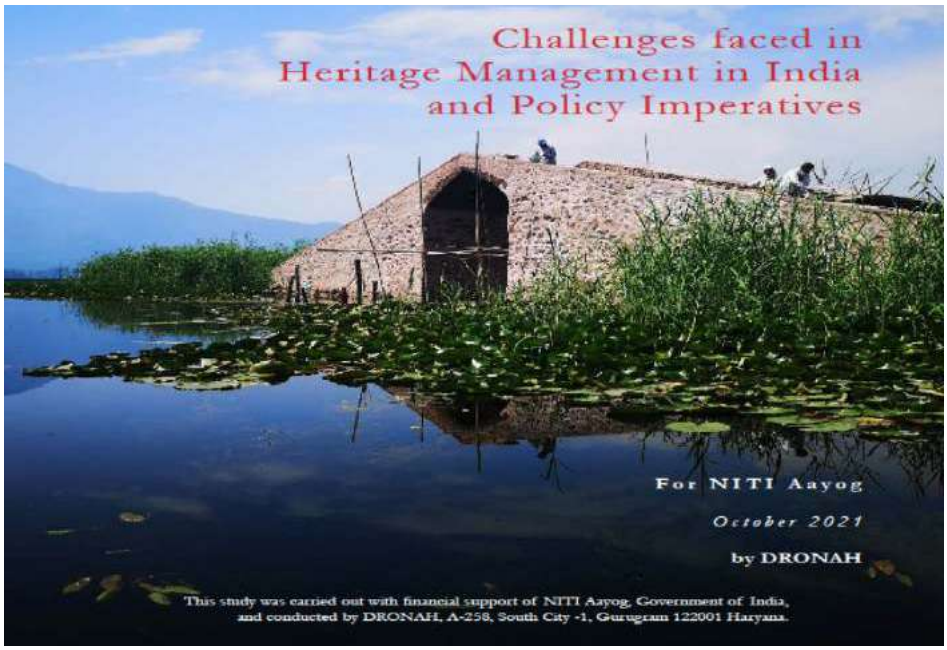

संस्कृति के तहत एक लाख विरासत संरचनाओं के चित्र सहित प्रलेखन का काम किया जा रहा है। डीआरओएनएएच के सहयोग से नीति आयोग द्वारा 'विरासत प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों' पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जिसमें देश भर में हमारी निर्मित विरासत की मात्रा, प्रकृति और स्थान की जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है ताकि इसकी दीर्घकालिक सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ प्राथमिक नीतियां और दिशानिर्देश तैयार किए जा सके।

कार्यनीति पत्र

दो कार्यनीति पत्र–(i) महामारी के मद्देनजर पर्यटन के विकास को बहाल करना; (ii) बुद्ध की भूमि में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना; विकसित किए गए हैं, जिनकी फरवरी 2022 में विश्व यात्रा पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) द्वारा विद्वत-समीक्षा की गई है।

स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ

नीति आयोग में स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ को मुख्य रूप से देश में साझेदारी और स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। यह प्रकोष्ठ, देश में वर्ष 2017 में आरम्भ किए गए एनजीओ दर्पण पोर्टल के माध्यम से एनजीओ और स्वयंसेवी संगठनों (वीओ) के डाटाबेस का रखरखाव करता है। यह पोर्टल एक प्रणाली-जनित विशिष्ट आईडी प्रदान करता है, जो मंत्रालयों/ विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान, विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम और सीएसआर के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने और 80-जी के तहत छूट के लिए आवेदन करने हेतु अनिवार्य है। अनुदान जारी करने से पहले मंत्रालयों/विभागों द्वारा दर्पण की विशिष्ट आईडी के माध्यम से एनजीओ का सत्यापन किया जाता है।

आज की तारीख में, एनजीओ दर्पण पोर्टल पर 1.5 लाख से अधिक एनजीओ पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, 43 मंत्रालयों/विभागों ने विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत एनजीओ/वीओ को अनुदान जारी किया।

एनजीओ डाटाबेस विभिन्न प्रकार की संचार और सूचना आवश्यकताओं के लिए, विशेष रूप से भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के भीतर सूचना प्रसार के लिए, संसाधनपूर्ण साबित हुआ है, और भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों और पुरस्कार कार्यक्रमों का विवरण प्रसारित करता है।

जल एवं भूमि संसाधन

यह वर्टिकल देश के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल और भूमि संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। यह उन्नत और रेडी-टू-यूज़ तकनीकों की क्षमता का दोहन करने के लिए नीति निर्देश और परामर्शी तैयार करता है तथा जल और भूमि संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। इस वर्टिकल का उद्देश्य, इन दो महत्वपूर्ण संसाधनों तक बाधा-मुक्त पहुंच को सक्षम करके सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाना है, और सभी हितधारक संगठनों को सतत विकास के बाधित हुए बिना सेवा प्रदायगी के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए तैयार करना है।

जल संसाधन में सर्वोत्तम परिपाटियों का संग्रह

विभिन्न सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों आदि द्वारा बहुत-सी सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाया गया है और ये सफल रही है। इस वर्टिकल ने कृषि, भूजल, वाटरशेड, जल अवसंरचना और जलवायु जोखिम और लचीलेपन को कवर करने वाली चुनिंदा सर्वोत्तम परिपाटियों, जिनका पूरे देश में अनुकरण किया जा सकता है, का विश्लेषण और प्रलेखन किया है।

सामुदायिक भागीदारी के साथ जल निकायों का कायाकल्प

नीति आयोग ने दो एनजीओ के साथ मिलकर 10 आकांक्षी जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना का निष्पादन किया, जिसमें सरकार ने परियोजना लागत का 26 प्रतिशत व्यय किया। एनजीओ भागीदार ने तकनीकी सहायता प्रदान की और सामुदायिक लामबंदी, निगरानी और मूल्यांकन, तथा तकनीकी अधिग्रहण किया, जो परियोजना लागत का लगभग 9 प्रतिशत था। लाभार्थी समुदाय ने अपने व्यय पर खुदी हुई मिट्टी/गाद को खेत में लाकर फैला दिया, जो परियोजना लागत का शेष 65 प्रतिशत है।

10 आकांक्षी जिलों में लगभग 430 जल निकायों का कायाकल्प किया गया है, जिससे अतिरिक्त लगभग 383 करोड़ लीटर सतही जल क्षमता का निर्माण किया जा रहा है (इसका एक गुणक भूजल पुनर्भरण को

ध्यान में रखते हुए बनाया गया होगा)। इससे लगभग 9.5 लाख लोगों की आबादी वाले 459 गांवों में जल सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पूरे देश में इस गतिविधि को विस्तारित करने के लिए चर्चा प्रगति पर है।

जल तटस्थता, जल सकारात्मकता और जल नकारात्मकता के आकलन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करना

जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में जल संरक्षण, दक्षता सुधार, अपशिष्ट जल उपचार, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण सर्वोपरि हैं। जैसा कि अधिक से अधिक उद्योग जल का चक्रीय उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जल तटस्थता और जल सकारात्मकता को परिभाषित करने और आकलन करने के लिए स्पष्ट पद्धति की आवश्यकता है। नीति आयोग ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सदस्यों के रूप में संबंधित विभागों के सचिवों के साथ नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया है और कार्य प्रगति पर है। शिक्षा जगत और उद्योग के प्रतिनिधि भी इस पहल का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं।

सिंचाई के लिए शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग

शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग को देश में अधिक गति नहीं मिली है, हालांकि कुछ राज्य कुछ हद तक औद्योगिक, भूनिर्माण और सिंचाई उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। शहरीकरण की गति को देखते हुए, आने वाले वर्षों में शोधित अपशिष्ट जल की मात्रा में बढ़ोत्तरी होगी और इसे लाभकारी उपयोग के लिए रखा जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, परिनगरीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक कार्यनीति पत्र तैयार किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी पत्र

जल और भूमि संसाधन वर्टिकल ने दो अंतरराष्ट्रीय तकनीकी पत्र (i) सितंबर/2022 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित विश्व जल कांग्रेस में भारतीय शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेतपत्र। (ii) अक्टूबर 2022 में एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जल-ऊर्जा-खाद्य गठजोड़ में भारत सरकार की दो योजनाओं (पीएमकेएसवाई और पीएम-कुसुम) का प्रभाव; प्रकाशित किए हैं। दोनों पत्रों को अंतर्राष्ट्रीय जल विशेषज्ञों से व्यापक सराहना मिली।

कृषि भूमि पट्टा अधिनियमों के कार्यान्वयन पर राज्य के प्रारंभिक अनुभव

एनआरएम, सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस, फ्लेम यूनिवर्सिटी, आईआईएम अहमदाबाद द्वारा नीति आयोग के सहयोग से एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसका शीर्षक, "बेहतर भूमि प्रशासन और समावेशी कृषि परिवर्तन के लिए कृषि भूमि पट्टा अधिनियम कार्यान्वयन पर राज्य के प्रारंभिक अनुभव का विश्लेषण" है।

महिला एवं बाल विकास

महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) प्रभाग, लैंगिक सशक्तिकरण के लिए नीति इनपुट प्रदान करता है और महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करता है। यह प्रभाग महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा और पहल तैयार करता है, और उनकी प्रगति और उनकी प्रभावकारिता की निगरानी करता है। यह प्रमुख हितधारकों और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विचार-मंच, शैक्षिक और नीति-अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करता है और साझेदारी को प्रोत्साहित करता है। यह प्रभाग, पोषण के संबंध में एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को भी अनुरक्षित करता है।

कुपोषण से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश की कार्य योजना का विकास (मुख्यमंत्री बाल सुपोषित योजना)

हिमाचल प्रदेश में आकांक्षी पोषण परिणाम प्राप्त करने और सहकारी संघवाद पर मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव और राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ 7 दिसंबर 2021 को एक बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉ. वीके पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री बाल सुपोषित योजना को विकसित करने के लिए एक साथ कार्य किया, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के अपने बजट भाषण में की थी।

जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान देना, पर्याप्त पोषण, टीकाकरण, उच्च जोखिम गर्भधारण, रक्ताल्पता, स्तनपान संबंधी काउंसलिंग के माध्यम से कम वजन वाले शिशुओं की अतिरिक्त देखभाल और कंगारू मदर केयर, और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं।

हिमाचल प्रदेश में विंग्स का पायलट स्केल-अप

8-9 सितंबर 2022 को नीति आयोग में सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वीके पॉल की अध्यक्षता **में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और शिशुओं के विकास के लिए एकीकृत हस्तक्षेप (विंग्स)** के पायलट स्केल-अप पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में पायलट मोड में विंग्स मॉडल के हस्तक्षेप को दोहराने में रुचि व्यक्त की।

आहार में पोषक अनाजों की शुरूआत के माध्यम से आहार विविधता में सुधार

यह वर्टिकल, मिलेट्स को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आईसीडीएस एवं एमडीएम जैसे सुरक्षा नेट कार्यक्रमों में शामिल करके मिलेट्स के उत्पादन और खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। मिलेट्स के उत्पादन और खपत पर राज्य-स्तरीय सर्वोत्तम परिपाटियों का एक सार-संग्रह जारी किया गया है।

रक्ताल्पता (एनीमिया) से निपटने के लिए कार्य योजना का विकास

28 अक्टूबर 2022 को डॉ. वीके पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में नीति आयोग में हाइब्रिड मोड में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम पर एक परामर्श आयोजित किया गया। परामर्श में, डॉ. राजीव बहल, महानिदेशक, आईसीएमआर, तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनीमिया नियंत्रण में राष्ट्रीय उत्कृष्टता और उन्नत अनुसंधान केंद्र, एम्स, नई दिल्ली, आर्थिक विकास संस्थान, यूनिसेफ और आईएफपीआरआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास, विशेष रूप से 0-3 वर्ष की महत्वपूर्ण आयु के लिए, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता में अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 0-3 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास पर अपने मॉडल साझा करने के लिए परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया था। कई दौर की आंतरिक चर्चाओं और परामर्शों के आधार पर, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास पर एक मसौदा नीति पत्र तैयार किया गया है और यह पूरा होने के अंतिम चरण में है।

एनएफएचएस 5 सहयोग

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–राउंड 5 (2019-21) के तथ्यपत्रक और रिपोर्ट जारी होने

के बाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आईआईपीएस के सहयोग से एक एनएफएचएस 5 सहयोग का गठन किया गया है, जो नीति आयोग द्वारा अभिचिह्नित विशिष्ट प्राथमिकता वाले प्रश्नों के लिए एनएफएचएस 5 डाटा का इकाई-स्तरीय विश्लेषण करेगा।

'टेक होम राशन: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अच्छी परिपाटियां' रिपोर्ट का लोकार्पण

नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 30 जून 2022 को 'टेक होम राशन: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अच्छी परिपाटियां' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने सदस्य (स्वास्थ्य) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति में जारी किया। रिपोर्ट जारी किए जाने के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के उप निदेशक भी मौजूद थे।

इस रिपोर्ट में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टेक होम राशन मूल्य श्रृंखला के कार्यान्वयन में अपनाई गई अच्छी और नवीन परिपाटियों का एक सेट प्रस्तुत किया गया है। अच्छी परिपाटियों की एक सूची तैयार करने के लिए उत्पादन, सूत्रीकरण, वितरण, लेबलिंग, पैकेजिंग, निगरानी, गुणवत्ता आश्वासन, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन से संबंधित पहलुओं की समीक्षा की गई है। यह रिपोर्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर-ज्ञानार्जन के अवसर उत्पन्न करेगी।

कर्नाटक में कुपोषण और एनीमिया के उन्मूलन के लिए कार्यनीति का विकास

नीति आयोग में सदस्य (स्वास्थ्य, डॉ. वी के पॉल की अध्यक्षता में 9 सितम्बर, 2022 को **कर्नाटक में स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों** पर एक बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार और महिला एवं बालक विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में कुपोषण और एनीमिया के उन्मूलन के लिए कार्यनीति के विकास में नीति आयोग के समर्थन का अनुरोध किया है। तदनुसार, नीति आयोग ने 7 दिसंबर 2022 को कर्नाटक में एक कार्यशाला की योजना बनाई हैं।

तीव्र कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन

गंभीर तीव्र कुपोषण वाले लगभग 85-90 प्रतिशत बच्चों का समुदाय में उपचार और प्रबंधन किया जा सकता है। समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों में रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के लिए बहुक्षेत्रीय संसाधनों का लाभ उठाया जाता हैं। तीव्र कुपोषण के समुदाय-आधारित प्रबंधन (सीएमएएम) पर राज्य-स्तरीय परिपाटियों का एक मसौदा सार-संग्रह विकसित किया गया है, और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आकांक्षी जिलों के लिए जेंडर और पोषण पुस्तिकाएं

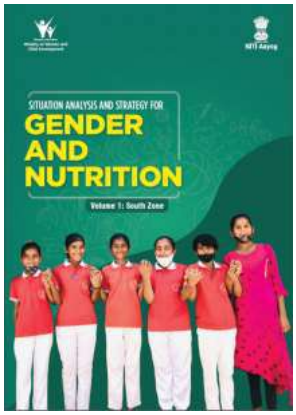

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नीति आयोग से 'महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव' विषय पर आकांक्षी जिलों में क्षेत्रीय बैठकों में वितरण हेतु जेंडर और पोषण पर एक हिमायत पुस्तिका तैयार करने का अनुरोध किया। तदनुसार, महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण परिणामों में सुधार के लिए स्थिति विश्लेषण और कार्यनीति, सर्वोत्तम परिपाटियों और राज्य-विशिष्ट मुख्य विशेषताओं तथा जेंडर और पोषण में सुधार के लिए सिफारिशों को कवर करते हुए पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं।

खंड

08

प्रशासन और सहायक इकाइयां

प्रस्तावना

नीति आयोग का प्रशासन प्रभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सेवा नियमावली और भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन प्रभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों, भर्ती, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा मामलो से संबंधित अदालती मामलों के सभी पहलुओं से संबंधित कार्यों को देखता है और इन ममालों में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना भी प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक डोमेन में नीति आयोग की नीतियों के कार्यनीतिक संचार का भी कार्य सौंपा गया है। हिंदी अनुभाग ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग की दिशा में अपने प्रयास जारी रखें।

टीम नीति के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करना

नीति आयोग के स्टाफ में सरकारी पदाधिकारियो के साथ-साथ कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञों को पार्श्वनियुक्ति के आधार पर खुले विज्ञापनों के माध्यम से नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञों की इस आवश्यक नियुक्ति की अनुमति देने और इसे सुकर बनाने के लिए, यूपीएससी ने अपने अनिवार्य परामर्श को समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप, नीति आयोग ने देश भर में उपलब्ध प्रतिभा पूल से प्रतिभाशाली प्रोफेशनलों और विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए भर्ती के नए रूपों की शुरुआत की।

वर्ष के दौरान, नीति प्रशासन ने सभी आवश्यक चयन औपचारिकताओं को पूरा किया और वरिष्ठ लीड (एचआर), एक वरिष्ठ विशेषज्ञ और एक विशेषज्ञ के पद पर नियुक्तियां की है। इसके अलावा नीति आयोग में दो एसोसिएट और एक तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

नीति प्रशासन ने ज्ञान और नवाचार हब (केआईएच) में जल संसाधन, औद्योगिक नीति और विदेशी निवेश, स्वास्थ्य, अर्थनीति और वित्त, तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में वरिष्ठ सलाहकार/ सलाहकार; अर्थ और वित्त, सतत विकास लक्ष्य, शिक्षा और संचार के क्षेत्रों में वरिष्ठ लीड/ लीड तथा विधि, पीएएमडी, अर्थ और नीति के क्षेत्रों में वरिष्ठ विशेषज्ञ/विशेषज्ञ के पदों के लिए विज्ञापन दिया है। इसके अतिरिक्त, फ्लेक्सी पूल में सार्वजनिक निजी भागीदारी, अर्थशास्त्र, परियोजना मूल्यांकन, शहरीकरण, स्वास्थ्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में वरिष्ठ एसोसिएट के छह पद और जी20 सचिवालय से संबंधित कार्य के लिए अवर सचिव के एक पद के लिए भी विज्ञापन दिया गया है।

महानिदेशक, विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय, वरिष्ठ लीड (मानव संसाधन), और वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (औद्योगिक नीति और विदेशी निवेश) को एसीसी के अनुमोदन से नियुक्त किया गया है, तथा वरिष्ठ विशेषज्ञ (विधि) और विशेषज्ञ प्रत्येक का एक-एक पद संविदा के आधार पर भरा गया है। नीति आयोग में दो एसोसिएट और एक तकनीकी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन ने अन्य विभागों के साथ संवर्गित पदों और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत विभिन्न अन्य रिक्तियों को भरने के लिए भी समय पर कार्रवाई की।

विचार मंच, जिसके लिए प्रोफेशनल की भर्ती में अधिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है, के रूप में कार्य करने के लिए नीति आयोग के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, ऐसे युवा प्रोफेशनलों, परामर्शदाताओं और वरिष्ठ परामर्शदाताओं की आवश्यकता महसूस की गई, जिनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता है। इन युवा प्रोफेशनलों, परामर्शदाताओं और वरिष्ठ परामर्शदाताओं से संचार, विकासात्मक नीति, अर्थशास्त्र, शिक्षा, इंजीनियरिंग, वित्त, अवसंरचना, सामाजिक विज्ञान, शहरी नियोजन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्य करने की उम्मीद की जाती है।

इस संबंध में नीति आयोग में परामर्शदाता (सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ), मानव संसाधन व्यवसाय भागीदार (वरिष्ठ परामर्शदाता), वरिष्ठ परामर्शदाता (एसडीजी), परामर्शदाता ग्रेड- II/। (संचार और संपादकीय) तथा अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) में नवोन्मेष लीड के पदों पर नियुक्ति की गई। नीति आयोग में परामर्शदाता ग्रेड- II (एडीपी) के पद और डीएमईओ में परामर्शदाता के पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया था। नीति (राज्य समर्थन मिशन) और डीएमईओ के लिए युवा प्रोफेशनलों/परामर्शदाताओं के पदों पर और अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं/युवा प्रोफेशनल के नियोजन के लिए दिशानिर्देशों के तहत इन विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए, नीति आयोग का प्रशासन, समयबद्ध तरीके से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का उपयोग करने के उद्देश्य से, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, अनुवीक्षण समिति और परामर्शिता मूल्यांकन समिति के माध्यम से क्रमशः अनुवीक्षण किया जाता है और साक्षात्कार आयोजित करता है।

नीति आयोग के कर्मचारियों की संरचना

क्रम सं.	अधिकारियों का स्तर	सरकारी	पार्श्व प्रवेशी प्रोफेशनल	आउटसोर्स किए गए अन्य प्रोफेशनल	कुल
1	अपर सचिव और समकक्ष	8	2	0	10
2	संयुक्त सचिव और समकक्ष	9	0	6	15
3	निदेशक और समकक्ष	19	17	0	36
4	उप सचिव और समकक्ष	30	3	8	41
5	अवर सचिव और समकक्ष	50	6	23	79
6	अनुसंधान अधिकारी और समकक्ष	28	15	0	43
7	अनुभाग अधिकारी और समकक्ष	45	0	93*	138
8	सहायक अनुभाग अधिकारी और समकक्ष	61	0	0	61
9	अन्य सहायक कर्मचारी	122	0	0	122
10	आउटसोर्स कार्मिक	0	0	157	157
	कुल	**372**	**43**	**287**	**702**

* युवा प्रोफेशनल

नीति आयोग द्वारा 2016 में शुरू की गई शिक्षुता योजना, 22 नवंबर 2018 के संशोधित नीति शिक्षुता दिशानिर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2022-23 में भी जारी है। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसरण में, एक व्यापक शिक्षुता पोर्टल को कार्यशील बनाया गया था, जिसने नीति शिक्षुता योजना के विकेंद्रीकरण और व्यवस्थित कार्यान्वयन को सक्षम बनाया, इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त की गई। यह योजना भारत या विदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में नामांकित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों या अनुसंधान विद्वानों को प्रशिक्षु के रूप में संलग्न करने का प्रयास करती है। प्रशिक्षुओं को नीति आयोग के अंतर्गत विभिन्न वर्टिकल/प्रभागों/एकक का अनुभव प्रदान किया जाता है।

नीति आयोग द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया नीति फैलोशिप कार्यक्रम 29 दिसंबर 2016 के फैलोशिप दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भी जारी है, जो नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है और विश्व भर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को उपयोग करने का एक प्रयास है, ताकि उन्हें भारत सरकार के प्रमुख विचार-मंच के साथ जोड़ा जा सके। नीति फैलोशिप, नीतिगत पहलों में उच्च क्षमता के वरिष्ठ और मध्य-कैरियर वाले प्रोफेशनलों को शामिल करने और किसी विशेष डोमेन की उनकी विशेषज्ञता से लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करती है।

अन्य उपलब्धियों में नीति भवन को अग्नि अनुकूल 5-सितारा ऊर्जा-दक्ष भवन बनाना, पांचवीं मंजिल पर सीसीटीवी कैमरों की संस्थापना, तथा नीति आयोग और मैसर्स ईईसीएल के बीच सकार्मिक पट्टा आधार पर पांच टाटा नेक्सॉन ईवी किराए पर लेने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

आजीविका प्रबंधन

नीति आयोग में आजीविका प्रबंधन (सीएम) अनुभाग प्रशिक्षण और कैरियर प्रबंधन से संबंधित मामलों के साथ-साथ नीति आयोग में सभी स्तरों के सभी अधिकारियों/कार्मिकों के विदेशी प्रशिक्षण और विदेश दौरों से संबंधित मामलों को संभालता है।

अप्रैल और दिसंबर 2022 के बीच, नीति आयोग में चवालीस अधिकारियों/कार्मिकों, जिसमें उपाध्यक्ष, सदस्य और विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) और प्रधानमंत्री के ईएएस के कार्यालय से संबद्ध अधिकारी/कार्मिक शामिल हैं, को विभिन्न देशों में आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों (कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/बैठकों/सम्मेलनों आदि) में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। नीति आयोग के दो अधिकारियों को ऑफलाइन विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया गया था, जबकि एक अधिकारी को उक्त अवधि के दौरान एक ऑनलाइन विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

सीएसएस, सीएससीएस, सीएसएसएस और अन्य सेवाओं/संवर्गों/पदों से संबंधित नीति आयोग के बयालीस अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसएम) या अन्य संवर्ग विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों या किसी अन्य प्रशिक्षण एजेंसी/संगठन द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन या ऑफलाइन घरेलू या घरेलू स्तर पर आयोजित संवर्ग प्रशिक्षण या अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

नए शामिल हुए अधिकारियों/कर्मियों को नीति आयोग, अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम), विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) की संरचना, भूमिका, कार्यप्रणाली, कार्यक्रमों और ई-ऑफिस का उपयोग आदि से परिचित कराने के लिए नीति आयोग द्वारा 16-17 अगस्त 2022 और 1-2 सितंबर 2022 के दौरान नीति आयोग (नीति मुख्यालय के साथ-साथ एआईएम एवं डीएमईओ सहित) के नव नियुक्त फ्लेक्सी-पूल अधिकारियों और परामर्शदाता पूल कर्मियों (अर्थात एसोसिएट्स/वरिष्ठ एसोसिएट्स/विशेषज्ञ/वरिष्ठ विशेषज्ञ और युवा पेशेवर/परामर्शदाता आदि) के लिए दो दिवसीय आंतरिक प्रवेशन-सह-अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

23-24 मई 2022 को राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी (एनएएए), शिमला से भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए दो दिवसीय अनुभव दौरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 29 जून 2022 को सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय से भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए भी नीति आयोग द्वारा एकदिवसीय नीति आयोग अनुभव दौरे का आयोजन किया गया। 12 सितंबर, 13 अक्तूबर, और 16 नवंबर 2022, को नीति आयोग में विदेश मंत्रालय के क्रमशः 60वें, 61वें और 62वें भारत के बारे में जाने (केआईपी) के तहत दुनिया के विभिन्न देशों से भारत आने वाले भारतीय मूल के युवाओं के लिए संवाद सत्रों के साथ अनुभव दौरा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। 14 अक्तूबर 2022 को आईसीसीआर, विदेश मंत्रालय के जेन-नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के 6वें बैच में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के विदेशी प्रतिनिधियों के लिए नीति आयोग में संवाद सत्र के साथ एक अनुभव दौरा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

संचार और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में चार्ट, मैप एवं उपकरण तथा फोटोस्टेट एकक और संपादकीय एवं सोशल मीडिया सेल शामिल हैं। चार्ट, मैप एवं उपकरण यूनिट नीति आयोग की केन्द्रीकृत डिजाइन एवं

तकनीकी सहायता एकक है। यह नीति आयोग के सभी वर्टिकल एवं प्रभागो को लॉजिस्टिक, तकनीकी एवं उपकरण सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, एकक द्वारा पीएम स्तरीय बैठकों के साथ-साथ विभिन्न अन्य वर्चुअल बैठकों और संगोष्ठियों सहायता प्रदान की गई। संपादकीय एवं सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का प्रबं धन इस समय दो पूर्णकालिक पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जो संपादकीय, समाचार, सोशल मीडिया तथा पीआर से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए नीति आयोग के सभी वर्टिकल, संबद्ध संस्थाओं तथा वरिष्ठ अधिकारियों, रचनात्मक एवं डिजिटल मीडिया प्रवर्धन एजेंसियों तथा प्रेस सूचना कार्यालय के साथ नियमित रूप से बातचीत एवं संपर्क करते हैं।

शासी परिषद सचिवालय

सचिवालय ने शासी परिषद (जीसी) की 6वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट और शासी परिषद की 7वीं बैठक के लिए कार्यसूची टिप्पणियां तैयार करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया। शासी परिषद की 7वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर आगे की कार्रवाई जारी है।

एक समन्वय केंद्र बिंदु के रूप में, सचिवालय ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में साप्ताहिक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें (एसओएम) आयोजित कीं। सचिवालय ने वरिष्ठ प्रबंधन समिति (एमएसी) की बैठकों के आयोजन की सुविधा प्रदान की, जिसे हाल ही में वरिष्ठ प्रबंधन परिषद (एसएमसी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में भी आयोजित की गई थी। इसने नीति आयोग द्वारा आउटसोर्स किए जाने वाले अनुसंधान प्रस्तावों/परियोजनाओं/अध्ययनों पर विचार-विमर्श के अतिरिक्त प्रमुख नीतियों और प्राथमिकताओं के साथ-साथ सुझावों, उनके कार्यान्वयन के लिए परस्पर-कार्यक्षेत्रीय कार्यनीतियों पर चर्चा की सुविधा प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, इसने विशेष रूप से पिछले सात वर्षों में नीति आयोग से संबंधित उपलब्धियों/नीतिगत निर्णयों के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त संदर्भों के लिए, स्वतंत्रता दिवस के भाषण से उत्पन्न होने वाले इनपुट और कार्य बिंदुओं, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ माननीय प्रधानमंत्री के संवाद के कार्य बिंदु, आदि के संबंध में संबंधित वर्टिकल/प्रभागों से सूचनाओं का समन्वय और संकलन किया। इसने संसदीय प्रश्नों, आरटीआई, स्थायी समिति संबंधी मामलों, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और वीआईपी संदर्भों सहित अन्य मामलों को भी संसाधित किया।

हिंदी अनुभाग

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, हिंदी अनुभाग ने वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रगामी प्रयोग की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।

राजभाषा विभाग को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी गई और संबद्ध कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट की नियमित रूप से समीक्षा की गई। हिंदी अनुभाग ने वार्षिक रिपोर्ट, अनुदान मांगों, संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित सामग्री, मंत्रिमंडल के लिए नोट, संसदीय प्रश्न, अधिसूचनाओं, समझौता ज्ञापन, प्रपत्र और प्रारूप, पत्र आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों का अनुवाद किया।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। नीति आयोग के सभी अनुभागों तथा इससे संलग्न कार्यालयों को सूचना एवं निर्देशों के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा अन्य आदेश/निर्देश अग्रेषित किए गए।

हिंदी सलाहकार समिति

दिनांक 5 मई 2022 के संकल्प संख्या ई-11011/1/2018-हिंदी के तहत समिति का पुनर्गठन किया गया है। माननीय योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता वाली समिति में 15 गैर-सरकारी सदस्य और 13 सरकारी सदस्य हैं। इस समिति के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक प्रस्तावित है। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी), सलाहकार (प्रशासन) की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह समिति समय-समय पर हिंदी के प्रयोग के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित सुझाव और उपायों की अनुशंसा करती है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से इस समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा नीति आयोग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों को भी नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है।

हिन्दी में मूल टिप्पण एवं मसौदा लेखन कार्य हेतु प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में टिप्पण एवं मसौदा लेखन के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2022-23 में भी जारी रखा गया। इस योजना में 5000 रुपये के दो प्रथम पुरस्कार, 3000 रुपये के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000 रुपये के पांच तृतीय पुरस्कार शामिल हैं। इस योजना के तहत नौ पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

हिंदी में डिक्टेशन के लिए नकद पुरस्कार योजना

हिंदी में डिक्टेशन (श्रुतलेख) करने वाले अधिकारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना प्रचलित है। इस योजना के तहत 5000-5000 रुपये के दो नकद पुरस्कार (एक हिंदी भाषी के लिए और दूसरा गैर-हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए) का प्रावधान है।

हिंदी पखवाड़ा

14 से 30 सितम्बर 2022 तक आयोजित हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया; इनमें हिंदी निबंध लेखन, अनुवाद, टिप्पण/मसौदा लेखन और तात्कालिक भाषण शामिल थे। नीति आयोग के मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए हिंदी टंकण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। 35 अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

हिंदी कार्यशाला

वर्ष के दौरान, फरवरी, अप्रैल और अगस्त 2022 माह में तीन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य अधिकारियों को हिंदी में और अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इन कार्यशालाओं में पचास से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निरीक्षण

राजभाषा नीति के कार्यान्वियन की देखरेख के लिए, हिंदी अनुभाग द्वारा नीति आयोग के संबद्ध कार्यालयों–डीएमईओ और एनआईएलईआरडी–का निरीक्षण किया गया।

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

नीति आयोग पुस्तकालय, भारत सरकार के मंत्रालयों में सबसे पुराने और सबसे बृहत पुस्तकालयों में से एक है। इस पुस्तकालय में रिपोर्ट, जर्नल-बाउंड वॉल्यूम और 1,326 श्रव्य -दृश्य मदें (एल्बम और सीडी) के अलावा 1.85 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। इसमें योजना आयोग के दौर के दस्तावेजों का संग्रह भी है। इसके पास अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की 123 दैनिकी, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का सब्सक्रिप्शन है। यह नीति नियोजन और अनुसंधान का समर्थन करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरणों के लिए ऑनलाइन डाटाबेस और लाइसेंस तक पहुंच जैसी आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित है। नीति आयोग पुस्तकालय को वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार, सफलतापूर्वक श्रेणी IV पुस्तकालय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह पुस्तकालय, संस्थान के सभी अधिकारियों को इस समृद्ध डाटाबेस तक पहुँच प्रदान करता है। नीति आयोग के बाहर के अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों में नामांकित शोधार्थियों के लिए आंतरिक परामर्श सुविधा भी उपलब्ध है।

पुस्तकालय को इसके विभिन्न प्रकार्यों और उपयोगकर्ता सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत करके पूरी तरह से स्वचालित किया गया है। नीति आयोग के इंट्रानेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डाटाबेस तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराई जाती है। नीति आयोग के पुस्तकालय के सदस्यों को यूआरएल: https://nitiaayoglibrary.in के माध्यम से ई-संसाधनों के लिए रिमोट एक्सेस भी प्रदान किया जा रहा है। इस पुस्तकालय को एक मोबाइल ऐप – एमलाईब्रेरी के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है, जो एंड्रॉइड-आधारित उपकरणों के लिए गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल डिवाइसों के लिए ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

पुस्तकों की खरीद, पत्रिकाओं/दैनिकी का सब्सक्रिप्शन, तथा डाटाबेस और पुस्तकालय के विकास सहित गतिविधियों का प्रबंधन एक पुस्तकालय समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान समिति में अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ सलाहकार, सदस्य के रूप में सलाहकार और सहायक निदेशक (राजभाषा) और सदस्य-संयोजक के रूप में निदेशक (पुस्तकालय) शामिल हैं। नियमित अंतराल पर पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चयन करने के लिए वार्षिक रूप से समिति की एक से दो बैठकें आयोजित की जाती हैं।

अपनी नियमित सेवाओं के हिस्से के रूप में, पुस्तकालय एक दैनिक बुलेटिन तैयार करता है–जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित अर्थव्यवस्था, वित्त और नीति पर वैश्विक और राष्ट्रीय समाचार होते हैं, एक दैनिक डाइजेस्ट–जिसमें नीति आयोग से संबंधित समाचार लेख और विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न विषयों पर ऑप-एड होते हैं, साप्ताहिक बुलेटिन–विशिष्ट क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग आदि पर प्रमुख अपडेट को कवर किया जाता है। मासिक आधार पर पुस्तकालय नई पुस्तकों के प्राप्त होने, पुस्कालय द्वारा सब्सक्राइब की जा रही प्रमुख आवधिक-पत्रिकाओं के सार और पत्रिकाओं की सामग्री की तालिका भी साझा करता है। नीति आयोग पुस्तकालय समय-समय पर दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में पढ़ने वाले पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों/प्रोफेशनलों को व्यावहारिक प्रशिक्षण/शिक्षुता भी प्रदान करता है।

पुस्तकालयों का एकीकरण

अभी तक, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अपने स्वयं के पुस्तकालय हैं, लेकिन वे पारंपरिक या हाइब्रिड मोड में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसलिए, वर्तमान डिजिटल परिवेश में भी, किसी विशेष पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों को खोजना चुनौतीपूर्ण है। डिजिटल तरीके से सरकारी पुस्तकालयों का एकीकरण संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद करेगा और संसाधनों तक पहुँचने के लिए एक एकल डिजिटल मंच प्रदान करेगा,

जो अंततः एक सरकार एक पुस्तकालय (डिजिटल) बन सकता है। नीति आयोग ने भारत सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों में स्थित पुस्तकालयों के एकीकरण को लागू करने के लिए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया। नीति आयोग पुस्तकालय इस परियोजना का समन्वय कर रहा है। कई बैठकों के बाद, यह दोहराया गया कि कार्यान्वित किए जाने पर यह परियोजना, एक मंत्रालय के अधिकारियों के लिए भारत सरकार के पुस्तकालयों में मौजूदा पुस्तकों तक बेहतर पहुंच प्रदान करते हुए भाग लेने वाले पुस्तकालयों में मौजूदा संसाधनों के उपयोग को इष्टतम करेगी, जिससे वे एक-दूसरे से दस्तावेज़ प्राप्त कर सकेंगे और ई-संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। कार्यबल ने पुस्तकालयों के एकीकरण को लागू करने के संबंध में सितंबर 2022 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यह पुस्कालय, भारतीय पुस्तकालय संघ (आईएलए), केंद्रीय सरकार पुस्तकालय संघ (सीजीएलए) और दिल्ली पुस्तकालय संघ (डीएलए) का एक संस्थागत सदस्य है। निदेशक (पुस्तकालय) और अन्य अधिकारियों ने समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/आईएलए, आईएएसएलआईसी और सीजीएलए की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया/सम्मिलित हुए।

ओएम एंड सी अनुभाग

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का आयोजन

8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर 'मानवता के लिए योग' का आयोजन

ओएमएंडसी अनुभाग ने 21 जून 2022 को **'मानवता के लिए योग'** की थीम के साथ **8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2022 का आयोजन** किया। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और आयुष मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई)-2022 के आयोजन की पृष्ठभूमि और आयुष मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य योग प्रोटोकॉल के आलोक में, नीति पोर्टल पर जानकारी के लिए आंतरिक दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग की वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) का प्रतीक चिह्न (लोगो) प्रदर्शित किया गया; नीति पोर्टल पर आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया योग ब्रेक (वाई-ब्रेक प्रैक्टिस) मोबाइल एप्लिकेशन, कामकाजी पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया पांच मिनट का योग प्रोटोकॉल परिचालित किया गया था; 13 से 20 जून 2022 तक आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) के सहयोग से

विशेषज्ञों द्वारा योग कार्यशाला, योग डेमो और योग व्याख्यान जैसी गतिविधियों सहित नीति आयोग में एक योग प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था।

21 जून 2022 को योग दिवस 2022 समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारम्भ नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने किया और इसमें नीति आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

ओएम एंड सी अनुभाग द्वारा आयोजित और शुरू की गई गतिविधियाँ:

- ओएम एंड सी अनुभाग जनवरी 2018 से सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायतों को रख-रखाव करता है और ऑनलाइन चैनल के माध्यम से लोक शिकायतों/अपीलों का निपटान करता है।
- अनुभाग ने ' राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा' (राष्ट्रीय एकता) का आयोजन किया, तथा माननीय उपाध्यक्ष, नीति आयोग द्वारा 31 अक्तूबर 2022 को नीति आयोग /डीएमईओ/एआईएम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई।

31 अक्तूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा दिलाई गई शपथ

- संविधान दिवस का आयोजन–नीति आयोग/डीएमईओ/एआईएम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 26 नवंबर 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया।
- लोक शिकायतों, संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों, संसदीय आश्वासनों आदि के निपटान के लिए 2 से 31 अक्तूबर, 2022 तक विशेष अभियान चलाया गया।
- सीपीजीआरएएमस 7.0 एक्सेल फ्रेमवर्क को क्यूसीआई टीम, डीएआरपीजी के मार्गदर्शन में अंतिम रूप दिया गया है, सभी प्रासंगिक क्षेत्रों को भरा गया है और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर डाटा फ्रीज कर दिया गया है। नीति आयोग के लिए सीपीजीआरएएमएस 7.0 संस्करण को डीएआरपीजी द्वारा प्रचलनाधीन कर दिया गया है।

आरटीआई प्रकोष्ठ

आरटीआई प्रकोष्ठ https://rtionline.gov.in पर ऑनलाइन और डाक द्वारा भौतिक रूप से प्राप्त सभी आरटीआई प्रश्नों का उत्तर देता है। वर्ष 2021-2022 और 2022-23 के दौरान, प्रकोष्ठ निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल रहा:

वर्ष 2021-22 (1 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक):

- 125 आरटीआई आवेदन और नौ अपीलें प्राप्त हुईं।
- केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष चार सुनवाई में भाग लिया।

वर्ष 2022-23 (1 जनवरी 2022 से 30 सितंबर 2022 तक):

- 531 आरटीआई आवेदन और 74 अपीलें प्राप्त हुईं।
- केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष नौ सुनवाई में भाग लिया।

सतर्कता अनुभाग

नीति आयोग के सतर्कता अनुभाग को संस्था में कार्यरत अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्यनिष्ठा की कमी के मामलों को निपटान करने का कार्य सौंपा गया है। यह अधिकारियों को सतर्कता स्थिति और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी जिम्मेदार है। जनवरी से अक्तूबर 2022 के बीच डीएमईओ और नीति आयोग के अधिकारियों को लगभग 550 सतर्कता निकासी जारी की गईं। अनेक आरटीआई प्रश्नों का भी निपटारा और निस्तारण किया गया है। कुछ अधिकारियों के विरुद्ध उचित प्रक्रियाओं/कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

निवारक सतर्कता

31 अक्तूबर से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह की थीम **"भ्रष्टाचार मुक्त भारत – विकसित भारत"** थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने संस्थान के सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस वर्ष का अभियान जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) के

बारे में जागरूकता फैलाने पर केंद्रित था। नीति भवन में सूचनात्मक बैनर लगाए गए थे, तथा नीति आयोग के अधिकारियों/अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से ई-सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के साथ क्या करें और क्या न करें जारी किया गया था।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

अनुलग्नक

अनुमोदित शोध अध्ययनों, पूर्ण किए गए अध्ययनों, स्वीकृत सेमिनार और प्रदान किए गये लोगो समर्थन की सूची

तालिका-1.1: वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत नए शोध अध्ययनों की सूची (31 दिसंबर 2022 तक)

S. No.	अध्ययन का शीर्षक	संगठन का नाम
1.	जैव-उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन के लिए गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर शोध अध्ययन	नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईएआर), नई दिल्ली
2.	राज्य स्तर पर सुनिश्चित सब्सिडी के युक्तिकरण पर शोध अध्ययन	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)
3.	इंडिया जी 20 अध्यक्षता पर शोध अध्ययन	मैसर्स ओलिवर वायमन, मुंबई
4.	डेलॉइट द्वारा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना	मेसर्स डेलॉइट, गुरुग्राम
5.	सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए एप्रोच पेपर को तैयार करना	मेसर्स ट्राईलीगल , नई दिल्ली
6.	खाना बनाने वाले कोयले के आयात को कम करने के लिए घरेलू खाना बनाने वाले कोयले की उपलब्धता बढ़ाना	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस), बेंगलुरु
7.	बिजली क्षेत्र में नियामक ढांचे की प्रभावशीलता में सुधार पर शोध अध्ययन	आईआईटी कानपुर
8.	अटल टिंकरिंग लैब्स के आकलन पर शोध अध्ययन	मैसर्स एथेना इन्फोनॉमिक्स , चेन्नई
9.	स्वतंत्रता-पूर्व कानूनों की समीक्षा	कानूनी नीति के लिए विधि केंद्र

तालिका-1.2: वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे किए गए अध्ययन (31 दिसंबर 2022 तक)

S. No	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान / शोधकर्ता
1.	कृषि बायोमास से खाद/उर्वरक का बड़े पैमाने पर उत्पादन	आईसीएआर- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
2.	भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के चुनिंदा निर्णय के हाइलाइट आर्थिक प्रभाव पर शोध अध्ययन	सीयूटीएस इंटरनेशनल, जयपुर
3.	मेडिकल कॉलेजों में समय पर भर्ती और फैकल्टी के बोर्डिंग की दिशा में बाधाओं पर शोध अध्ययन	मैसर्स सहमंथन प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम
4.	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना और मध्यम अवधि प्रभाव के मूल्यांकन पर शोध अध्ययन	डीओओआरएस, नोएडा
5.	इंडिया विजन 2036-37- एक मैक्रो इकोनोमेट्रिक दृष्टिकोण पर शोध अध्ययन	आर्थिक विकास के लिए ईजीआरओडब्ल्यू फाउंडेशन , नोएडा
6.	भारत में विमानन क्षेत्र के लिए एमआरओ उद्योगों के विकास पर शोध अध्ययन	मेसर्स ब्रीफ, इंडिया
7.	ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे व्यवसायों/व्यापारियों का एकीकरण	मैसर्स पीडब्ल्यूसी, गुरुग्राम
8.	बाल विवाह निषेध (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 2016	नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलुरु
9.	इंडिया विजन 2046-47 एक मैक्रो इकोनोमेट्रिक दृष्टिकोण पर अनुसंधान अध्ययन	आर्थिक विकास के लिए ईजीआरओडब्ल्यू फाउंडेशन , नोएडा
10.	सीसीयूएस पॉलिसी फ्रेमवर्क और भारत में इसकी तैनाती तंत्र	एम एन दस्तूर एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड

तालिका 1.3: वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत लोगो समर्थन की सूची (31 दिसंबर 2022 तक)

S. No	कार्यक्रम का नाम	आयोजक का नाम
1.	विश्व स्वास्थ्य सेवा सम्मेलन और एक्सपो (डब्ल्यूएचसी C22)	ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन, नई दिल्ली
2.	इलेक्ट्रिक वाहनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन और अधिनिर्णय	सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी), गुरुग्राम
3.	11वां संस्करण बिग सीआईओ शो एंड अवार्ड्स	त्रेस्कोन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु
4.	"कम कार्बन सीमेंट: एनसीबी पहल" पर राष्ट्रीय कार्यशाला	सीमेंट और निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद, बल्लभगढ़
5.	9वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सामग्री पुनर्चक्रण सम्मेलन	भारतीय सामग्री पुनर्चक्रण संघ, मुंबई

S. No	कार्यक्रम का नाम	आयोजक का नाम
6.	खनिज, धातु, धातु विज्ञान और सामग्री (एमएमएमएम) को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का 13वां संस्करण	भारतीय धातु संस्थान (आईआईएम), दिल्ली चैप्टर और एचवाईवीई (पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रदर्शनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-आईटीईआई), दिल्ली
7.	आजादी का अमृत महोत्सव	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हरियाणा
8.	इंडिया इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन एक्सकॉन	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली
9.	कोविड -19 टीकाकरण और प्रवासियों पर राष्ट्रीय जुड़ाव- किसी को पीछे नहीं छोड़ना	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन (आईओएम), नई दिल्ली
10.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम 2022	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
11.	मिंट इंडिया पब्लिक पॉलिसी समिट एंड अवार्ड्स	एचटी मीडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
12.	विश्व तंबाकू निषेध दिवस	पॉलिसी सर्किल, नई दिल्ली
13.	कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल एप्लिकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन	जर्मन कृषि व्यवसाय संवर्धन (जीएए), जर्मनी
14.	13वां विश्व अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कांग्रेस" और "छठा विश्व जल शिखर सम्मेलन	ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन, नई दिल्ली
15.	रीडिंग और डिजिटल रीडिंग पर राष्ट्रीय अभियान	पी.एन. पणिकर फाउंडेशन तिरुवनंतपुरम
16.	इलेक्ट्रिक वाहन इंडिया 2022 एक्सपो- एक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन शो	ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया, नोएडा, यूपी
17.	डीएक्स सिक्युर	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), गुरुग्राम
18.	"कॉपर इंडस्ट्री: विजन 2030 और 2047	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), नई दिल्ली
19.	फायर इंडिया 2022	इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स (इंडिया) और सर्विसेज इंटरनेशनल, नई दिल्ली
20.	चैंबर ऑफ कॉमर्स, सतत विकास और विदेश संबंध	चैंबर ऑफ कॉमर्स, सतत विकास और विदेश संबंध, नई दिल्ली
21.	इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022	सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए), नई दिल्ली
22.	एसटीईएम शिखर सम्मेलन में महिलाएं	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), गुरुग्राम
23.	इंडिया ईवी मार्केट कॉन्क्लेव	जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स, गुड़गांव
24.	10वां संस्करण बिग बीएफएसआई फ्यूचर टेक शो एंड अवार्ड्स	त्रेस्कोन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु
25.	एफआईसीसीआई मेटावर्स सम्मेलन 2022	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), नई दिल्ली
26.	भारत में हरित ऊर्जा पर 12वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2021- वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी	सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली

S. No	कार्यक्रम का नाम	आयोजक का नाम
27.	पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश
28.	ईटी सरकार-तीसरा डिजीटेक कॉन्क्लेव	ईटी सरकार (टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड), नई दिल्ली
29.	मेरकॉम इंडिया सोलर समिट	मेरकॉम कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु
30.	दूसरा आईएचडब्ल्यू डिजिटल स्वास्थ्य सम्मलेन एंड अवाड्र्स 2022	एकीकृत स्वास्थ्य और कल्याण परिषद, नई दिल्ली
31.	सीआईआई 8वां जल नवाचार सम्मलेन	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली
32.	18वां वैश्विक संस्करण/वर्ल्ड क्लाउड शो एंड अवाड्र्स का 18वां वैश्विक संस्थान	त्रेस्कोन ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु
33.	एफआईसीसीआई 16वां वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा सम्मेलन- एफआईसीसीआई हील 2022	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), नई दिल्ली
34.	सिमरिसर्च 2022	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (डीम्ड यूनिवर्सिटी), पुणे, महाराष्ट्र
35.	द इकोनॉमिक टाइम्स एजुकेशन लीडरशिप समिट	ईटी सरकार (टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड), नई दिल्ली
36.	छठा रेल इंडिया सम्मेलन और एक्सपो	मेसे फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
37	22वां इंडिया डिजाइन समिट	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), गुरुग्राम
38	सुलभ और सहायक प्रौद्योगिकी के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने पर 5वां सम्मेलन	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
39	आईपीआर पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली
40	डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट (डीयूएम 2022) का छठा संस्करण	इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, नई दिल्ली
41	8वां भारत स्वास्थ्य और कल्याण शिखर सम्मेलन 2022	एकीकृत स्वास्थ्य और कल्याण परिषद, नई दिल्ली
42	विश्व पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2022 (डब्ल्यूजीटीसी) और विश्व तेल रिसाव सम्मेलन 2022 (डब्ल्यूओएससी)	ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन, नई दिल्ली
43	भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन (आईडब्ल्यूआईएस)	गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र (सी गंगा), आईआईटी कानपुर
44	इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक का 9वां संस्करण (आईएसयूडब्ल्यू 2023)	इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, नई दिल्ली
45	तीसर विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस 2023 और चौथी विश्व ईंधन शिखर सम्मेलन 2023	ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन, नई दिल्ली

नीति आयोग